

Uncorrected – Not for Publication

LSS-D-I



LOK SABHA DEBATES

(Part I -- Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock.

Thursday, July 27, 2017/Shravana 5, 1939 (Saka)

LOK SABHA DEBATES**PART I – QUESTIONS AND ANSWERS**
Thursday, July 27, 2017/Shravana 5, 1939 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
...	1
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. 161 TO 164)	1A-22
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. 165 TO 180)	23-38
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. 1841 TO 1970, 1972 TO 2014, 2016 TO 2070)	39-266

For Proceedings other than Questions and Answers, please see Part II.

Uncorrected – Not for Publication

LSS-D-I



LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, July 27, 2017/ Shravana 5, 1939 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, July, 27, 2017/ Shravana 5, 1939 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	267
PAPERS LAID ON THE TABLE	268-70
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	271
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 4TH AND 5TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES -LAID Dr. Sanjeev Balyan	272
MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL 2016- EXTENSION OF TIME Shri Satyapal Singh	273
SPECIAL MENTIONS	274-304
MATTERS UNDER RULE 377—LAID	305-27
Shrimati Rakshatai Khadse	306
Shri Pankaj Chaudhary	307
Shrimati Rama Devi	308
Dr. Kirit P. Solanki	309
Shri Chhedi Paswan	310
Shri Naranbhai Kachhadiya	311
Shri Hari Manjhi	312
Shri Rameswar Teli	313
Shri Sushil Kumar Singh	314
Shri Ganesh Singh	315

Col. Sona Ram Choudhary	316
Shri Satyapal Singh	317
Shri Rajeev Satav	318
Prof. K. V. Thomas	319
Shri T. Radhakrishnan	320-21
Shri B. Senguttuvan	322-23
Shri Balabhadra Majhi	324
Kunwar Haribansh Singh	325
Shri Vijay Kumar Hansdak	326
Adv. Joice George	327
COMPANIES (AMENDMENT) BILL	328-460
(Contd. - Concluded)	
Motion for Consideration	328-30
Shri Arjun Ram Meghwal	328-30 422-28
Prof. K.V. Thomas	331-34
Dr. Kirit Somaiya	335-42
Shri S.R. Vijaya Kumar	343-48
Prof. Saugata Roy	349-55
Shri Bhartruhari Mahtab	356-65
Shri Jayadev Galla	366-72
Shri Konda Vishweshwar Reddy	373-77
Shri Md. Badaruddoza Khan	378-81
Shri Varaprasada Rao Velagapalli	382-87
Shri Subhash Chandra Baheria	388-91
Shri N.K. Premachandran	392-99
Shri Rattan Lal Kataria	400-02
Shri Rajeev Satav	403-07

Shri Prem Das Rai	408-09
Shri Ajay Mishra Teni	410-13
Kunwar Haribansh Singh	414-15
Shri E.T. Mohammad Basheer	416-18
Shri Bhairon Prasad Mishra	419-21
Motion for Consideration – Adopted	429
Consideration of Clauses	429-60
Motion to Pass – Adopted	460
...	461
INDIAN INSTITUTES OF MANAGEMENT BILL	462
(Inconclusive)	
Motion for Consideration	462
Shri Prakash Javadekar	462
(Speech not finished)	
....	463

XXXX

(a1/1100/sk-snb)

1101 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में लोकतंत्र का गला घोंटा गया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Q. No. 161

Shri S. R. Vijaykumar -- Not present.

Shri Gajanan Kirtika -- Not present.

... (*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : माननीय अध्यक्ष जी, मासूम लोगों की जान ली जा रही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। अभी कुछ नहीं होगा।

...(व्यवधान)

(प्रश्न 161)

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Madam Speaker, the hon. Minister has mentioned in his reply that modernization of major ports in the country is an on-going process to keep the ports abreast with new technologies and also to meet trade traffic requirements...

(Interruptions)

1102 hours

(At this stage, Shri Anto Antony and some other hon. Members came and stood near the Table.)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (Interruptions) ... (Not recorded)

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Now, in the State of West Bengal, the Eastern freight corridor being built by the Railways will stop in Dunkuni and we have a deep sea port at Haldia...

(Interruptions)

HON. SPEAKER: Hon. Member, again you are doing wrong things.

... (Interruptions)

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): We need greater passenger ferries and water-borne good transport to connect Dunkuni with Haldia, the deep sea port. We have to think ambitiously. We can consider a Kolkata Super Port which will include the neighbouring regions of the 24 Parganas, North and South, Howrah and Midnapore. If such a proposal comes from the Government of West Bengal, will the Minister of Shipping respond positively to regenerate that region of Eastern India?

श्री नितिन गडकरी: माननीय अध्यक्ष, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और न्यू पोर्ट डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल कंसलटेंट को एपाइंट किया था। उन्होंने 120 रिकमेंडेशन्स दी थी। इन 120 रिकमेंडेशन्स में से 85 इम्प्लीमेंट की हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि पोर्ट सेक्टर में पहले साल 3,000 करोड़ रुपए का प्राफिट हुआ, दूसरे साल 4,000 करोड़ रुपए और तीसरे साल 5,000 करोड़ रुपए का प्राफिट हुआ।... (व्यवधान) इस बार 7000 से 8000 करोड़ रुपए प्राफिट मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जो कर रहे हैं, ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी: जहां तक माननीय सदस्य ने ईस्टर्न रीजन के बारे में कहा है, पहले हम सागर पोर्ट बनाने वाले थे, अब उन्होंने ताजपुर का प्रस्ताव दिया है, उन्होंने पोर्ट की जगह बदलने के बारे में कहा है। हम जगह बदलने के बारे में कैबिनेट को प्रस्ताव दे रहे हैं। इसे क्लियर करके जरूर बंगाल सरकार की बात पर विचार करेंगे।... (व्यवधान)

जहां तक माननीय सदस्य वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कह रहे हैं, इसके लिए हम बंगाल सरकार को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर वे खुद करना चाहते हैं तो उनको अनुमति देंगे। अगर हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो हम ज्वाइंट वैंचर में एक स्पेशल व्हीकल बनाकर करने के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान)

(b1/1105/rjs-ru)

अगर वह कुछ इक्विटी लगाते हैं, तो हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान) हमारे ऑप्शन्स पूरे ओपन हैं। ... (व्यवधान) जहां भी पैसेंजर और कार्गो का ट्रांसपोर्ट बढ़ सकता है, उसके लिए हम हर प्रकार का सहयोग सब राज्यों के लिए करने को तैयार हैं।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.30
a.m.

1105 hours

*The Lok Sabha then adjourned till thirty minutes
past Eleven of the Clock.*

(c1/1130/rbn-rps)

1130 hours

The Lok Sabha re-assembled at thirty minutes past Eleven of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri S.R. Vijaya Kumar.

... (*Interruptions*)

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): The National Water Highway No. 4 includes the entire stretch of Buckingham Canal for a length of 316 kms. The stretch of North Buckingham Canal and South Buckingham Canal acted as a buffer zone and regulated the tsunami waves and saved thousands of lives along the Coromandal Coast from tsunami waves, which occurred on 26 December, 2004. ...

(*Interruptions*)

1130 hours

(At this stage, Shri Ravneet Singh and some other hon. Members came and stood near the Table.)

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): I would like to know from the hon. Minister whether the Government is keen about expediting the National Waterway Highway No. 4 covering the Buckingham Canals from Chennai to Pondicherry and if so, the steps being taken by the Government in this regard. Thank you.

श्री नितिन गडकरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, बकिंगम कैनल साउथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के लिए पैसेंजर एवं गुड्स ट्रांसपोर्ट के

लिए बहुत उपयोगी है। ...(व्यवधान) इसके दो फेज हैं। इसके फर्स्ट फेज की शुरूआत विजयवाड़ा से होने वाली है, इसका टेंडर निकल गया है और आने वाले 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी और मैं वहां आकर, भूमिपूजन करके इस कार्य का शुभारम्भ करेंगे। ...(व्यवधान) फर्स्ट फेज का काम करीब 160 किलोमीटर है और फर्स्ट फेज का काम पूरा होने के बाद सेकण्ड फेज का काम शुरू करेंगे। ...(व्यवधान) यह काम जल्दी शुरू हो जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats. This is not proper. यह कोई अच्छी बात नहीं है। चर्चा के लिए किसी ने मना नहीं किया है। आप लोगों को वापस जाना चाहिए।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग अपने किए पर माफी भी नहीं मांग रहे हैं और इस तरीके से हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यह पूरे देश को देखना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

...(व्यवधान)

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद एवं बधाई देता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चर्चा के लिए मनाही नहीं है, आप लोग चर्चा कर सकते हैं। मगर इस तरह से न तो चर्चा हो सकती है और न ही इस तरीके से कोई माफी हो सकती है।

...(व्यवधान)

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : अध्यक्ष महोदया, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए, आजादी के बाद पहली बार आंतरिक जल ट्रांसपोर्ट के लिए जिस प्रकार से प्रयास किए हैं...(व्यवधान) और बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की कोशिश की है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी को देखने दीजिए कि क्या हो रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर के बाद बोलने दूंगी।

...(व्यवधान)

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इसमें किस प्रकार से नए-नए विषय करेंगे, किस प्रकार की नावें बनेंगी, किस प्रकार की बोट और जेट्टी बनेंगी, कौन-कौन से विषय लेंगे? ...(व्यवधान) खासकर महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में जलवाहक बड़ी नदियों में यह ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ता पड़ता है। ...(व्यवधान) ऐसा बार-बार मंत्री जी ने भी कहा है। यह काम किस प्रकार से होगा और कब तक पूरा होगा, इस बारे में मंत्री जी जानकारी दें। ...(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में हमने अभी 111 नदियों को जलमार्ग के रूप में घोषित किया है। ...(व्यवधान) मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें 20,275 किलोमीटर रिवर लेंथ है। ...(व्यवधान) अगर रोड से यात्रा करने पर डेढ़ रुपये खर्च आता है, रेलवे से जाने पर एक रुपया खर्च आता है तो पानी से जाने के लिए केवल 20 पैसे खर्च आता है। ...(व्यवधान) अभी हमने दो रिवर्स में काम शुरू कर दिया है, जिनमें सबसे पहले गंगा और ब्रहमपुत्र नदी का काम शुरू हुआ है। गंगा में जो काम हमने शुरू किया है, उसमें कम से कम 5,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, उसमें श्री मल्टीमॉडल हब - वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज हैं। ...(व्यवधान) उसमें 40 रिवर पोर्ट्स हैं, सात फेरी सर्विसेज और आठ रो-रो सर्विसेज हैं। ...(व्यवधान) मुझे इस सभागृह को बताते हुए खुशी हो रही है कि करीब 2500 करोड़ रुपये के काम हमने अवार्ड कर दिए हैं और काम शुरू हो गया है।

...(व्यवधान)

ब्रह्मपुत्र रिवर पर भी सात रिवर पोर्ट्स बन रहे हैं, दो जगहों पर फेरी सर्विस चालू हो गयी है, दो जगहों पर रो-रो सर्विस चालू हो गयी है और वहां भी काम शुरू हुआ है। ... (व्यवधान) मैं सभागृह को बताना चाहता हूँ कि आने वाले 15 दिनों के अंदर, पार्लियामेंट के इसी सेशन से पहले, हम आठ नदियों के जलमार्ग पर काम शुरू करने का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से करने वाले हैं। ... (व्यवधान) इस तरह से देश में दस जलमार्गों पर काम शुरू हो जाएगा और वर्ष 2018 से पहले इन जलमार्गों को हम पूरा करेंगे। ... (व्यवधान)

(d1/1135/asa/rp)

एक अच्छी बात और यह हुई है कि पेट्रोल और डीजल पर जो सैस लगता था, वह रोड और रेलवे के लिए मिलता था। अब हमने कैबिनेट में निर्णय किया है और आपके सामने बिल आया है। उसमें से 2000 करोड़ रुपये साल के जल मार्ग के लिए मिलेंगे और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से यह काम होगा। एक अच्छी बात यह है कि इन 8 नदियों के अलावा करीब 16 डीपीआर बनने के लिए तैयार हुए हैं और उसमें से काफी काम अभी हम लोग ले रहे हैं। उसमें से बराकूँवर असम में हैं। वर्क अवार्ड कर दिया है। ब्रेजिंग को प्रपोज कर दिया है। 76 करोड़ का काम असम में शुरू हुआ है। वॉटरवेज इन गोवा - उसमें चम्बूरिया, मांडवी, झुआरी तीनों का काम हो गया है। उसका टेंडर निकल गया है। काम शुरू हो रहा है। अलगपूजा, कोट्टायम, अथिरपुजा, केनाल, के.एम.डबल्यू. लाइन-केरल, इसमें हमने काम एप्रूव किया है। वर्क प्रपोज किया है और तुरंत मानसून के बाद काम शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की गंडक रिवर, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बिहार और यूपी. से जाती है, इसके ऊपर भी हमने डी.पी.आर. मंजूर किया है। टेंडर निकला हुआ है। आने वाले दो महीनों में इसका काम शुरू हो जाएगा। रिवर रूपनारायण, वैस्ट बंगाल की है। इसका काम भी मंजूर हुआ है। मानसून के बाद काम शुरू हो जाएगा।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब अगला पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो करीब 10 जलमार्ग का काम शुरू होगा। मैं स्पीकर साहिबा जी से अनुरोध करूँगा कि चूंकि यह विषय लोगों के लिए नया है कि जलमार्ग कैसा होगा तो अगर आप अनुमति देंगी

तो इसके ऊपर एक विशेष चर्चा करवाएंगे। इससे पूरे देश के लोगों को यह जानकारी मिलेगी और यह देश का भविष्य होगा, गेम चेंजर होगा। देश की प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा।

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर यदि आप चर्चा की डिमांड करेंगे तो जरूर हम एलाऊ करेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वह सबके ध्यान में आना चाहिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, Prof. Sugata Bose.

... (*Interruptions*)

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Madam, I have already asked my Supplementary Question. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. I forgot it.

Shri Kalikesh N. Singh Deo ji.

... (*Interruptions*)

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Thank you, Madam. The hon. Minister himself said that the cost of transporting goods through inland waterways is less than 20 per cent versus railways and roads. However, in contrary to the contribution of the ports in inland waterways to the GDP, which stands at one per cent, Railways contributes 9 per cent and roadways contributes 6 per cent to the GDP. It means, there is a lot of potential to develop this entire inland waterways and port sector.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Ports of Paradip and Mahanadi inland waterways system which he has already committed to. I would like to know from the hon. Minister as to what are the plans to develop the Mahanadi inland waterways. How

much money is he going to spend on both the Paradip Port and Mahanadi waterways and by when would this be done?

श्री नितिन गडकरी : माननीय अध्यक्ष जी, तालचर से पारादीप रेलवे लाइन 1000 करोड़ रुपये की लागत की पोर्ट की ओर से हम बना रहे हैं। जो ब्राहमणी नदी है, जो विशेष रूप से राऊरकेला तक तालचर से पारादीप आगे जाती है, उसके काम को हमने मंजूरी दी है। उसका भी डी.पी.आर. तैयार किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कोल इंडिया का कोल प्रोडक्शन तालचर के क्षेत्र में 60 मिलियन टन है। हमारे कोल मंत्री का यह प्रयास है कि वह 300 मिलियन टन तक जाए। इसलिए यह कोल जब होगा तो इसे रोड से भेजना संभव नहीं है। इसलिए इस कोल को हम पारादीप लेकर आएंगे और पारादीप के पोर्ट में ब्रेजिंग करके 18 मीटर तक इसको हम लेकर जाएंगे और उससे यह पूरा कोल महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर आएगा।

राजस्थान का जो लाइम है, वह ओडिशा में है, वह वापस आएगा। इससे महाराष्ट्र और गुजरात में बिजली की कीमत रास्ते कम करने से 50 पैसा प्रति यूनिट कम होगी। इन सब कामों के डी.पी.आर. तैयार हुए हैं। अभी तीन दिन पहले मैं उड़ीसा गया था। मेरी अगले विजिट में भूमि पूजन का कार्यक्रम करके काम का शुभारम्भ होगा और यह पारादीप पोर्ट विश्व का एक ऐसा पोर्ट बनेगा जो ओडिशा को ही नहीं, पूरे भारत का एक ग्रोथ पोर्ट होगा जहां आने वाले समय में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, हमारा, कोल तथा यूरिया के अनेक प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं, उससे एक लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेन्द्र प्रधान जी और मैं, हम दोनों ने बैठकर सागरमाला में पोर्ट के डवलपमेंट का पारादीप का प्लान तैयार किया है। इसी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2018 पूरा होने से पहले करीब एक लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम पारादीप पोर्ट में करेंगे और दुनिया का सबसे अच्छा पोर्ट इसको बनाएंगे। आपने जो बात कही है, वह बिल्कुल सही है और इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे।

(इति)

(e1/1140/asa/rcp)

(प्रश्न 162)

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी और अपने मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की कि जिस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, जिस तरीके से धरती मां के स्वास्थ्य के लिए हमने सॉयल हेल्थ कार्ड बनाया, उसी तरीके से पहली बार केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत बनी भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली यानी कि आईबीएमएस नामक परियोजना शुरू की गई थी जो भारत के पुलों और सुरंगों की जांच करेगी जिसके लिए पहला सर्वेक्षण 'पुलों का स्वास्थ्य' अभी पिछले ही वर्ष शुरू किया गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि क्या सरकार ने भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली को लागू करने से पूर्व किसी विदेशी पुल प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन किया है? यदि हां तो इस बारे में सदन को बताने की कृपा करें।

श्री नितिन गडकरी : माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के बाद पहली बार इस बात का पता चला कि इस देश में कितने पुल हैं। हमारे देश में 1,63,202 पुल हैं। इसमें से 1,27,288 कार्यरत हैं। 35914 पुल जो हैं और मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि 50 पुल ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं और महाराष्ट्र में सावित्री नदी पर एक हादसा हुआ और उसमें 100 लोग मर गये क्योंकि वह पुल पुराना हो गया था। मुझे इस सभा में बताते हुए खुशी हो रही है कि हादसा होने के बाद सरकार ने उस पुल को 165 दिनों में बनाकर तैयार कर दिया। अभी हमने इन पुलों के बारे में आईबीएमएस की स्थापना की है। इसका डेटा इकट्ठा हुआ है और पुल के अध्ययन करने में जानकारी मिली है कि 23 पुल ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। हम इनको सुधारने को प्रायोरिटी दे रहे हैं। 1628 पुल ऐसे हैं जो 50 साल पुराने हैं और विशेष रूप से 147 पुल ऐसे हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है। इनको हमने डिजिटलाइज किया है। अब किसी भी पुल की जानकारी आपको उससे मिल सकती है। पूरी तरह से हमने इसको कम्प्यूटरीकृत किया है। इन पुलों को सुधारने के लिए विश्व में जो बैस्ट

प्रैक्टिसेस ऑफ टैक्नोलॉजी है, उसका उपयोग करके हम काम कर रहे हैं। इसमें 600 इंजीनियर अभी काम कर रहे हैं। इसमें नैनो, लेजर और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंजीनियर टीम फील्ड में जा रही है। आई.आई.टी. को रिसर्च करने के लिए कहा गया है। पुराने पुलों को कम पैसों में कैसा बनाया जाए, उसके लिए वर्ल्ड की बैस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टैक्नोलॉजी को हम ला रहे हैं और पूरी तरह से इस योजना को हम गंभीरता से ले रहे हैं। 100 लोगों की तो जान चली गई लेकिन अब कोई जान नहीं जाएगी। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि इसके बाद यदि कोई पुल गिर गया और किसी की जान गई तो 302 की दफा आपके ऊपर लगाएंगे और आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि न्यू जनरेशन बाइक लेकर चलती है और हमेशा उनके कान में लीड रहती है। मोबाइल फोन तो जेब में रहता है लेकिन कान में लीड हमेशा लगाकर रखते हैं। उससे आए-दिन दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। गाड़ी में भी हम देखते हैं कि लोग मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं जिससे हम यह बात भी कहते हैं कि 'नजर हटी, दुर्घटना घटी'। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जिम्मेदारी पूर्वक मोबाइल फोन का उपयोग करने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित भारत नामक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? यदि हां तो सदन को बताने की कृपा करें।

श्री नितिन गडकरी : माननीय अध्यक्ष जी, यह गंभीर बात है और एक विषय ऐसा है जो मेरे मंत्रालय को एम्बैरेंसिंग करने वाला है। हमारी सरकार आने के बाद 4 प्रतिशत एक्सीडेंट बढ़े हैं और हमारी ऑटोमोबाइल ग्रोथ 22 प्रतिशत है। देश में 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं और डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु होती है। आज एक अंग्रेजी अखबार में ट्रक के कारण लोग कैसे मरे हैं, यह हाल है। मैडम, आपको और सभा के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूर किया है। इसके कारण यह कानून और कड़ा होगा। राज्य सभा में आज भी मेरी मीटिंग है। देश में 3 लाख लोग मर रहे हैं। देश में 30 प्रतिशत लाइसेंस बोगस हैं। देश में

लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको सजा नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में इसको लाने के लिए जल्दी मुझे सहयोग करें। साथ ही जो मोबाइल फोन के बारे में बातें कही गई हैं, इसके लिए हमने एक अभियान शुरू किया है। मैंने खुद एक प्राइवेट कंपनी के साथ कैम्पेन किया है। लोगों के फोन पर जा रहा है कि आप ड्राइविंग करते समय मोबाइल मत चलाओ।

(f1/1145/raj-smn)

मैडम, यह बहुत गंभीर विषय है।...(व्यवधान) इसमें सभी का सहयोग चाहिए और लोगों की जान बचानी चाहिए।...(व्यवधान) हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हम कम से कम 50 प्रतिशत लोगों की जान बचाने की कोशिश करेंगे। ...(व्यवधान)

SHRI B. SRIRAMULU (BELLARY): Madam Speaker, I would like to know from the Minister whether the Government has launched any Indian Bridges Management System (IBMS) and created database inventory for all bridges and culverts in the country as part of the administrative steps. And if so, the details thereof.

Has the Government completed safety audit of 1.6 lakh bridges in the country under IBMS and found 147 structures in deplorable condition? If so, the details thereof and the reactions of the Government along with the list of such bridges structurally, both State-wise and UT-wise.

श्री नितिन गडकरी : मैडम, मुझे बताते हुए दुःख हो रहा है कि 70 साल राज हुआ, अनेक साल इनको राज करने का मौका मिला। ...(व्यवधान) मेरे डिपार्टमेंट को यह पता नहीं था कि देश में कितने ब्रिजेज हैं। ...(व्यवधान) मुझे ब्रिजेज की संख्या मालूम करने में एक साल लगा।...(व्यवधान) पहली बार ब्रिजेज का इंस्टीट्यूट तैयार हुआ है, मैं यह नेशनल हाईवेज की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट हाईवेज की बात नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान) अब पहली बार पता

चला कि कितने ब्रिजेज हैं।...(व्यवधान) उसमें से एक ब्रिज बह गया, 100 लोग मर गये और 100 ब्रिजेज की हालत खराब है।...(व्यवधान) पहली बार सरकार ने उसको प्रायरिटी दी है, नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम इसके बारे में कॉशस हैं।...(व्यवधान) पर, मुझे यह स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं है कि 50-70 सालों में कोई ध्यान नहीं दिया गया। ... (व्यवधान) पहली बार हमने काम शुरू किया है, हमारा काम प्राथमिक स्टेज पर है, ... (व्यवधान) पर, संवेदनशील होने के कारण हमारी सरकार इसके ऊपर पूरा ध्यान देगी।...(व्यवधान) अब इसके बाद कोई ब्रिज कोलैप्स नहीं होगा।...(व्यवधान) ब्रिज रिपेयर होगा, साइंटिफिक और टेक्निकल एप्रोच से सभी प्रकार का उपयोग करके हम आगे जायेंगे।...(व्यवधान)

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Hon. Speaker Madam, through you, I would like to ask the Minister the number of bridges identified under the Bridges Management System in Tamil Nadu. The bridges are the basic need for connecting people with the mainstream. Will the Government take any step to create a separate Department for construction of bridges all over the country?

श्री नितिन गडकरी : मैडम, कोई सेपरेट डिपार्टमेंट खोलने की आवश्यकता नहीं है।...(व्यवधान) मुझे आकड़ा मिला है कि देश के नेशनल हाईवेज पर 1,63,202 पुल हैं। इनमें से 1,27,288 क्लवर्ट हैं और 35,914 पुल हैं, ... (व्यवधान) पूरे देश में अलग-अलग नेशनल हाईवेज पर जो पुल हैं, यह उनका आंकड़ा है। मेरे पास अलग से तमिलनाडु का डाटा उपलब्ध नहीं है, ... (व्यवधान) अगर सम्मानीय सदस्य को वह चाहिए तो हम अपने ऑफिस से उसे उपलब्ध करा कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, आप शॉर्ट प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों का काया-कल्प करने का काम किया है। ... (व्यवधान) राष्ट्रीय जल मार्ग में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। ... (व्यवधान) हमारे यहां झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग है। ... (व्यवधान) जहां पर बदौसा के पास बांदा जनपद में पुल बहुत खराब हालत में है। ... (व्यवधान) उसको कई बार रिपेयर करवाया गया, काफी दुर्घटनायें हुयी हैं, वहां पर गाड़ियां भी झुक जाती हैं। ... (व्यवधान) आप सभी ने आश्वासन दिया है कि उसे जल्दी करा रहे हैं, लेकिन उसको कराना अति आवश्यक है। ... (व्यवधान) मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या उसका काम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, जिससे वहां पर दुर्घटना न हो। ... (व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन जब हमारे सम्मानीय एमपी साहब कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह सिरियस मैटर है। ... (व्यवधान) मैं इमिडिएट डिपार्टमेंट को इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने का आदेश दूंगा और यह काम कर दूंगा। ... (व्यवधान)

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री का अभिनंदन करता हूँ कि सावित्री नदी पर बना पुल गिरने के बाद 165 दिनों में पुल का निर्माण किया गया है। ... (व्यवधान) उस दुर्घटना के बाद डिसिजन लिया गया कि देश के सभी ब्रिजेज का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। इसके लिए इंडियन ब्रिजेज मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लिमेंट किया गया। ... (व्यवधान) मेरा जो साउथ सेंट्रल मुंबई, लोक सभा क्षेत्र है, उसमें 13 ब्रिजेज हैं। ... (व्यवधान)

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ नेशनल हाईवेज के लिए है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास जो ब्रिजेज हैं, उनकी भी स्ट्रक्चरल ऑडिट करने की जरूरत है क्योंकि साउथ सेंट्रल मुंबई में दादर में जो तिलक ब्रिज है, वह वर्ष 1923 में बनाया गया है। ... (व्यवधान)

उसके ऊपर से रोज 10 हजार व्हीकल्स गुजरते हैं। ... (व्यवधान) यह ब्रिज दादर ईस्ट और वैस्ट को जोड़ता है। इस ब्रिज का पुनर्निर्माण करने की भी जरूरत है।

(g1/1150/ind-mmn)

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार और म्युनिसिपल कार्पोरेशन के अंदर जो सौ साल पुराने ब्रिजेज हैं, क्या उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट इंडियन ब्रिजेज मैनेजमेंट सिस्टम से किया जाएगा?

श्री नितिन गडकरी : महोदया, म्युनिसिपल कार्पोरेशन और राज्य सरकार के ब्रिजेज हमारे मैनेजमेंट में नहीं आते हैं, लेकिन लोगों की जान बचाने और इस कार्य का महत्व देखते हुए राज्य सरकार और म्युनिसिपल कार्पोरेशन अगर हमसे सहयोग मांगती है, तो ब्रिजेज की मजबूती के लिए, उन्हें नए बनाने के लिए और नई टेक्नोलॉजी के लिए निशुल्क पूरा सहयोग म्युनिसिपल कार्पोरेशन और राज्य सरकार को देंगे।

(इति)

(प्रश्न 163)

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा (कच्छ) : महोदया, मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं स्वयं का अनुभव बताते हुए आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े-बड़े मालवाहक वाहन, बड़े-बड़े टैम्पो इत्यादि भी चलते हैं और उनके साथ छोटे-छोटे वाहन जैसे एम्बुलेंस, कारें, अन्य मुसाफिर वाहन आदि भी चलते हैं। बहुत बार भारी वाहनों की वजह से टोल नाके पर सामान्य वाहनों को लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस समस्या के निदान हेतु आने वाले दिनों में मंत्री जी क्या करने वाले हैं? मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारी गुजरात सरकार ने जितने भी छोटे वाहन हैं जैसे कार आदि, इनके लिए टोल फ्री व्यवस्था की है। क्या इस तरह की व्यवस्था करने की भी मंत्री जी सोच रखते हैं?

श्री नितिन गडकरी : महोदया, हमने फास्ट ट्रैक सिस्टम शुरू किया है। जैसे मोबाइल फोन चार्ज होता है, ऐसे ही इसमें एक स्टीकर लगा हुआ है और आप टोल नाके पर जाते हैं, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। यह सिस्टम आने के बाद नई टेक्नोलॉजी भी आई है और हमने जो टेक्नोलॉजी अपनाई है, वह भी आउटडेटेड हो गई है। इसलिए एनएचएआई के चेयरमैन के साथ दो-चार दिन पहले मीटिंग हुई है। मैंने उन्हें कहा कि आप वर्ल्ड की सबसे बैस्ट टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, जिसमें टोल नाके ही नहीं रहेंगे। इस टेक्नोलॉजी में उस नाके की एंट्री पर लोहे के डंडे पर कैमरे लगे रहेंगे और उसमें फोटोग्राफ निकलेगा। आपके बैंक एकाउंट से पैसे माइनस होंगे और आपको कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ल्ड की बैस्ट टेक्नोलॉजी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे रिलीफ मिलेगा। जहां तक टोल माफी की बात कही है, यह आज के समय में संभव नहीं है। यदि ऐसा एक जगह करेंगे, तो दूसरी जगहों पर भी करना पड़ेगा और ऐसा अभी मुमकिन नहीं है।

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा (कच्छ) : मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि टोल नाके के पास जितने गांव हैं, वहां के लोगों को दिन में कई बार आना-जाना पड़ता है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि खास कर इनके लिए सर्विस लेन की व्यवस्था या टोल फ्री करने की व्यवस्था करने की मंत्रालय की कोई योजना है या नहीं?

श्री नितिन गडकरी : महोदया, सम्मानीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के सामने रखा है। अभी तक फाइनेंशियल लॉस होने के कारण इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और कैबिनेट से अप्रूवल लेने की जरूरत होती है। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ कि यदि गांव के लोग आस-पास जाते हैं, तो उन्हें इतना टोल देना जस्टीफाई नहीं है। इसके लिए हमने प्रपोजल तैयार किया है और वह प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री और कैबिनेट अप्रूव करेंगे, तभी मैं ऐसा कर पाऊंगा, अदरवाइज इसमें अड़चन है।

महोदया, टोल के आस-पास बीस किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उसके लिए मंथली पास देने की पालिसी हम ला रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे कुछ रिलीफ मिलेगा। मैं अपनी तरफ से इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मर्यादा है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल के बिना ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं है।

(h1/1155/vb-vr)

माननीय अध्यक्ष : श्री देवसिंह चौहान - उपस्थित नहीं।

श्री रत्न लाल कटारिया।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आदरणीय मंत्री जी ने मेरे लोक सभा क्षेत्र- अम्बाला का एक साल में दो बार दौरा किया और फोर लेन सड़कों का जाल बिछाया, उसके लिए तो मैं इनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली से यमुनानगर तक एक्सप्रेस वे बनाने का विचार मंत्रालय के अधीन चल रहा है? क्या आपने अपने विज़िट के दौरान आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से भी इस विषय में बात की है कि यदि वे लैंड प्रोवाइड कराएँ, तो इसके ऊपर विचार हो सकता है?

श्री नितिन गडकरी : महोदया, यमुना के तट से दिल्ली से यमुनानगर तक एक्सप्रेस हाइवे बनाने का सुझाव हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे दिया है। उसमें कल्पना यह है कि यमुना में जब हम ड्रिलिंग करेंगे, तो जो सैंड निकलेगा, एक तरफ उसका इम्बैकमेंट करेंगे, उसके बाद एक्सप्रेस हाइवे बनाएंगे, उसके लिए सौ मीटर की विड्थ रखेंगे। इस प्रस्ताव के लिए अभी हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर एनएचएआइ की ओर से हम इस प्रस्ताव की पहले स्टडी करवाएंगे और उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी की स्टडी कराएंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। स्टडी करने के लिए मैंने आदेश दे दिया है। जल्दी ही उसका रिपोर्ट मिलेगा, उसके बाद हम अंतिम निर्णय करेंगे।

(इति)

(प्रश्न 164)

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न प्रधानमंत्री जी की इज़रायल यात्रा के संबंध में था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने रिवर्स ऑसमोसिस के बारे में जवाब दिया है।

According to the Ministry of Water Resources, since India is going to become water deficient in near future, the reverse osmosis process waste three liters of water for one liter of potable water. Is the Ministry considering the recommendations of Dr. R.A. Mashelkar Committee to implement the sustainable alternative technology?

Since Karnataka is a severely drought affected State where water table has gone down, has the Ministry got any request from the State Government to mitigate wastage of water by requisiting new technology for recycling and providing clean drinking water to all?

श्री रमेश जिगाजिनागि : अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी यूज़ करने का सब्जेक्ट स्टेट का है। माशेलकर कमेटी ने जो टेक्नोलॉजी के बारे में रिपोर्ट दी है, उसे हमने सभी राज्यों को दे दिया है। जो टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसे राज्य सरकारें यूज़ करती हैं।

माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न है- क्या कर्नाटक से इस संबंध में कोई प्रपोजल आया है। मैं बताना चाहूँगा कि कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रपोजल नहीं भेजा है।

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Madam, in line with the hon. Prime Minister's vision to make India driven by clean fuel, has the Ministry taken any initiative to combine desalination plants with solar energy to provide sustainable and cheap drinking water to all through solar desalination plants?

Madam, the Government of Karnataka has stated that it is installing desalination plants in rural and remote areas of the State. कर्नाटक सरकार ने बहुत दावा किया है, लेकिन वास्तव में वहाँ बहुत कम हुआ है। इसके अलावा वे बंद पड़े हुए हैं। One of the reasons for closing down of these desalination plants is unavailability of electricity. My specific question is, whether the desalination plants will be linked with solar electrification.

श्री रमेश जिगाजिनागि : अध्यक्ष जी, कर्नाटक में टोटल नौ हजार आर.ओ. प्लांट लगे हुए हैं। उनमें बहुत कम, लगभग पाँच पर्सेंट वर्क नहीं करते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन और मेनटेनेंस लोकल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ करती हैं। Technology selection is done by the State Government. But, Madam Speaker, solar desalination can also be taken up.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Hon. Minister in his reply has said 'desalination'. Desalination is different from RO plants. They are not connected. So, I will just ask him to clarify this. ... *(Interruptions)*

I would also like to ask whether he will make it cost effective because normal water is for 10 paise. In this new research of 30 technologies, will it become cheaper because we come from a country which is water deficit? ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: So, you do not have any question on that.

... *(Interruptions)*

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, I would like to know whether the cost can be reduced. ... *(Interruptions)*

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्री तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): अध्यक्ष महोदया, लवणीकरण के मामले में सरकार पूरी तरह चौकन्नी है। हम लोग लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि जल की शुद्धता के लिए जो भी नई टेक्नोलॉजी आए, उसे हम मशेलकर कमेटी में भेजें। मशेलकर कमेटी उसका परीक्षण करती है और राज्यों को एडवाइस देती है। राज्य जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं, उसे वे यूज़ करते हैं। इस दिशा में काम चल रहा है। ... (व्यवधान)

QUESTION HOUR OVER

(j1/1200/san-pc)

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION

1201 hours

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from some Members on different issues. The matters, though important, do not warrant interruption of Business of the Day. The matters can be raised through other opportunities. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

... (*Interruptions*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

1201 hour

HON. SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

Shri Piyush Goyal.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI PIYUSH GOYAL): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (1) Memorandum of Understanding between the Rural Electrification Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2017-2018.
 - (2) Memorandum of Understanding between the NTPC Limited and the Ministry of Power for the year 2017-2018.
 - (3) Memorandum of Understanding between the Hindustan Copper Limited and the Ministry of Mines for the year 2017-2018.
 - (4) Memorandum of Understanding between the National Aluminium Company Limited and the Ministry of Mines for the year 2017-2018.
- (2) A copy of the Notification No. S.O.997(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 30th March, 2017,

regarding modification in the Schedule III, mentioned therein, of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 under sub-section (3) of Section 31 of the said Act.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

- (i) Notification No. L-1/18/2010-CERC published in Gazette of India dated 8th May, 2017, containing corrigendum to the Notification No. L-1/18/2010-CERC dated 12th April, 2017.
- (ii) The Central Electricity Regulatory Commission (Communication System for inter-State transmission of electricity) Regulations, 2017 published in Notification No. L-1/210/2016-CERC in Gazette of India dated 29th May, 2017.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Aircraft (Fifth Amendment) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1156(E) in Gazette of India dated 20th December, 2016 under Section 14A of the Aircraft Act, 1934, together with an explanatory note.

... (*Interruptions*)

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के केन्द्रीय रेशम बोर्ड (प्रशासनिक, लेखा और सामान्य संवर्ग पद) भर्ती नियम, 2015, जो 11 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 963 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

... (Interruptions)

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

1202 hours

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

- (i) “In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 26th July, 2017 agreed without any amendment to the Collection of Statistics (Amendment) Bill, 2017, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 11th April, 2017.”

... (*Interruptions*)

**STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 4TH AND 5TH REPORTS OF
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES - LAID**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (DR. SANJEEV BALYAN): Madam, I beg to lay the following statements regarding -

- (1) the status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Water Resources on the 'Issues concerning flood management, compensation and status of ownership of submerged and eroded land in the country including compensation to farmers for loss of their crops destroyed by floods and right to disposal of the sand left in the fields of farmers', pertaining to the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.
- (2) the status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Water Resources regarding 'Review of ground water scenario, need for a comprehensive policy and measures to address problems in the country with particular reference to (a) Dark Blocks and (b) Contamination of underground water by certain industries, pertaining to the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

... (*Interruptions*)

*** MOTION RE: REPORT OF
JOINT COMMITTEE ON CITIZENSHIP
(AMENDMENT) BILL, 2016 – EXTENSION OF TIME**

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि यह सभा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय संसद के शीतकालीन सत्र (2017) के अंतिम सप्ताह के पहले दिवस तक बढ़ाती है।”

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on The Citizenship (Amendment) Bill, 2016 upto the First day of the last week of the Winter Session (2017) of Parliament."

The motion was adopted.

... (Interruptions)

* Memorandum giving reasons for extension of time circulated separately.

SPECIAL MENTIONS

1203 hours

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ये मैडम-मैडम चिल्लाने से कुछ नहीं होता है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: You will have to go to your seats. Then only I can allow. I am sorry. This is not the way.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is it?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam, I wish to ask a question. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No. The Question Hour is over. Why are you asking a question?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No. What is this?

... (*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : मैडम, खड़गे साहब बोलेंगे ... (व्यवधान)

1204 hours

(At this stage, Shri Ravneet Singh and some other hon. Members went back to their seats.)

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप शांति से अपनी जगह पर सही से बैठिए।

मोहम्मद सलीम जी, पहले बैठो तो सही।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ बैठो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं पहले अपनी सूची कम्पलीट करूँगी, फिर थोड़ा समय सब को दे दूँगी।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, हमने आपको मॉब लिविंग कि विषय में नोटिस 5 जून को ही दे दिया था, कि इसे नियम 193 में लिया जाना चाहिए। उसके बाद जब वह नियम 193 में नहीं आया, तो हमने यह कोशिश की कि एडजर्नमेन्ट मोशन में रूल्स 56 और 57 के तहत इसे इस सदन में लिया जाना चाहिए। इस पर आप रेडी है, लेकिन सरकार रेडी नहीं है। यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

माननीय अध्यक्ष : सरकार भी रेडी है, कोई मना नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : हमें आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हम जब आपसे मिले तब आपने कहा कि आपकी तरफ से इसमें कोई बाधा नहीं है, हम सिर्फ सरकार को समझाएं। अगर सरकार को समझ में आएगा, तो हम उसे समझाएंगे। हम सोए हुए लोगों को जगा नहीं सकते हैं।

(k1/1205/mz-ak)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी मेरे शब्द ऐसे मत बनाकर बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने कहा था कि तुरंत कराइए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : ये मेरे शब्द उनके लिए हैं। सोये हुए लोगों को।

माननीय अध्यक्ष : आपने मेरे शब्द बोले कि मेरे शब्द हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आपके शब्द ये कि 'मैं डिसकसन के लिए तैयार हूँ, सरकार को आप'।

माननीय अध्यक्ष : कब लगाना? सरकार भी तैयार है। कब लगाना है, यह आप तय करें।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : सरकार नहीं मान रही है। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मैंने केवल सरकार नहीं कहा, मैंने कहा कि सबको, और इसके लिए आज बी.ए.सी. मीटिंग भी रखी है। मैंने कहा सब लोग चर्चा के लिए जब तैयार हों, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : इसीलिए हम विनती करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : मेरे शब्दों का हेर-फेर मत कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, आपके शब्दों को गोल-मोल करके कहा जाऊंगा। मुझे तो यहीं रहना है। मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि मॉब लिचिंग का विषय एक बड़ा मुद्दा है। राज्य सभा में इस पर चर्चा हो गई है। हर पेपर में एडिटोरियल से लेकर डिबेट तक हो गया है।

माननीय अध्यक्ष : चर्चा कर लेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आप इजाजत दीजिए। आज इसको शुरू करना चाहिए। हम सस्पेंशन के बारे में, मेंबर्स के रिवोकेशन के बारे में कुछ नहीं पूछने वाले हैं। आपने जो निर्णय लिया है, वह लिया है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आपको माफी भी नहीं मांगनी है। ठीक है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : हम उस बात को छोड़ देंगे।

माननीय अध्यक्ष : इसमें आप छोड़ क्या देंगे?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : यह मुद्दा महत्व का है। यह जनता का मुद्दा है।

माननीय अध्यक्ष : इसमें छोड़ना क्या होता है, वह हो गया है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मासूम लोगों को यहां पर मारा गया है। उनके लिए हम लड़ने के लिए तैयार थे। जिस वजह से वे सस्पेंड हुए हैं। हम रिवोकेशन के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष : इसमें पूछना क्या होता है। किसी ने न कोई माफी मांगी, न अपनी गलती स्वीकार की।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : कृपया करके आप हमको चर्चा शुरू करने के लिए सहमति दीजिए।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I think that as regards mob-lynching issue, the Government has also agreed to take part in this debate and discussion. I also agree that today at 1 pm the Business Advisory Committee (BAC) meeting has been called. It would be better that in the quickest possible time the House can run smoothly and the discussion can take place very soon.

HON. SPEAKER: Yes, as regards that I have no objection.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): So, I will approach to the Government also that in response to the appeal from the Opposition let this discussion start immediately, and if possible, it can start today itself also.

HON. SPEAKER: Sure!

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): We can discuss about it in the BAC meeting at 1 pm. Mob-lynching issue is the

most important issue. Trinamool Congress has given their notice also, and we want to take part in the debate all out.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैडम, कितनी संजीदगी से बात हो रही है। हम पिछले दो सप्ताह से एडजर्नमेंट मोशन दे रहे हैं। 50 लोगों की मॉब लिंगिंग हुई है और लोग एक दहशत के माहौल में जी रहे हैं। यदि हम सदन में चर्चा नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। आपने बी.ए.सी. की बैठक बुलाई है। हम उसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे। लेकिन 17 तारीख से, दो सप्ताह से हम कह रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हम चर्चा नहीं कर सकते, आखिर हमारे कॉन्स्टीट्यूट्स हैं। इस जगह पर उलटा टम्प्रेचर बढ़ाया गया। इधर से कुछ बोलेते हैं, उधर से कुछ बोलते हैं। मंत्री जी को पहले दिन ही उठकर बोलना चाहिए था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, किंतु मोशन कौन सा होगा।... (व्यवधान) लेकिन दो सप्ताह से हम एडजर्नमेंट मोशन दे रहे हैं आप उसे नकार रही हैं। क्या हम एडजर्नमेंट मोशन रूल बुक से निकाल देंगे। आखिर इस इश्यू पर चर्चा नहीं होगी, जहां लोगों की जान खतरे में है। एक 16 साल का बच्चा मार दिया जा रहा है और लोग मारे जा रहे हैं।... (व्यवधान) वहां पर कोई सुनवाई नहीं होगी। ... (व्यवधान) तो हम यहां पर क्या करने आए हैं। क्या तमाशा करने आए हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, चिल्लाइए मत।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : हमने दो सप्ताह से इंतजार किया है। ... (व्यवधान) हमने दो सप्ताह से इंतजार किया है।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : आप ... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया) करेंगे, क्या चाह रहे हैं? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप सब बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए। पहली बात तो यह है कि, No, you cannot challenge my ruling, and you cannot challenge the Speaker.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: How are you saying something like this?

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ आप लोग बैठ जाइए। मैं बोलने के लिए मौका दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम जी, आप भी एक बात समझिए कि मैंने एडजर्नमेंट मोशन हर बार नकारते समय चर्चा के लिए मना नहीं किया था। मोहम्मद सलीम जी, आप सीनियर हैं, समझदार है। अपनी लैंग्वेज को तैश में नहीं लाइए। मैंने एडजर्नमेंट मोशन नकारते समय, हर समय कहा था कि चर्चा के लिए मना नहीं है।

(11/1210/bks-spr)

आप नियम 193 में चर्चा मांगिये और जैसा सबसे पहले सप्ताह में सबका आग्रह था कि पहले किसानों पर चर्चा हो तो उस पर तुरंत एग्री किया गया था। क्योंकि उस पर आप बार-बार बोल रहे थे तो चर्चा के लिए मना नहीं है और यह भी तय हुआ कि सेशन में आप चर्चा दिया करो। मैंने कहा चर्चा दे देंगे, चर्चा नहीं देने की बात नहीं थी और इस पर भी मैंने कहा कि चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के लिए मैंने कभी मना नहीं किया। एडजर्नमेंट मोशन नहीं होना चाहिए, यह भी नहीं बोला है। ऐसा बोला नहीं है कि यह नहीं होना चाहिए। मैंने सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑवर के लिए कहा कि रहने दो। आप थोड़ी बात समझो। उसके बाद यह हो रहा है और आज मैंने इसीलिए कहा, जब कल बात आई थी कि आप इसे तुरंत लगाइये, मैंने कहा कि जिस तरीके का माहौल है, आप सब लोगों के साथ तय करो कि कब करना है। सरकार ने भी कहा था और मुझे लगता है कि आज भी वह कहेंगे, इसकी मना

नहीं है, आज रखा है। मगर आप तैश में आकर इस तरीके से मत बोलो।... (व्यवधान) इसके लिए मना नहीं है। श्री अनंत कुमार जी, आप बोलिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिये, अब क्या आप भी कुछ अलग बोलेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा चलता है, यू डोंट वरी, वह मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष जी, जैसा माननीय खड़गे साहब ने कहा, पहले दिन से हर तरीके की चर्चा के लिए सरकार तैयार है। पिछली बार जब हम बैठे थे, सबका आग्रह था, सभी पार्टियों के सभी नेताओं का आग्रह था कि हम पहले कृषि संकट के बारे में, खेती के बारे में, किसानों के सामने जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप सबकी सहमति से देर रात साढ़े दस बजे तक सारे सदन ने इसमें भाग लिया। बाद में एट्रोसिटीज के बारे में, किलिंग्स के बारे में, लिंगिंग के बारे में और जो पोलिटीकल किलिंग्स हो रही हैं, उन सारे विषयों के बारे में कई मैम्बर्स ने नियम 193 के अंदर नोटिसेज दिये हुए हैं। उसके बारे में भी मैंने बार-बार यहां खड़े होकर पूरे सदन को बताया और आपको भी निवेदन किया कि इसके बारे में भी हम पूरी चर्चा और बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे एक घटना हुई, पेपर बॉल्स बनाकर आपके ऊपर फेंका गया, यह अनपार्लियामेन्ट्री है... (व्यवधान) मुझे क्षमा करो, यह अनपार्लियामेन्ट्री है। ... (व्यवधान) मैं अभी भी आपके द्वारा... (व्यवधान) पूरा सदन यानी बंदोपाध्याय जी, भर्तृहरि जी और अन्य सभी नेता यहां बैठे हुए हैं, सबकी तरफ से मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करता हूं, कांग्रेस के नेताओं से आग्रह करता हूं कि इतनी गलत घटना होने के बाद इतना तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेताओं को सोचना और समझना चाहिए था... (व्यवधान) आप मैडम स्पीकर से क्षमा याचना करें... (व्यवधान) और मैडम स्पीकर को यह बतायें कि यह लोकतंत्र के खिलाफ था, यह सदन की परम्परा के खिलाफ था, यह घटना सर्वदा ठीक नहीं है, इसलिए हम क्षमाप्रार्थी हैं। ऐसा

कहते हुए कांग्रेस के नेता आपके सामने खड़े होते केवल मात्र वह सस्पेंशन रिवोक करो, यह बात वापस लो, खड़गे साहब, यह कहने से कुछ नहीं होता...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप बाहर की लिंगिंग के बारे में, बाहर की वायलेंस के बारे में बात करते हो, परंतु हाउस में यह जो घटना घटी, इसके बारे में आपकी राय क्या है...(व्यवधान) क्या यह जायज है? ...(व्यवधान) यह प्रजातंत्र का मंदिर है, इस मंदिर की अध्यक्षता माननीय सभाध्यक्षा जी करती हैं, वह एक महिला हैं, क्या एक महिला के ऊपर आप पेपर फाड़कर, पेपर के गोले बनाकर फेंकोगे? अगर आप ऐसा बाहर करते तो आई.पी.सी. का सैक्शन लगता। कांग्रेस पार्टी को इतना तो समझ में आना चाहिए कि वह मैडम से क्षमा याचना करें। फिर भी मैडम ये जो चर्चा मांग रहे हैं, उस चर्चा के लिए हम तैयार हैं। बी.ए.सी. में आप समय तय करिये, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया) हाउस में चलेगी तो वह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया)शब्द रिकार्ड पर नहीं जायेगा, आप ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया) क्यों बोलते हो।

...(व्यवधान)

(m1/1215/gg-sr)

माननीय अध्यक्ष : अब बात हो गई न तो बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वीरेंद्र कुमार जी, बैठिए, सब लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चंदूमाजरा जी, बोलिए?

...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम, देश में विशाल जल संकट है। ...(व्यवधान) देश में वॉटर क्राइसिस का बहुत बड़ा इश्यु है। ...(व्यवधान) हमें सबसे पहले उसको डिस्कस करना चाहिए। ...(व्यवधान) जिससे कुछ न कुछ समाधान निकाल जाए। ...(व्यवधान) राष्ट्र को फायदा हो पाए। ...(व्यवधान) सबसे पहले नियम-193 में मैंने नोटिस दिया हुआ है। ...(व्यवधान) इस जल संकट पर पहले चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव जी - आप नहीं बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गोपाल शेटी जी बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे ज़ीरो ऑवर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया है। ...(व्यवधान) आज जब चीन के सैनिक हमारी सीमाओं पर घुसपैठ को ले कर हमारी सेनाओं के साथ नॉक-ड्रॉक और भारी तनाव बना कर युद्ध जैसी स्थिति बना रहा है। ...(व्यवधान) ऐसी स्थिति में हमारे देश के सभी नागरिकों को और सरकारी तथा गैर-सरकारी कंपनियों को चीन निर्मित सभी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। ...(व्यवधान) मेरी जानकारी के मुताबिक चीन से प्रति माह बड़ी संख्या में निम्न सामान जैसे 1. हैडरेस्ट कवर, 2. एयरसिकनेस बैग, 3. डिस्पोज़ेबल पिलो कवर, 4. टिनफॉयल और कैसरोल, 5. हैडसेट इत्यादि सामानों की खरीदी एयर एण्डिया द्वारा की जा रही है तथा देश में चीन निर्मित सामानों की बिक्री जारी है। ...(व्यवधान) उस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। ...(व्यवधान) चीन निर्मित उत्पादों पर देश में प्रतिबंध लगाने से जहां चीन की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी, वहीं

हमारे देश में निर्मित समान सरकार के मेक इन इण्डिया प्रोग्राम को और अधिक गति प्रदान करते हुए, मज़बूती दे कर हमारी अर्थव्यवस्था और अधिक बेहतर बनाएगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री आलोक संजर, श्री शरद त्रिपाठी, श्री रोड़मल नागर, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रामचरण बोहरा, डॉ. मनोज राजोरिया, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री अर्जुन लाल मीणा, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री निशिकान्त दुबे, श्री शिवकुमार उदासि एवं डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री गोपाल शेटी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

श्री छोटेलाल (राबट्सगंज) : अध्यक्ष महोदया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदया,

“ देश के किसान नाही रहिएं तो दो जून की रोटी मुहाल हो जाई।
अ सीमा पर जवान न रहिए तो देसवा बेहाल हो जाइ। ”

दोनों की ही रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। ... (व्यवधान) ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर ये विपक्षी दल के लोग बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा है। ... (व्यवधान) दोनों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। ... (व्यवधान) मनरेगा को कृषि कार्य खेती-बाड़ी इत्यादि संपूर्ण कार्यों के लिए जोर देना चाहिए। ... (व्यवधान) जिससे मज़दूरों और दलितों को बरसात के महीने में भी रोज़गार मिलता रहेगा तथा किसानों का समर्थन मूल्य लगभग 300 रुपये से 400 रुपये प्रति क्विंटिल से बढ़ा कर धान खरीद करना चाहिए। ... (व्यवधान) अपने ही देश में किसानों के धान, गेहूँ, सब्जी इत्यादी खरीदना अनिवार्य कर देना चाहिए। ... (व्यवधान) महोदया, डीजल एवं खाद पर सब्सिडी किसानों को देने का प्रावधान करना चाहिए। ... (व्यवधान) वैसे हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किसानों की आय सन् 2022 तक दुगना करने की सोच रहे हैं। ... (व्यवधान)

जो मुफ्त शिक्षा, दवा मुफ्त देगा, किसानों की हरदम सुरक्षा करेगा, और देगा समय से बिजली, खाद पानी, वही तो किसानों का नेता रहेगा। वही तो किसानों का नेता रहेगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, श्री अर्जुन लाल मीणा, श्री सी.पी. जोशी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री छोटेलाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Thank you hon. Speaker, Madam. The introduction of NEET has created a huge uproar in Tamil Nadu and many pertinent questions were raised. Our beloved leader Puratchi Thalaivi Amma had categorically opposed to the introduction of NEET as it was a direct infringement on the rights of the State and would cause grave injustice to the students of Tamil Nadu.

The Government of Tamil Nadu has established many Government medical colleges across the State to achieve the optimum Doctor-Population ratio and to augment the medical service infrastructure. If these seats are taken away by students of other States through NEET, it will create non-availability of doctors and medical services particularly in rural areas of Tamil Nadu.

Keeping this in view, the Tamil Nadu Legislative Assembly has passed two Bills for protecting the existing admission policy for UG and PG admissions in Medical and Dental Colleges. The two Bills have been sent to the Government of India for obtaining the assent of the President of India under Article 254(2) of the Constitution of India.

(n1/1220/ub-cs)

With a view to protecting the prospects of the State Board students and providing them fair and equal opportunity, the Government has taken a policy decision to allocate 85 per cent of State quota seats to the Tamil Nadu State Board students and balance 15 per cent to the students from other Boards, and conduct admission based on marks obtained in NEET.

In this situation, I urge the Government to facilitate the Presidential assent for two Bills may be accorded immediately to enable the Tamil Nadu State to continue its existing system of admission to Government Medical and Dental Colleges.

HON. SPEAKER: Shri P.R. Sundaram is permitted to associate with the issue raised by Shri S.R. Vijaya Kumar.

HON. SPEAKER: Shri P. K. Biju – Not present.

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): The continuing apprehensions of our fishermen and the attempts of Sri Lankan Government to destroy the Indian fishing operations in the Palk bay waters is highly disturbing and deplorable. The recent legislation enacted in the Sri Lankan Parliament regarding impounding and levying huge penalties is creating a sense of fear and unrest among the fishermen community in Tamil Nadu.

The Sri Lankan Government plans to move a new Bill “The Fisheries and Aquatic Resources (Amendment) Bill”. Under the provisions of this draconian Bill, the fishermen could be imprisoned for

two years and a huge fine up to 50,000 Lankan Rupees will be imposed. The latest amendment Bill is aimed at causing catastrophe to the livelihood of our fishermen.

I strongly reiterate that the stand taken by our revered leader, Puratchi Thalaivi Amma that the retrieval of Katchatheevu and the re-fixation of IMBL would alone bring a lasting solution to this vexatious issue.

I, therefore, once again urge the Government to intervene immediately to secure the release of 92 fishermen and 144 fishing boats from the Sri Lanka and to find diplomatic ways to restore Katchatheevu and to regain our traditional fishing rights in Palk Bay.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri P.R. Sundaram and Shri K. Ashok Kumar are permitted to associate with the issue raised by Shri V. Elumalai.

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Madam, I want to raise an important issue.

HON. SPEAKER: Your subject has already been answered by the Minister yesterday.

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): It is just an update. Within one hour of the External Affairs Minister's statement, we saw pictures on the media that mass graves have been found around Badush jail. We appreciated the External Affairs Minister's statement, but she also could have appreciated the work of a woman reporter from India who had sent investigative reports from the ground telling us that the Badush jail was in ruins.

So, I would urge the External Affairs Minister to provide an update to her statement and also provide the full circumstantial evidence of what is going on in Mosul and the Badush area. We want to hear from the Government. We do not want to rely only on media reports. There should be authoritative statements from the Government about the full and detailed position in Mosul.

HON. SPEAKER: Adv. Joice George and Shri Rabindra Kumar Jena are permitted to associate with the issue raised by Shri Sugata Bose.

SHRI GEORGE BAKER (NOMINATED): I would like to draw the attention of this House to an incident that took place on 24th of June at a place called Katiganga in Burdwan District at Kalna Sub-division....
(Interruptions)

I was on my way with some *Karyakartas* to attend Vistarak Yojana which was a Party programme. As we were passing in front of the Trinamool Congress Office, the procession was belaboured by the members of the Trinamool Congress who came out of their office. They came, vandalized my vehicle and assaulted me. I know that law and order is a State subject, but, at the same time, the present lawlessness is there in Bengal ranging right from Darjeeling right up to Basirhat and other places. This should be taken into consideration in this House. I just wonder if a Member of Parliament is assaulted by Trinamool Congress people, what is the condition of our *Karyakartas* there in West Bengal?

I would request everyone in this House to permit that there be some discipline in West Bengal. ... (Interruptions) Do not ask me to sit

down. Like you, I am a minority. You please keep quiet. Allow me to speak. You have no right to stop me. It is only the hon. Speaker who can stop me, not you or anyone else. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Sharad Tripathi, Shri Shiv Kumar Udasi, Shri Nishi Kant Dubey, Shri Bhairon Prasad Mishra, Prof. Richard Hay and Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri George Baker.

(o1/1225/hcb/kmr)

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे शून्य काल में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सदन का और माननीय मंत्री जी का ध्यान स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की तरफ दिलाना चाहती हूँ। सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना का मैं समर्थन करती हूँ। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, अभी स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था अध्यापकों द्वारा की जाती है जिसमें स्कूल के अध्यापकों का अधिकांश समय मिड डे मील को तैयार करने में लग जाता है। पहले कभी अगर विभाग की जांच आती थी तो स्कूल की पढ़ाई का स्तर देखा जाता था। आजकल जो इंस्पैक्शन होता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि मिड डे मील कैसा बना है, रसोई की व्यवस्था कैसी है, खाद्य सामग्री कहाँ है। मेरा मानना है कि इससे अध्यापकों का अधिकांश समय नष्ट होता है और सीधा-सीधा जो सामान खुरद-बुर्द कर देते हैं, वह भी राष्ट्र का एक नुकसान है। मेरा निवेदन है कि मिड डे मील व्यवस्था का रिव्यू किया जाए। यह किसी प्राइवेट संस्थानों को दें या क्या करें, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री अर्जुन लाल मीणा एवं श्री शरद त्रिपाठी को श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान - उपस्थित नहीं।

श्रीमती रमा देवी।

...(व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण - तीन जिलों में बँटा हुआ है। इनमें से पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले के बीचोंबीच लाल बकिया नदी बहती है जिस कारण वर्षा के दिनों में लोगों को आपस में एक से दूसरे जिले में संपर्क स्थापित करने के लिए या तो काफी दूरी तय करनी पड़ती है अथवा नावों का सहारा लेना पड़ता है, जिसके चलते उक्त लाल बकिया नदी में समय-समय पर नावों के दुर्घटनाग्रस्त होने से दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है। जनता की इस त्रासदी को देखते हुए उक्त तीनों जिलों को परस्पर आपस में जोड़ने के उद्देश्य से जनवरी, 2013 में सरकार द्वारा पूर्वी जिला अंतर्गत फुलवरिया घाट पर आरसीसी पुल निर्माण की एक महत्वाकांक्षी योजना का आरंभ किया गया था जिसका तय समय-सीमा के अंदर निर्माण किया जाना था, किन्तु चार वर्षों में मात्र ढाँचा तैयार किया गया है। विगत छः-सात माह से निर्माण कार्य पूर्णतः ठप है। ...(व्यवधान) मुझे जानकारी मिली है कि इस काम को अधूरा छोड़ दिया गया है। यह परियोजना सीतामढ़ी-पूर्वी चंपारण जिलों की लाइफलाइन है और वर्षा के दिनों में डाइवर्जन भी बंद हो जाता है। इस कारण से वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है एवं बार-बार दुर्घटना होने की संभावना रहती है। प्रशासन द्वारा भी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी जाती है। सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनहित में फुलवरिया घाट पुल के बंद पड़े पुल निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं हिमालय में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास और संवर्द्धन की दिशा में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी 18452 गाँव जो अंधेरे में डूबे हुए थे, उनमें से 13511 गाँव अभी तक विद्युतीकृत हो गए हैं जो 2019 तक पूरे हो जाएँगे। ... (व्यवधान)

महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि आज देश की प्रगति की दिशा में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी जो क्रांतिकारी योजनाएँ हैं, वे ऊर्जा पर ही निर्भर होंगी। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यह भी ऊर्जा पर ही निर्भर होगी। कोयला पर आधारित जो भी प्लांट हैं, वे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं इसलिए ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा का उत्पादन है, वह प्रदूषण रहित होना चाहिए। हिमालयी राज्यों में जलविद्युत परियोजना, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी व्यापक संभावनाएँ हैं जिन पर एक विशेष कार्य योजना होनी चाहिए और हाइड्रो, सोलर तथा विंड जैसी परियोजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति के साथ-साथ राज्यों द्वारा मिनी और माइक्रो प्रोजैक्टों हेतु स्थानीय जनता को प्रोत्साहित किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे समृद्ध भारत का सपना भी पूरा होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि समूचे हिमालय के क्षेत्र में सर्वेक्षण कराकर पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रोजैक्टों के लिए स्थान चिह्नित किए जाएँ और स्थानीय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी इन परियोजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इससे पलायन भी रुकेगा, देश की अर्थव्यवस्था भी मज़बूत होगी और ऊर्जा का संरक्षण भी होगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री अर्जुन लाल मीणा एवं श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(p1/1230/rk-rv)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I would like to raise the following matter in 'Zero Hour'.

Our State of West Bengal is facing the threat of floods in six districts namely, Birbhum, Bankura, Murshidabad, Howrah, Hooghly and East Midnapore. Already three people have died in three districts. A large number of villages are facing water logging. This flood threat is man-made. The flood threat has come due to release of water from the dams of Damodar Valley Corporation. Since West Bengal is in the lower reaches of river Damodar, our suffering is more. The water level in Tenughat reservoir in Jharkhand is already high and the dam is likely to release more water. The DVC has released two lakh cusecs of water in three days from Maithon and Panchet dams, both of which are situated in West Bengal. ... (*Interruptions*)

The State Government has been repeatedly requesting for de-silting of the reservoirs in above dams since a long time but the DVC, which is under the Central Government, has taken no steps. Nor has the Centre given approval to the Lower Damodar Drainage Scheme.... (*Interruptions*)

Madam, the flood in West Bengal is man-made. I may say that the Prime Minister went for an aerial survey of floods in Gujarat and sanctioned Rs.500 crore for flood relief, which is all right but he did not

come to visit Assam, which is badly affected by flood, or Rajasthan let alone West Bengal. We want the Prime Minister to deal with all the flood affected States on an equal footing and take steps to stop the man-made floods in West Bengal. Thank you, Madam.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri C. Mahendran. Three Members are raising the same issue.

*SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): Hon. Madam Speaker, Vanakkam. The introduction of National Eligibility cum Entrance Test (NEET) for admission into medical colleges will only be unilaterally favouring the rich students of Urban areas. Whereas, the rural poor students, who are socially and economically backward, will not be able to compete with the urban students. This may lead to a state of inequality which is dangerous. The students from urban areas can avail facilities like coaching centres, classes and study material for getting them prepared for the NEET. But the same facilities are not available for the socially and economically backward rural students. Moreover, NEET has created confusion and frustration among the poor students especially those living in the small towns and villages of Tamil Nadu. Under the golden reign of Hon. *Puratchithalaivi* Amma, Tamil Nadu remained and continue to remain a progressive State in providing health and public sanitation to all the people of Tamil Nadu particularly the rural poor. Under the able vision of Hon. *Puratchithalaivi* Amma, 22 medical colleges were opened in the State in order to bring out well-trained doctors matching with the population of Tamil Nadu. Particularly in the rural areas of Tamil Nadu, we need to have trained Doctors who know the local language, Tamil. If the students from other States join the medical colleges located in Tamil Nadu through NEET then it will drastically affect the total number of serving Doctors in Tamil Nadu. I therefore urge upon the Union Government to exempt Tamil Nadu from NEET. Thank you.

* Original in Tamil

HON. SPEAKER: You have raised your matter.

Dr. J. Jayavardhan, you can associate with him. Shri P.R. Sundaram is permitted to associate with the issue raised by Shri C. Mahendran.

(q1/1235/my-ps)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद।... (व्यवधान) मैं अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर की एक बहुत दुःखद सच्चाई के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ।... (व्यवधान) हमारा संसदीय क्षेत्र कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है, जो कि मुम्बई से लेकर लखनऊ के लिए सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे माना जाता है।... (व्यवधान) वहां पर माननीय गडकरी जी के माध्यम से बांकीपुरा का फोर लेन स्वीकृत हो गया है।... (व्यवधान) उसमें से 130 किलोमीटर का एक छोटा पार्ट, जो कबरई से कानपुर के बीच का है, वह पहले बी.ओ.टी. प्रोजेक्ट में हुआ था।... (व्यवधान) उसे केवल टू लेन बनाया गया था। अब उसकी यह स्थिति है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में चार हजार तथा पाँच हजार आबादी वाले गांवों के तीस-तीस, चालीस-चालीस नौजवान, जो कि साइकिल सवार और मोटरसाइकिल वाले होते हैं, उनकी मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है।... (व्यवधान) यह सच्चाई है और मेरे पास इसके आंकड़े हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि कबरई से कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन का बनाया जाए।... (व्यवधान) जब से उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी जी की सरकार आई है, वहां पर पहले जो ट्रकों में ओवरलोडिंग होती थी, अब उसको बंद करा दी गई है।... (व्यवधान) इसकी वजह से वहां पर ट्रकों की संख्या तीन गुनी हो गई है।... (व्यवधान) लोगों को चलना मुश्किल है और वहां पर टोल बूथ बनाए गए हैं।... (व्यवधान) जो लोग मार्ग दुर्घटना में घायल होते हैं, उनको टोल बूथों पर उपलब्ध एम्बुलेंस से इलाज के लिए ले जाया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस से अगले बूथ तक ले जाने में ही पीड़ित की मृत्यु हो जाती है।... (व्यवधान) मैंने अपनी आँखों से वहां पर देखा है कि एक

एम्बुलेंस में दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं और उसी राजमार्ग के बैरियर पर उसे पंद्रह मिनट रूकना पड़ता है।...(व्यवधान) वहां से निकलते वक्त दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मौत हो जाती है।...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भारत सरकार कबरई से कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 86 को छह लेन का बनाने का कष्ट करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र तथा श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में यमुना पार मैदानी व पहाड़ी दोनों इलाकों में खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरें नहीं हैं और न ही नलकूपों की संख्या ही इतनी है कि पूरे क्षेत्र में सिंचाई हो सके।...(व्यवधान) इस क्षेत्र में करछना, मेजा, बारा, कोरांव चार तहसील व इसी नाम से चार विधानसभाएं हैं, जिसमें कोरांव और बारा में पहाड़ी क्षेत्र काफी है।...(व्यवधान) सिंचाई के अभाव के कारण यहां भरपूर फसल नहीं हो पाती है।...(व्यवधान) मैंने सिंचाई हेतु यह सुझाव दिया था कि लिफ्ट कैनल योजना (यमुना नदी) के माध्यम से इन क्षेत्रों में सिंचाई कराई जाए। इन क्षेत्रों में और खास तौर से पहाड़ी क्षेत्र में पेयजल का भी बड़ा संकट गर्मियों में रहता है।...(व्यवधान) उक्त यमुना नदी के माध्यम से पेयजल आपूर्ति ओवर हेड टैंक स्थापित कर पेयजल पाइप लाइनों से संकटग्रस्त ग्रामों में पेयजल पहुंचाया जा सकता है।

हमारा यह अनुरोध है कि हमारी सरकार इस समस्या पर जरूर ध्यान दें।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी तथा श्री अर्जुन लाल मीणा को श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shrimati P.K. Shremathi Teacher - not present

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Thank you, Madam Speaker. I would like to draw your kind attention towards a newspaper article dated 07.07.2017 with the headline 'Telangana Pilgrim dies in gas cylinder mishap in bus in J&K, 13 injured.' The details may kindly be perused. But, as per the statements of the pilgrims and apprehensions, the incident was a terrorist activity and not a cylinder blast issue. Nevertheless, there was casualty and injury was caused to the devotees, who hailed from my parliamentary constituency, Kamareddy district of Telangana State, when they were returning from the Amarnath Shrine, from Srinagar to Jammu, after *darshan* of Lord Shiva. One of the devotees died while others suffered grievous injuries.

I would like to request, through the hon. Chair, to the hon. Minister of Home Affairs to look into the matter and grant suitable compensation to the victims on humanitarian and compassionate grounds, so that the dependants of the deceased and injured could feel compensated and obliged and not discriminated.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Bheemrao B. Patil.

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Hon. Speaker, I would like to raise an important and urgent issue to safeguard the interests of our citizens. India is basically an agricultural country, but farming in Tamil Nadu is at an alarming level. They are the least spoken people by Indian media. As a producer, our farmers cannot determine the price of their products. There are plenty of middlemen who procure at a cheap rate and sell through black market at a high price when the demand is

more. Many farmers who are doing farming, generation after generation, are now leaving farming and are working as unskilled labour in other sectors.

(r1/1240/rc/sk)

They do not want their kids to do farming as practically there is no career growth. The Government should relax its norms and it should allow farmers to declare the price of their goods along with limited controls to safeguard consumers' interest. Immediate action on this issue may stop farmers' suicides... (*Interruptions*).

Madam, secondly, we cannot dream of eating rice and vegetables, if procurement and production goes in the hands of corporate companies. They will decide their own selling price. Friends, if we would not support the farmers now, then, believe me, we would be digging graves not only for us but for our future generations too... (*Interruptions*).

Thirdly, many have started earning money through real estate. Farmers have started selling their land for cash and these real estate people destroy the farmland for creating townships... (*Interruptions*).

HON. SPEAKER: You have made your point.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri C. Gopalakrishnan... (*Interruptions*).

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, this is in connection with flood situation in West Bengal. Around 2.50 lakh cusecs of water have been released by DVC without any

intimation to the State Government due to which the districts which Prof. Saugata Rao has already mentioned, have been badly affected...
(Interruptions).

At this moment, dredging is very important because without dredging the water reservoirs cannot keep water at appropriate levels. Therefore, I would urge that the DVC should take such decisions in consultation with the State Government. They will help DVC adequately. They will contribute towards funds for improving the dredging system so that a permanent solution can be found out...
(Interruptions).

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र राँची में छावनी के जवानों द्वारा जो घटनाएं हो रही हैं, उनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र राँची में स्थित मिलिट्री छावनी के अधिकारियों द्वारा ग्राम सुगनू, गाढी एवं हुन्दरू के लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। ...(व्यवधान) 11 जुलाई, 2017 को हुन्दरू सड़क को मिलिट्री छावनी के अधिकारियों के आदेश पर जेवीसी से रास्ते को काट दिया गया। इस मिलिट्री छावनी के आसपास दर्जनों गांवों की यह सड़क शुरू से ही आवागमन का साधन है। ...(व्यवधान) सड़क काटने के विरोध में 12 जुलाई, 2017 को मिलिट्री क्षेत्र के पास एयरपोर्ट सड़क पर जन आंदोलन होने से दिन भर जाम रहा। ग्रामीण लोगों की बुनियादी सड़क सेवा को बंद किए जाने पर अभी गांव के लोगों में भयंकर क्रोध है और कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। इन गांवों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बिछाई जाने वाली सड़कों में पानी के पाइप भी मिलिट्री के जवान लगाने नहीं देते हैं। ...(व्यवधान) इस संबंध में मेरा निवेदन है कि मिलिट्री के स्वार्थी अधिकारियों की जांच हो और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

मुझे खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि मैं मिलिट्री छावनी के अधिकारियों के तुष्टीकरण कार्यों की बात सदन में उठा चुका हूँ, परंतु आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ... (व्यवधान) ग्राम सुगनू, गाढी और हुन्दरू के ग्रामीण लोगों ने हजारों एकड़ जमीन एयरपोर्ट और मिलिट्री छावनी को दी है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र रांची के हुन्दरू ग्राम में 11 जुलाई को मिलिट्री छावनी के अधिकारियों के आदेश पर सड़क को जेवीसी से काटा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ... (व्यवधान)

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak during ‘Zero Hour’ about the most important, sensitive and burning issue of illegal drug trafficking and drug abuse in Telugu-speaking States of Telangana and Andhra Pradesh in particular... (*Interruptions*).

I wish to bring to the notice of this House that in a series of incidents in Hyderabad, a huge drug racket had been busted and almost 20 people were arrested of which five to six people are foreigners... (*Interruptions*).

(s1/1245/snb-rjs)

Accordingly, around 12 Tollywood celebrities and personalities have been summoned by SIT. These drug rackets are actually targeting the students and the youth of the State. So many people have been involved in this. The Media is doing a lot of speculation in the matter. As per the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, the Union Government is empowered to enquire in such cases.

Madam Speaker, through you, I would like to request the Union Government to kindly intervene in the matter and take over the case and entrust this matter of enquiry to the NCB for further investigation.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kothapalli Geetha.

Smt. Renuka Butta, you can also associate with this matter.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Madam Speaker, I would like to bring to the notice of this august House about the disturbing involvement of children in drug abuse and its murky net in Hyderabad. More than 200 children are reported to have procured LSD blots, apart from involvement of high profile individuals. This is only a tip of the iceberg. This may have surfaced in Hyderabad but might have spread across the country, especially in major cities. This is a problem concerning the health of India and its culture. The problem is more serious because the children who are the future and hope of this country, and the youth are being dragged into this murky trade.

The situation is so grave that the children are able to place orders online and get the stuff of their choice. I appreciate the Government of Telangana for their prompt action and investigation in the matter.

It is further reported that Visakapatnam has become the trade centre for supply of cannabis, locally known as '*ganjayi*' from where it is supplied across the country. It is necessary to find out whether what has been unearthed has terror and international ramifications.

We need to combat this menace by developing necessary specialized agencies for prevention of drug culture and cure of those affected. I request this Government to come out with a comprehensive legislation on this subject covering penal provisions, counseling, establishment of specialized rehabilitation and medical facilities...

(Interruptions)

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Butta Renuka.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, कल कारगिल दिवस था और इस दिन हम अपने शहीदों को याद करते हैं। इसी प्रकार से जेएनयू जैसी यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मांग की कि मुझे अपने क्षेत्र में डिसप्ले के लिए एक टैंक दे दीजिए, तो उसे कुछ लोगों ने विवाद बना दिया।

अध्यक्ष महोदया, मुझे याद है कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां पर एयरोप्लेन के मॉडल्स होते थे। वहां पुराने एयरोप्लेन रखे होते थे और स्कूल खत्म होने के बाद सब बच्चे उन हवाई जहाजों के आसपास खेलते रहते थे। जब वे बड़े हो गये, तो एयरफोर्स स्टेशन के जितने जहाज डिसप्ले पर हैं, वे उन्हें देखने आते हैं। इंडिया गेट के पास जो ट्रेनें खड़ी हैं, उन्हें देखने के लिए बच्चे उन पर चढ़ते हैं। जो राष्ट्रवाद की भावना है, वह राष्ट्र को समझने से ही प्राप्त होती है। इसमें जेएनयू जैसी यूनीवर्सिटी शायद एक प्रतिशत भी नहीं है, बहुत कम है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी कम है। यह यूनीवर्सिटी राष्ट्र के पैसे से चलायी जाती है। अगर वहां पर अलगाववाद के नारे लगते हैं या इस प्रकार के नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं व्यवस्था और विचार में गलती है। उस व्यवस्था और विचार को सुधारने के लिए कोई व्यक्ति विचार करता है, जो कि वहां के वाइस चांसलर हैं, तो वह राष्ट्रवाद का मुद्दा बना दिया जाता है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, जैसे एक पुराना गाना है कि 'हम लाये हैं तूफान से किशती

निकालकर, बच्चों इसे रखना संभाल के।' इस देश की संस्कृति, सभ्यता और वे शहीद, जो बार्डर सुरक्षित रखते हैं और जिसके कारण ये यूनीवर्सिटी चलती हैं, देश सुरक्षित है, उनका अपमान और अनादर इस देश की संसद और व्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए इस देश के सैनिक, जो राष्ट्र, एकता, सौहार्द और शक्ति के प्रतीक हैं, उनके आदर और सत्कार में जो कुछ किया जा सकता है, वह किया जाना चाहिए। इस यूनीवर्सिटी के बच्चों को शपथ लेनी चाहिए कि हम रहें या न रहें मां, मगर तेरा वैभव, यानी भारतमाता, राष्ट्रीयता का वैभव अमर रहे। ऐसी यूनीवर्सिटी से भविष्य के नागरिक उत्पन्न हो, यही मेरी कामना है। जयहिन्द।

माननीय अध्यक्ष : श्री रोडमल नागर, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री आलोक संजर, कुमारी शोभा कारानन्दलाजे, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री रमेन डेका, श्री हरिओम सिंह राठौड़, श्री अर्जुन लाल मीणा, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री संजय धोत्रे, श्री गोपाल शेट्टी, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री लाखन लाल साहू, डॉ. बंशीलाल महतो, श्री विनोद लखमाशी चावड़ा, श्री जनक राम, श्री रामेश्वर तेली और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(t1/1250/ru-rps)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak during the 'Zero Hour'.

I would like to draw the attention of the House to the fact that menstruating adolescent girls do not feel comfortable and shy away from schools during their periods. Specially the girls of rural and sub-urban areas mainly use home-made napkins which are even more uncomfortable and inconvenient to lead a normal social life. Most of the MPs of Trinamool Congress are providing napkin vending machines and incinerator machine to all girls and educational

institutions from our MPLAD funds to ensure menstrual hygiene as well as to increase the percentage of attendance of girl students. This work is a part of the Nirman Bangla Abhiyan. But imposition of 12 per cent GST on sanitary napkins will become a major roadblock in our efforts.

This tax is a tax on our necessity. This is a tax on the right of basic health care. Women from economically weaker sections have been severely affected by this decision and women of Maharashtra have been on hunger strike against this regressive decision of the Government. Their voices remain unheard.

So, I request the hon. Finance Minister through you to think about this issue and withdraw the tax on sanitary napkins to make way for Swachh Bharat Abhiyan to become successful.

HON. SPEAKER: Shrimati Arpita Ghosh, Dr. Mamta Sanghamita and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Pratima Mondal.

श्री सुरेश सी. अंगड़ी (बेलागवी): बहुत-बहुत धन्यवाद, मैडम।

मैडम, कर्नाटक राज्य पिछले चार साल से ड्राउट से अफेक्ट हुआ है। इसके लिए मेरी विनती है कि राज्य सरकार उधर राजनीति में लगी हुई है, एक दिन झण्डे का लगाते हैं, एक दिन कास्ट का लगाते हैं।... (व्यवधान) मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि उस दिन किसानों के बारे में बात करने के लिए रात साढ़े दस बजे तक आपने अवसर दिया था, मगर हमारे कांग्रेस पार्टी के फ्रेंड्स, हमारे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी उस दिन यहां मौजूद नहीं थे, उधर केवल दो लोग हाउस में थे। ... (व्यवधान) कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार है, वहां कांग्रेस राजनीति कर रही है। उधर से लोग वहां जाकर झगड़ा लगा रहे हैं। वहां किसान मर

रहे हैं, किसानों के लिए कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। किसान के लिए चर्चा करने को तैयार नहीं हैं।... (व्यवधान) मेरी विनती है कि मेरे जिले में सूखा पड़ा है, वहां बारिश नहीं हुई है। मेरे जिले की रामदुर्ग तालुका, बोका तालुका, सौदक्या तालुका और पार्ट ऑफ हैदराबाद और कर्नाटक प्रभावित हुए हैं। ... (व्यवधान) मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे देश के वरिष्ठ नेता हैं। ... (व्यवधान) मल्लिकार्जुन खड़गे जी, किसानों के बारे में बात कीजिए। कोई किसानों के बारे में बात नहीं कर रहा है। मेरी आपसे विनती है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुरेश सी. अंगड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

1253 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

(u1/1400/rbn/asa)

1402 hours

*The Lok Sabha re-assembled at two minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Shri Ramen Deka *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID

1402 hours

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAMEN DEKA): Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377

today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

Re: Need to use river-friendly techniques

SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE (RAVER): Rains falling on lands are drained into rivers running through lengths of catchments & finally discharged into seas in natural drain arrangements. Out of the total rainfall a part is absorbed in the land and the balance reaches the rivers. The absorption of water depends and differs from catchments to catchments and depends upon the land characteristics. Presently with availability of technology, water demand requirements for growing population, demand for more lands and industrial needs man is regulating nature's rivers and also encroaching on the rivers flood path for constructions. Also due to control of river for storage of water through barrages & dams, the downstream of the dam/barrages gradually dries up disturbing rivers' path. Through the august House, I request the Hon'ble Minister to depute a group of experts in this field to study the river-friendly techniques and chalk out proper river and rain management steps to maintain their geophysical characteristics and establish a model law to address these issues.

(ends)

Re: Need to upgrade sub-post office at Maharajganj district headquarters in Uttar Pradesh as Main Post Office

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज):

**Re: Need to ensure payment of arrears to sugarcane farmers by
sugar mill in Motihari under Sheohar parliamentary
constituency, Bihar**

श्रीमती रमा देवी (शिवहर):

**Re: Need to fill-up the vacant posts of sanitary workers in
Railways on permanent basis**

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :

Re: Need to extend Jagdishpur-Haldia and Bokaro-Dhamra gas pipelines upto Rohtas and Kaimur districts of Bihar

श्री छेदी पासवान (सासाराम) :

Re: Need to accord approval to the proposal of Government of Gujarat for establishment of Aanganwadi and Mini Aanganwadi centres in the State

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) :

**Re: Need to build a railway over bridge at level crossing no. 1 near
Gaya Railway Station, Bihar**

श्री हरि मांझी (गया) :

**Re: Need to set up a water treatment plant in Dibrugarh
Parliamentary Constituency of Assam**

SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): My constituency Dibrugarh has a large number of tea gardens. The area is famous for mineral resources like oil, gas, and coal. But the area lacks facilities in drinking water. Despite having many rivers in my constituency, the people of my constituency is facing the problem of non-availability of potable water. There are some places in my constituency where fluoride and other harmful substances have also been found. But people are compelled to drink such contaminated water. I, therefore, request the government to set up a water treatment plant in my constituency, Dibrugarh, for uninterrupted supply of potable water to the people of my constituency.

(ends)

**Re: Need to restart the Additional Central Assistance scheme for
Left-Wing Extremism affected districts in Bihar**

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) :

**Re: Need to undertake cleanliness drive at railway lines near
railway stations**

श्री गणेश सिंह (सतना) :

**Re: Need to provide funds for various drinking water projects in
Barmer parliamentary constituency, Rajasthan**

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) :

**Re: Need to provide direct cash transfer to people in lieu of subsidy
on foodgrains under PDS**

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) :

Re: Need to enact a law for safety of journalists in the country

श्री राजीव सातव (हिंगोली) :

Re: Need to review the decision of Indian Oil Corporation to set up storage facility at Puthuvyppu in Kochi, Kerala

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): There is widespread agitation against the establishment of an L & G storage facility by IOC in Puthuvyppu, Kochi, Kerala by the local people. People fear that this storage facility will be hazardous and dangerous to the local people. Vypeen is a thickly populated island. The people believe that there is violation of CRZ rules, environmental regulations, etc. There is also a case before the Green Tribunal, Chennai against the project. I request the Government not to take any hasty decision until residents apprehensions are addressed.

(ends)

Re: Need to reduce GST rate on fire crackers

SHRI T. RADHAKRISHNAN (VIRUDHUNAGAR): Fireworks industry was started in Sivakasi in the year 1930. Since then it has grown day by day and supporting the livelihood of 8 lakh people in the Virudhunagar District alone by direct employment and another 100 lakh people across the country who earn their living by transporting and selling fireworks.

GST Council in its meeting has decided to impose GST at 28% on fireworks, If the government starts charging 28% GST, the prices of crackers will increase by a minimum of 30% which will affect the sale of crackers which leads to reduction in sales ultimately affecting the employment opportunities of 8 lakh people. Further, the fireworks industry is already facing stiff competition from cheap illegal Chinese fireworks. Therefore, Fireworks industry, if taxed on higher scale, cannot compete against the tax free illegal Chinese fireworks.

The fireworks factories will now vanish under the GST regime with the steep 28% GST rate. This upper most rate of 28% will lead to huge evasions and overall corruption and act as a sure killer of the industry. Since the prevailing “value based exemption” will be scrapped under GST, all the 1220 factories will be brought into GST coverage. Therefore, even a lower rate of tax like 5% or 12% will ensure total compliance from all the 1220 factories, thereby generating enormous and multifold increase in revenue.

Globally, India ranks second in the world next to China in terms of its annual production of fireworks. The fireworks industry can surge forward to meet the global challenges, provided the industry is allowed to survive by charging affordable GST rates like 5% or 12%.

As a member of Lok Sabha from Virudhunagar Constituency, I call upon the government to reduce the GST rate for fireworks from 28% to 5% or 12% thereby saving the industry and livelihood of several lakh people dependent on it.

(ends)

Re: Monitoring of Central Grants to Jammu & Kashmir and repealing of Article 370

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): The Framers of the Constitution, due to various reasons, granted special status to some States upon their accession to the Indian Union. The State of J&K enjoys special status vide the provisions of Art. 370 as a Temporary and Transitory arrangement. While in respect of other States, the special-status provisions have been repealed, in respect of J&K, Art. 370 still remains, The Government of India has been bankrolling the State of Jammu and Kashmir with the money of taxpayers from the rest of India. The mere 1% of Indian population in J&K gets 10% of the grants from the Centre. Over the years, the Government of India (GOI) has been pumping thousands of crores into J&K for developmental works- power projects, railway lines, better roads, prestigious industries and academies of excellence, which resulted in improvement of life of the common man in Kashmir. In comparison, their counterpart in PoK, is poverty-stricken, disease-ridden and unemployed. Between 2000 and 2016, the Gol sanctioned for J&K nearly Rs. 1.25 lakh crore. The NDA under the leadership of the Hon'ble Prime Minister in its outreach to the people of J&K allocated more funds. Each person in J&K received Rs. 91,300 per person over the last 16 years in contrast to Rs. 40001/- per person in the rest of India. The Central grants account for 54% of the State's revenue and 44% of the State's expenditure. The worst part is, the State fails to submit proper audited returns; and ignored several CAG queries.

The Special Status coupled with the infusion of huge Central Grants into Jammu and Kashmir is only counter-productive. Terrorism sponsored by Pakistan and China has taken a toll on the health of the State. Brave sons of India are falling prey to the bullets of violent faceless cowards. The schools and colleges remain closed. The attempts of the Government of India to bring them into the national mainstream have failed. Therefore, I urge the Home Ministry to move an amendment to the Constitution to repeal the temporary provision of Art. 370 thereby allowing amalgamation of J&K with the rest of India by permitting the citizens from rest of India to settle in J&K and exercise more vigilance in monitoring the outlay of Central Grants.

(ends)

Re: Alleged irregularities in Rourkela Steel Plant, Odisha

SHRI BALBHADRA MAJHI (NABARANGPUR): It is appearing in print and electronic media for quite some time that there are large scale alleged irregularities in Rourkela Steel Plant. Some of the alleged irregularities are as follows :-

(1) Blast furnace slag was being sold at a throwaway price without resorting to e-tender, favouring only a few. Finally when it was enforced by an honest Additional Chief Vigilance Officer it turned out that as against previous price of about Rs.275/- per tonne it fetched Rs. 1065 to Rs. 1105 per tonne meaning a loss of about Rs. 26.00 crores in six months.

(2) There was breakdown of newly commissioned Blast Furnace no. 5 for a period of 20 days, causing an immediate loss of Rs 50.00 crores and reducing its life span by about 12 years.

(3) Officers are allowed to continue beyond their period of superannuation. It is learnt that in all these cases, the issues were brought to the notice of Minister concerned and no action seems to have been initiated even after writing about the said alleged irregularities to the Minister concerned.

It is urged upon the Government to investigate the matter through an independent agency like CBI and initiate action against the defaulters.

(ends)

Re: Need to reopen manned railway crossing and provide a halt station and an underpass at level crossing near Sooryagarh Jagannath in Pratapgarh parliamentary constituency, Uttar Pradesh

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़) :

Re: Need to undertake survey of unurveyed land in the country particularly in Rajmahal parliamentary constituency, Jharkhand

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) :

Re: Implementation of Forest Conservation Act, 1980

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): The Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are being deprived of their rights due to various reasons including the lack of clarity in rules, regulations and procedures for implementing programmes meant for them. The interstate migration of SC people after 1950 is still continuing as a grey area which resulted in denial of rights conferred over them including benefits of education and protection against atrocities. Similarly the programmes and projects meant for the tribal people are also in jeopardy due to indiscriminate exercise of power by various departments mostly the forest and wildlife. The establishment of road connectivity, electric line and improvement of tribal habitats are being obstructed by the forest officials citing lame excuses under the pretext of implementing Forest Conservation Act 1980. The forest right act is also being misinterpreted and misused to their disadvantage. Therefore, the urgent intervention of the Government is requested to solve the above.

(ends)

COMPANIES (AMENDMENT) BILL - Contd

1203 hours

HON. CHAIRPERSON: Now, the House will take up Item No. 9, the Companies (Amendment) Bill, 2016.

Hon. Minister to continue.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति जी, मैं कंपनीज अमेंडमेंट बिल, 2016 के बारे में कहना चाहता हूँ। यह बिल चर्चा करने और पास करने के लिए है। बिल के साथ कुछ ऑफिशियल अमेंडमेंट भी हैं जिनको मैंने ऑलरेडी मूव कर दिया है। मेरा यह कहना है कि कंपनीज एक्ट 2013 दिनांक 19 अगस्त 2013 को नोटिफाइड हुआ था। 2013 के अधिनियम द्वारा कंपनीज एक्ट में बहुत अमेंडमेंट किये गये थे। मुझे ध्यान है कि पन्द्रहवीं लोक सभा में देर रात तक इसके लिए बैठे थे, जैसे स्टोक होल्डर का डिसक्लोजर, डाइरेक्टर, ऑडिटर व प्रमुख कार्मिकों की एकाउंटेबिलिटी है तथा इसका मुख्य उद्देश्य इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेन्स है। That was the main objective behind this amendment to the Companies Act.

(w1/1405/raj-rp)

इस एक्ट के प्रारंभिक काल में कुछ परेशानियां आयी थीं, रिप्रजेंटेशंस आये, जिसको दूर करने के लिए हमारी सरकार आने के बाद मई, 2015 में अमेंडमेंट किया गया था।

सभापति महोदय, जब वर्ष 2015 में कंपनीज एक्ट, 2015 पर राज्य सभा में चर्चा हो रही थी, तब यह सुझाव आया कि अमेंडमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रूप में आना चाहिए और इसी श्रृंखला में बहुत माननीय सदस्यों ने कंपनी एक्ट के नये संशोधनों को सुधारने के लिए प्रतिवेदन दिये, जिस पर एक कमेटी बनी, जिसका नाम कंपनी लॉ कमेटी था और कहा गया कि इसमें जितने भी स्टोक होल्डर्स हैं, उनसे वह चर्चा करें, चाहे वह चार्टर्ड एकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट्स हों, कंपनी सेक्रेट्री इंस्टीट्यूट हो, कॉस्ट एकाउंटेंट इंस्टीट्यूट हो, इंडस्ट्रीयल

एसोसिएशन हो, सीआईआई हो, एसोचैम हो, फिक्की हो, पी एच डी चैम्बर्स एंड कॉमर्स हो, इन सभी से चर्चा करें और चर्चा करके एक कॉन्ग्रिगेशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आएं। सेक्रेट्री कॉरपोरेट अफेयर्स के बीच में अध्यक्षता बनी, उन्होंने एक फरवरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उसके बाद यह मैटर स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को रेफर हो गया। मैं श्री एम.वीरप्पा मोइली जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वह इस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनके सभी वरिष्ठ साथी भर्तृहरि महताब जी, सौगत राय जी, किरीट सोमैया जी, दिनेश त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये, एक कॉन्ग्रिगेशनल रिपोर्ट आयी। इस रिपोर्ट के बाद यह बिल लोक सभा में 16 मार्च, 2016 को इंट्रोड्यूस हुआ। जब यह बिल 16 मार्च, 2016 को इंट्रोड्यूस हुआ तो कमेटी को रेफर हुआ और 12 अप्रैल, 2016 को कमेटी को यह रिपोर्ट दिया और 07 दिसम्बर, 2016 को अपनी रिपोर्ट आयी। कमेटी ने दो फील्ड विजिट भी की - मुंबई एंड बंगलुरु, उसमें नेशनल एसोसिएशंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी से भी कंसल्ट किया और एसोसिएशन से भी कंसल्ट किया।

(x1/1410/ind-rcp)

मैं आपके माध्यम से इनिशियल रिमार्क में यह कहना चाहता हूँ कि इस अमेंडमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है, वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। मुझे विश्वास है कि इस अमेंडमेंट के बाद प्रॉसिजर सिम्प्लिफायड हो जायेगा। कम्प्लायंस सरल हो जाएगा और जो कम्पनियां डिफॉल्ट करेंगी, उन्हें सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से किया गया है। कम्पनीज अमेंडमेंट एक्ट, 2016 के मुख्य उद्देश्य का मैंने जिक्र किया है। उसके साथ-साथ होल्डिंग कम्पनी, जिसके विषय में भी इसमें अमेंडमेंट है और इसमें एक बड़ा अमेंडमेंट है कि पहले के प्रावधानों में 20 करोड़ रुपये का टर्नओवर करने वाली कम्पनियों का कम्प्लायंस सरल था, उसकी सीमा हमने 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सौ करोड़ रुपये कर दी है। इसका मतलब 100 करोड़ रुपये तक की कम्पनियां इसके सरल कम्प्लायंस के कैनवास में आ गई हैं। हमने श्रेश होल्ड लिमिट में कम्प्लायंस सरल करने का काम किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हं कि हमने सैक्शन-42 में संशोधन किया है, उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट में सिक्योरिटीज़ को ईज़ कर दिया है। यह भी एक बड़ा विषय समिति के सामने था। सैक्शन-230 के तहत जो रिओपनिंग आफ एकाउंट को रीड करता है, उसमें भी संशोधन किया गया है। पहले इसमें कोई सीमा नहीं थी। अब इसमें संशोधन करके आठ साल तक के खातों को रिओपनिंग करने का प्रावधान किया गया है। यह भी कम्पनियों को राहत देगा और ईज़ आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा। सैक्शन-96 के तहत जो अनलिस्टेड कम्पनियों को एनुअल जनरल मीटिंग रजिस्टर्ड आफिस में ही करना अनिवार्य था, अब इसमें प्रावधान किया गया है कि रजिस्टर्ड आफिस के अलावा भी आप एजीएम कर सकते हैं और यह कदम भी ईज़ आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाता है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि इंडिपेंडेंट आडिटर्स पांच साल के लिए और फर्म दस साल के लिए अप्रूव्ड होती थी। हर साल एजीएम में रेक्टीफाई करना पड़ता था, अब रेक्टीफिकेशन हटा दिया गया है। यह भी ईज़ आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है।

महोदय, कम्पनीज एक्ट में एक और संशोधन किया गया है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, वह हमने सेबी के साथ हार्मोनाइज किया है। मैं इनीशियल रिमार्क में कहना चाहता हूं कि सैक्शन 185 के तहत जो कॉमन डायरेक्टरशिप वाली कम्पनियों में 'ए' कम्पनी को 'बी' कम्पनी को लोन एलाऊ नहीं था, अब लोन एलाऊ कर दिया गया है। इससे बिजनेस करना आसान होगा। कुल मिलाकर ईज़ आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कम्पनीज अमेंडमेंट बिल, 2016 सदन के समक्ष चर्चा के लिए लाया गया है। सार्थक चर्चा के बाद इसके पास होने से ईज़ आफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बहुत बड़ा सुधार होने की संभावना है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल पर सदन चर्चा करे और इस कम्पनीज़ अमेंडमेंट बिल को पास करे।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAMEN DEKA): Motion moved:

“That the Bill further to amend the Companies Act, 2013, be taken into consideration.”

1411 hours

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Sir, as the hon. Minister himself has admitted in his introductory speech, this amendment is to dilute many of the stringent provisions of the Companies Act, 2013. The Companies Act, 2013 has been brought after 50 years. The Companies Act, 1956 was existing and in 2013, when this Act was brought, it was to amend and correct many of the anomalies in the then existing Act. The 2013 Act was brought in a context when we had a large number of scams like the Sahara scam, the Saradha scam. In order to prevent such scams in future, this 2013 Act was enacted. It was discussed many times. The present enactment and amendments are completely diluting the existing stringent regulations. For example, the 2013 Act permits the Central Government to impose a cap on layers of subsidiaries a company can have. This was a very stringent law. The Government proposes to dilute that amendment also.

The Government itself has accepted in the Statement of Objects and Reasons of 2013 Act that the Act introduced significant changes related to disclosures to stakeholders, accountability of directors, auditors and key managerial personnel, investor protection and corporate governance.

The Government itself has accepted that the 2013 Act was to prevent the malpractices existing in many of the private companies. However, the Government continues to say, Government received number of representations from industry Chambers, Professional Institutes, legal experts and Ministries and Departments regarding difficulties faced in

compliance with certain provisions. Amendments of the Act were carried out through the Companies (Amendment) Act, 2015 to address the immediate difficulties arising out of this. So, the Government has openly admitted that this amendment is to help private companies and private manufacturers and industries. What is the position in the country in the last 3 ½ years? This Government has been in power for the last 3 ½ years and they have made a lot of promises. The industrial production has come down from 75 per cent to 50 or 60 per cent. The Government admits this. Many of the major industries are going out of the country. For example, auto industry, General Motors. They are going out of the country.

(y1/1415/smn/vb)

Now, layoffs in many companies like IT is going up everyday. Now, the economy is slowing down. Only thing is that there is a hike in the stock market and everybody knows the reason that blackmoney is again coming back. The Government took a very important decision of demonetisation on 8th November, 2016. What the Government said and what the Prime Minister himself said:

“This is to check blackmoney; this is to prevent terrorism; this is to prevent Pakistan sending fake notes to us. ”

Sir, eight months have passed. Where are we? How much money has come back? Why is the Government hiding it? Many of the Committees of the Parliament have called the Reserve Bank Governor and asked him about the position. He still says that they are counting it. This shows where we stand economically.

Sir, in the 2013 case, how was this brought? In view of the changes in the national and international economic environment and expansion and growth of economy of our country, the Central Government, after due deliberations, decided to repeal the Companies Act, 1956 and enact a new legislation to provide for new provisions to meet the changed national and international economic environment and further accelerate the expansion and growth of our economy. This was the purpose of 2013 Act. The present amendment of 2017 should be an attempt to find what the faults are, to find remedial measures and if the Government's intention was in that direction, we would have definitely supported them. But if you go clause by clause of important amendments that the Government is bringing, one of it says that investments in the company cannot be made through more than two layers of investment. That was in 2013. What is the attitude of the Government?

Similarly, the memorandum must define the specific objects for which the company is being incorporated and other related matters. It permits the annual return for a one-person company or a small company to be signed by the Company Secretary or the bank. There are a large number of acts in the Companies Act, 2013. How the Government is going to handle it in the 2017 amendments? These are serious matters. For example, take the case of CSR. How the CSR of a company has to be decided? How it would be fully under the control of the Government? These are some of the issues which have been under discussion and deliberation.

Sir, my request to the Government is that it has to look at the problems of the poor, of the farmers and of the small traders. For example, in the case of GST, the hon. Finance Minister is here, what are we hearing from different parts of the country? The officers in the Finance Ministry are threatening the people in many parts of the country. Stories are coming out. So, when I had an occasion to talk to the hon. Prime Minister, he said the Government will ensure that the officers will not create problems in the country but the picture is quite different. This is something that the Government has to look into. I am not against GST because GST is one of our products. But at the time of implementation, the Government has to be careful.

Similar is the case of this Companies Act Amendment. The 2013 enactment came in the context of Sahara scam, Sarada scam etc. We have to find a solution to similar scams. Now, again everything has been thrown open. Everything is free. What are the private companies or multinational companies going to do in this country? So, I think the Government has to be serious about these amendments and see that the industry flourishes and employment is generated.

(z1/1420/mmn-pc)

But at the same time the corporate houses should not take undue advantage of the economic situation in this country. So that should be primarily in the mind of the Government.

With these words, I request the Government to consider these amendments properly. Thank you.

(ends)

1420 बजे

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने चर्चा के प्रारंभ में बताया कि मुख्यतः कंपनीज़ एक्ट, 2013 के संदर्भ में गत दो-तीन सालों में जो सुझाव आए, उनके लिए यह कंपोज़िट अमेन्डमेन्ट बिल लाया गया है। उन्होंने ऐसा प्रस्तावित किया।

माननीय मंत्री जी ने दो चीज़ों का उल्लेख किया है कि मुख्यतः, कंपनीज़ एक्ट का उद्देश्य इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन और कॉरपोरेट गवर्नेन्स था। मेरे सहयोगी और सदन के वरिष्ठ सदस्य कांग्रेस के थॉमस जी ने इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए यह अमेन्डमेन्ट लाते समय या कंपनीज़ एक्ट का एग्जिक्यूशन करते समय, कहीं इसमें कुछ त्रुटियाँ तो नहीं हैं, इसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सहारा स्कैम से लेकर शारदा स्कैम और अनेक पॉन्जी कंपनियों का उल्लेख किया।

मैं सब से पहले मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहूँगा। We certainly welcome and support 'ease of business', लेकिन 'ईज़ ऑफ बिज़नेस' का एग्जिक्यूशन करते समय 'ईज़ी फॉर बिज़नेस' और इस बिज़नेस की व्याख्या कहीं पर कैसी हो जाती है, मैं आज उसके दो-चार उल्लेख-उदाहरण देने वाला हूँ। एक चीज़ होती है - 'एक्ट' और दूसरी होती है उसका - 'एग्जिक्यूशन'। 'ईज़ी ऑफ बिज़नेस' जिस प्रकार होता है, उसके उदाहरण के रूप में थॉमस जी ने 4-5 कंपनियों के नाम दिए हैं। इस अमेन्डमेन्ट का सभी लोग स्वागत करते हैं। फाइनेंस कमेटी ने भी इसका समर्थन किया है। इस अमेन्डमेन्ट के दो-चार अच्छे उद्देश्य अर्थात् 'एनकरेजिंग स्टार्ट-अप्स' हैं। जब यह मूल एक्ट सन् 2013 में आया था, उस वक्त इसके स्टार्ट-अप्स की कल्पना ने इतनी प्रगति नहीं पाई थी। After 2014, when the Modi Government took over, the Prime Minister himself insisted on the new entrepreneur, the 21st century's entrepreneur, उनको बढ़ावा देना चाहिए। स्टार्ट-अप बिज़नेस के लिए इसमें कुछ अच्छे

सुझाव आए हैं- harmonising the law, easier management. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के संबंध में छोटे-छोटे स्ट्रिक्जेंट प्रोविजंस किए गए थे। छोटी-छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और एस.एम.ई. कंपनियों को इस कंपनीज़ एक्ट के एग्जिक्यूशन में तकलीफ हो रही थी। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मालिक, जो खुद लोन्स लेते और देते हैं, उसके संबंध में भी इसमें त्रुटियाँ थीं। इसके संबंध में अच्छे सुझाव आए हैं। हम इस अमेन्डमेन्ट का स्वागत करते हैं, लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक दूसरी बात की ओर दिलाना चाहूँगा। वास्तव में मैं आज डीमॉनिटाइजेशन पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। हमारे मित्र ने डीमॉनिटाइजेशन का उल्लेख किया है। डीमॉनिटाइजेशन के कारण कांग्रेस का बहुत डीवैल्युएशन हो चुका है। अब तो वह अपने खुद के अस्तित्व के लिए डीमॉनिटाइजेशन की चर्चा बंद करे। अगले चुनाव के लिए जिस व्यक्ति को वे प्रधान मंत्री का पर्याय मान रहे थे और उन्हें वह पद देने की बात कर रहे थे, वे भी उनके भ्रष्टाचार से कंटाल आकर इस ओर आ गए हैं।

(a2/1425/mz-san)

मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार का है। जो कंपनीज़ एक्ट 2013 बना उसमें भ्रष्टाचार किस प्रकार से पनपा, बहुत अच्छा स्ट्रिक्जेंट एक्ट था। स्ट्रिक्जेंट एक्ट के अंतर्गत गत सप्ताह वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि ‘around 12th July, 2017, we have deregistered or struck off 1,62,618 companies.’ Why did the previous Government not stop it up till 2014? Who registered these companies? क्या ये महज वर्ष 2014 या वर्ष 2012 में कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थीं? ये सब कंपनियां वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के दरमियान बनीं। इन कंपनियों का उपयोग कैसे हुआ, किसने किया, मैं उसका उदाहरण देने वाला हूँ। What is ‘ease of business’ and what is ‘easy for business’? What was the definition of business for the earlier Government? बोगस कंपनियां बनाओ, फेल कंपनियां बनाओ, बेनामी कंपनियां बनाओ और मनी लॉन्डरिंग के लिए जैसे चाहे वैसे उसको उपयोग करो। सरकारी प्रॉपर्टी एक

कंपनी से दूसरी में लेना, दूसरी से तीसरी में ले जाना और वहां से लाकर फिर राज्य सरकार के मुख्य मंत्री के परिवार के नाम पर वे कंपनियां रातों-रात ट्रांसफर हो जाती हैं।... (व्यवधान) रेलवे की प्रॉपर्टी, रेलवे के होटल, ईज ऑफ बिजनेस और ईजी फॉर बिजनेस, इसका थोड़ा अंतर समझ लो। पहले की सरकार ईजी ऑफ बिजनेस करती थी, **We want ease of business for SMEs, for genuine manufacturers and genuine industrialists. This is the difference between 'ease of business' and 'easy for business.'**

माननीय सभापति महोदय, कंपनियां किस प्रकार से बनीं। मैं आपको इसके एक-दो उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे पास यह सूची है। इसकी कंपनियां **Mishail Packers and Printers Private Limited is one of them.** मैं उनके बेनिफिशियरी के नाम नहीं पढ़ता हूं। उसे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। वह समाप्त हो गया है। आज तो शपथ विधि भी हो गई है। अब मैं आगे जाता हूं। मनी लॉन्डरिंग 8 हजार करोड़ रुपये का हुआ। क्या कोई पूछने वाला है? मैंने सुरेश प्रभु जी से पूछा कि इस प्रकार से रेलवे की प्रॉपर्टी दूसरी कंपनी के पास कैसे पहुंच गई। किसी व्यक्ति के नाप पर कैसे चढ़ गई। वह भी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हैं, मैं भी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हूं। उनको भी समझने में काफी सप्ताह लगे और मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया हूं।... (व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : आप पढ़े नहीं हैं।

डॉ. किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व) : हां जी, हम अनपढ़ हैं, वे पढ़े-लिखे हैं। मुझे सुरेश प्रभु जी ने कहा कि एक काम करो कि तुम्हारी एक पी.एच.डी. मुंबई यूनिवर्सिटी से है और अब दूसरी पी.एच.डी. बिहार की कंपनियों के ऊपर कर लो। अभी गाइड को फुर्सत मिल गई है और शायद अब टोटल ही फुर्सत हो जाएगी। तुम गाइड बना लो, तुम्हें अच्छा गाइड करेंगे। ... (व्यवधान) वह इमरजेंसी वाला मीसा, यानी जेल में... (व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : जब हम लोग जेले में थे मीसा वाले में, तो पैसा रखा गया था ... (*Not recorded*) में... (व्यवधान)

डॉ. किरिट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : वह ... (*Not recorded*) में आप गए थे, ये ईमानदार हैं।

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAMEN DEKA): Dr. Kirit Somaiya, please address the Chair.

डॉ. किरिट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक कंपनी और ये सब वर्ष 2013 के एक्ट के अंतर्गत फंक्शनिंग कर रही थीं। ये कंपनी वर्ष 2005 के बाद बनीं। उसमें आप देखें।

(b2/1430/ak-bks)

It is stated that : "... In a way, a relative converted black money into white by selling a share of rupee one at Rs. 10..." एक रुपये का शेयर दस रुपये में बेचा। It further states that : "... and repurchasing the same at Rs. 1.11 per share ...". एक रुपये का शेयर दस रुपये में और तीन महीने के बाद में... (व्यवधान) लेकिन यह कमाल तो हममें से किसी को नहीं आता है। हमारे मंत्री को इसे पकड़ना भी नहीं आता है। 7 लाख पचास हजार शेयर्स इस प्रकार से लिये गये, इसे टैक्निकल फाइनेंशियल लेंग्वेज में राउंड ट्रिपिंग कहते हैं और साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये, मैं अभी की बात कर रहा हूं, हमारे महाराष्ट्र के उस समय के उप-मुख्य मंत्री डेढ़ साल से जेल में हैं, मेरे महाराष्ट्र के साथी समझ जायेंगे। उन्होंने जिन कंपनियों में मनीलांड्रिंग की, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वेनु इंफ्रा प्रोजैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, आशीष प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, गुड वैल्यूज टाप ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, स्वप्न सुंदरी होल्डिंग एंड ऐस्टेट डैवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और फर्स्ट ग्रोथ प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ये जो सब कंपनियां हैं, इनमें जिन्होंने मनी लांड्रिंग की, ई.डी. ने उन्हें अरेस्ट किया, वे वहां से सुप्रीम कोर्ट तक आए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी, डेढ़ साल से जेल में हैं। मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इन कंपनियों में जिन बाकी लोगों ने मनी लांड्रिंग की है, क्या ई.डी. उसकी जांच करेगा, क्या इंकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी जांच करेगा? चाहे कोई भी हो, किसी का

साला हो, किसी का श्वसुर हो, चाहे वह मुम्बई वाला हो या दिल्ली वाला हो या बिहार वाला हो। मंत्री महोदय आप और मैं राजस्थान घूमते थे तो राजस्थान वाला भी साला-बहनोई हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जिन्होंने इस प्रकार से मनी लांड्रिंग की है, उन सब कंपनियों की मैं बैलेंस शीट लेकर आया हूँ और इनमें किसने-किसने मनी लांड्रिंग की, यह सब जब आप चाहोगे, मैं ये डाकूमैन्टरी एविडेंस आपको देने के लिए तैयार हूँ। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : आप इनके बारे में बोलिये।... (व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : क्या मैं एक-एक नाम बोलूँ?... (व्यवधान) कुछ मेरे मित्र आपकी पार्टी में भी हैं, क्योंकि इसमें कोलकाता की कंपनियां भी शामिल हैं।... (व्यवधान)

महोदय, मैं संकट महसूस कर रहा हूँ। मेरे मित्र, हमारे सीनियर सदस्य कह रहे हैं, कुछ मेरे मित्र उनकी पार्टी में भी हैं और इन कंपनियों में जिनका शारदा चिट फंड में मनी लांड्रिंग हुआ है, उन कंपनियों के नाम भी इन कंपनियों की सूची में हैं। वह कहेंगे तो मैं अभी एक-एक नाम बोल दूंगा और उसके बेनिफिशियरीज... (व्यवधान) मेरे पास पांच सौ कंपनियों की सूची है। एक नम्बर से लेकर एडीए, एग्जिम से लेकर आदाम विनकॉम से लेकर आकाश फाउंडरी से लेकर 529 कंपनी जिंग मर्चेट प्राइवेट लिमिटेड ... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I have a Point of Order. ... (*Interruptions*) Sir, I am raising a Point of Order. ... (*Interruptions*) This is a discussion on The Companies Bill. While participating in the discussion on this Bill the hon. Member, Dr. Kirit Somaiya, is pointing out and through his speech making insinuations. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly mention the Rule No.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): There was a hawala scandal in Kerala BJP. Are you aware about that also? There was a big

news about it, and your Party has investigated the matter. An amount of Rs. 5.5 crore was sent to Delhi. Who is taking that money? ...

(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, Dr. Kirit Somaiya, please continue.

... *(Interruptions)*

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Let us talk about that also.

... *(Interruptions)*

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, मेरे मित्र अगर जांच कराना चाहते हैं तो केरल में हमारा एक ही विधायक है।

(c2/1435/gg-spr)

कल तक आपकी सरकार थी। आज से हमारे मित्र कम्युनिस्टों की सरकार है। वहां तो भारतीय जनता पार्टी का इतना ही काम है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इतने ही स्वयंसेवक हैं। ... (व्यवधान) लेकिन एक जन को काम करने नहीं देते हैं। उनसे इतना डरते हैं कि कितने ही कार्यकर्त्ताओं और स्वयंसेवकों की हत्या की जाती है। तीन सौ से ऊपर की हत्या की जा चुकी है। अभी इतना घोटाला, जैसे मैंने कहा कि यह 529 कंपनियों की लिस्ट जब भी माननीय मंत्री महोदय कहेंगे, मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। कोई राज्य का उप-मुख्य मंत्री है तो कोई मुख्य मंत्री है तो कोई अभी का उप-मुख्य मंत्री है। यह जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ी फॉर बिज़नेस है, मैं एक और चीज़ के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो इनवेस्टर्स प्रोटेक्शन की बात की है my Ph.D. was on non-investor protection. मंत्री महोदय, कंपनीज़ एक्ट के एग्ज़िक्युशन के बारे में जिस प्रकार से आपने यह प्रोविज़न किया है, I supported that provision. जो प्राइवेट इनवेस्टर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट का इस प्रकार का दुरुपयोग होता होगा तो आपको

सावधान रहना पड़ेगा। आज आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में ऑन-लाइन एप्लिकेशन करो, आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। **There is no due diligence. We have to pay attention. We have to correct that system.** आपको पासपोर्ट चाहिए, दस धक्के देने पड़ते हैं, पचास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसिस देने पड़ते हैं। राशन कार्ड चाहिए, पचास डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस के कारण इस प्रकार की स्थिति होगी, यह नहीं पता था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एल्डर फार्मा नाम से मुंबई की एक फार्मास्युटिकल कंपनी है। हमने इस पर डिपॉज़िट लेने के ऊपर थोड़ा सा ईज़ी किया, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपके पास कितनी शिकायतें आती हैं। छोटे-छोटे निवेशक कंपनीज़ में डिपॉज़िट रखते हैं। कंपनी दिवाला निकाल देती हैं। उसके बाद ये बेचारे दस साल इंतजार करते हैं। **I would refer to the CAG Report which was presented in Lok Sabha on 10th March, 2017 – Report No.2, Chapter No.5 – fictitious sales and purchases by shell companies and hawala operators.** हम राजनीति में हैं, हमारे राजनीतिक मतभेद होंगे, उनकी चर्चा जरूर करें, लेकिन इन फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले लोगों से हम सबको मिल कर लड़ना चाहिए। मैं इसमें इतना आश्चर्यचकित हो गया कि एल्डर फार्मा ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम डिपॉज़िटर्स को पैसे नहीं देंगे। वित्त मंत्री को मैंने पत्र लिखा, शिकायत भेजी, माननीय अरूण जेटली जी का जवाब 14 दिसंबर, 2015 को आया कि एल्डर फॉर्मास्युटिकल के विरुद्ध शिकायत आई है। उसके बाद में कंपनी अफेयर्स सैक्रेट्री का जवाब आया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 03 फरवरी, 2017 को **Liquidator is appointed.** उसके बाद लिक्विडेटर का जवाब 19 जनवरी, 2017 को आया। इनवेस्टर्स की इतनी सारी शिकायतें मैंने भेजीं। अब आपको आश्चर्य होगा कि जो सीएजी ने रिपोर्ट प्रेज़ेंट की है। 35 कंपनियों का एक-एक उदाहरण उन्होंने दिया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शैल कंपनीज़ बना कर हवाला ऑपरेटर्स, शैल कंपनीज़ और उसके द्वारा किस प्रकार से फ्रॉड किया जाता है, फिर चाहे वह कोलकाता की हो या मोरिशियस बेस्ड हो या मुंबई, दिल्ली बेस्ड हो। एक ओर

सरकार को लूटते हैं, दूसरी ओर छोटे निवेशकों को लूटते हैं। इस एल्डर फार्मा की 700 करोड़ रुपये की डिपॉजिट डिपॉजिटर्स को नहीं दी और सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने, वैट डिपार्टमेंट ने ऐसी 2000 कंपनियों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाली है। इन 2000 कंपनियों ने, खोका कंपनियों के पास से खोटे परचेज़ बिल लिए और वे अपने अकाउंट में लगाए। It amounts to Rs.30,000 crore. 30 हजार करोड़ रुपये खोटे खर्चे दिखाए। इसके कारण इनकम टैक्स इतना बचा, खोटे बिल अकाउंट किए, प्रॉफिट कम किया और डिपॉजिटर्स के पैसे डुबा दिए। एल्डर फार्मा कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। इसमें सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एल्डर फार्मा ने दो बोगस बिल के द्वारा 77 करोड़ 40 लाख रुपये बोगस बिल अकाउंट कर के बाहर निकाल दिए। डिपॉजिटर्स के पैसे नहीं दिए जाते हैं।

(d2/1440/cs-sr)

सीएजी ने लिखा है कि ईडी और इन्कम टैक्स ने इस विषय में, जो महाराष्ट्र सरकार ने वैट के ऊपर जो दो हजार कंपनीज कीं और वैट बोगस, उनका वैट आउट प्रूव हो गया है, कोर्ट में एप्लीकेशन रिजेक्टेड, लेकिन इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी को भी उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यह सीएजी रिपोर्ट और उसकी जानकारी टेबल पर रखना चाहूँगा।

महोदय, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि यह जो अच्छा बिजनेस है, लेकिन आखिर में यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ए गुड बिल, ईज़ ऑफ बिजनेस, लेकिन पॉजी कंपनियों को बढ़ावा न मिले, यह भी ध्यान देना पड़ेगा। जो मान्यवर वित्त मंत्री ने बजट सेशन में कबूल किया था, वचन दिया था कि वर्ष 2016 के बजट में कि एंटी पॉजी कानून लाया जाएगा, वह बिल लगभग बनकर तैयार है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि 1998-99, when I was in this House, at that time, I had introduced this subject. तभी से केन्द्र सरकार कह रही है। वर्ष 2003 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्र स्तर पर एंटी पॉजी एक्ट बनाया जाएगा। आज 2017 हो गया है। आपने बजट में वचन दिया है तो आप जल्दी वह बिल इंट्रोड्यूस करो और एक ओर आप बिजनेसमैन को राहत दीजिए और दूसरी ओर छोटे इन्वेस्टर्स का रक्षण कीजिए। (इति)

1442 hours

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Thank you, Sir. I wish to express my gratitude to our immortal leader Puratchi Thalaivi Amma and thank you for allowing me to speak on the very important Companies (Amendment) Bill, 2016.

As on 31st December, 2016, a total of 16,13,371 companies were registered in the country. Of them, 11,43,131 companies were active and the rest were inactive. Of the active companies, there are 10,77,398 private companies and 65,733 public companies engaged in under four broad heads, namely, business services, manufacturing, trading and construction. Business services include hardware and software, data processing, research and development, legal, accounting and audit services, business and management consultancy, entertainment and advertising etc. Manufacturing companies include food products, textiles, paper, metallic/non-metallic mineral products, chemicals and petrochemicals, radio, television, mobile phones and communication products, transport equipments etc. The total authorized capital of these companies is around Rs.53 lakh crore.

The Companies Act was enacted and enforced on 12th September, 2013 which replaced the old Companies Act of 1956. The Act was brought in to address the loopholes and discrepancies that were present in the old Act. Since then, the Act has been amended *vide* the Companies (Amendment) Act, 2014 and the Companies (Amendment) Act, 2015. The Companies (Amendment) Bill, 2016 was introduced in the Lok Sabha on March 16, 2016, to further amend the Act. It was

referred to the Standing Committee on Finance on April 12, 2016 and the Committee submitted its 37th Report on December 6, 2016. In April 2017, the Government circulated certain amendments to the Bill.

The Bill amends the Companies Act, 2013 in relation to structuring, disclosure and compliance requirements for companies. The Act of 2013 permits the Central Government to impose a cap on layers of subsidiaries that a company can have. But the Companies (Amendment) Bill, 2016 removed the restrictions on the number of layers of subsidiaries of a company. The amendments to the Bill, 2016 restores, the provision in the Act of 2013 and permits the Central Government to impose a cap on layers of subsidiaries of a company.

With regard to the cap on investments through layers of companies (Section 186) under the 2013 Act, investments in a company cannot be made through more than two layers of investment companies. The amendment in the Bill of 2016, removes the restrictions on number of layers of investment companies. Now, the Government restores the provision in the 2013 Act and prohibits investments in a company through more than two layers of investment companies.

As far as the objects of the company are concerned, it was recommended by the Standing Committee on Finance that the amendments in 2016 Bill may lead to the creation of bogus entities and *status quo* should be restored.

(e2/1445/ub-hcb)

The recommendations are accepted. It is required that the Memorandum is to define the specific objects for which the company is being incorporated.

A simple form of annual return may be prescribed for small companies, one-person companies and private companies with less than annual sales turnover of say, Rs. 100 crore. This may apply to other forms of companies as well to avoid repetitive information. The Government has accepted the recommendations of the Standing Committee. The amendment extends the power of the Central Government to prescribe abridged form of annual returns for other types of companies, in addition to one person company or a small company.

As far as the annual financial statement (Section 129) is concerned, the amendment prescribes for a company to attach a separate financial statement of its associate companies, in addition to that of its subsidiaries. For financial statement of foreign subsidiary (Section 137), every company is required to file a copy of its financial statement with the Registrar along with the accounts of subsidiaries incorporated in foreign countries.

If the accounts of foreign subsidiaries are not required to be audited under the local law, companies need to make a special declaration stating the same. This applies only for public listed companies. It was recommended that such a provision should be applicable to all companies, and not just listed public companies.

With regards to late filing, the 2013 Act gave the companies 270 days of upper time limit. The amendments remove the time limit for filing of documents under the Act. For non-filing of documents under Section 92 (filing of annual return) and Section 137 (filing of financial statements), a minimum fine amount of Rs. 100/day has been specified. Further, the company shall be liable for penal action. If a company defaults on submitting the documents for two or more times, the fees levied on the company may be doubled. The imposition of fines on late filing may not fetch desired results in many small companies and perhaps detrimental to the survival and growth of smaller companies. It is, therefore, desired that the provisions of the 2013 Act should be restored.

In calculation of profits to provide dividends (Section 123), the company should declare or pay dividends only out of the profits of the company. The amendments add a proviso which, in computing profits, excludes: (i) any unrealised or notional gains, or (ii) revaluation of assets and any change in carrying amount of an asset or liability.

With regards to the loans to directors of companies (Section 185), a company is not allowed to advance any loan to its directors or to any person in whom the director is interested. The Bill 2016 allows the companies to advance a loan to any person a director is interested in if the company passes a special resolution to this effect.

The amendments proposed by the Government provide that if loans extended are used against certain conditions, in addition to the company and its directors, every defaulting officer in the company may

also be imprisoned or fined. The amendment proposed deletes the provision that provides power to SEBI to enforce the insider trading and forward dealing provisions of the Act.

The Bill permits an independent director to have a pecuniary relationship up to 10 per cent of his total income with the company. Currently, there are restrictions on loans that can be provided to a company by its director or their relatives. The restrictions are based on factors such as net worth of the companies. The loans from directors are major source of funding for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Restrictions on these loans are restraining the finances and growth of MSMEs. The restriction on loans from directors should be reduced to promote growth of MSMEs.

Currently, every company is required to file a copy of the financial statement with the Registrar, consisting of details regarding balance sheet, cash flow and profit and loss statements, etc. Further, companies are required to attach accounts of subsidiaries which are incorporated in foreign countries. The Bill requires that if the accounts of such subsidiaries are not required to be audited under the local law, companies need to make a special declaration stating that. However, the requirement applies only for public listed companies. The Committee recommended that such requirement should hold to all public companies.

The Bill also seeks to set a limit on the reopening of accounts of a company.

(f2/1450/kmr/rv)

The Bill suggests that the accounts of a company prior to eight years from the date of examination must not be reopened. This will be a great relief to companies as they will not have to carry on the cumbersome task of maintaining books of accounts for several years as they currently are required to.

Before I conclude, I would like the Union Government to make more provisions and provide powers to the Central and State Governments as well as elected representatives to involve, suggest, recommend and monitor the annual allocation and spending of the public and private sector companies under the corporate social responsibility.

Thank you, Sir.

(ends)

1451 hours

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Companies (Amendment) Bill, 2016.

I did not want this debate to be a bipartisan debate or a partisan debate. I wanted this to be a general discussion on the problems faced by the companies. Very often in recent times problems regarding companies have come up. We had the collapse of the Satyam Computers. We had the history of ponzy companies. In recent times what we are hearing very much is about the shell companies that have been floated post demonetization.

Our hon. Shri Kirit Somaiya brought up many issues including Elda pharmaceuticals. My request to him would be to directly go to the Minister instead of raising it in Parliament. In the Corporate Affairs Department there is the Serious Fraud Investigation Office (SFIO). If somebody has done something wrong, let the Government take action through the SFIO. We the opposition people will raise this issue in Parliament. People belonging to Ruling Party can always approach the Minister, talk about things in the party meetings. I do not know why hon. Shri Somaiya decided not to take that route.

Hon. Shri Somaiya spoke about demonetization. He says that demonetization has been proved to be correct because of UP elections. It is strange to relate one thing to another. They may say lynching of people by *Gorakshaks* is also related to victory in UP election. These are entirely different issues.

The bad effects of demonetization are being felt now. In the first quarter of 2017, the GDP has already gone down by one per cent. Small industries have been destroyed altogether. We have been trying to repeatedly find out how much money has been deposited in the banks till today after demonetization. The Reserve Bank Governor has not been able to say how much money was deposited in the banks after demonetization. So, I do not want to go into those matters.

As I said earlier, it should not be a partisan debate because the Companies Act which was passed during UPA-2 regime in 2013 was the result of a long discussion. The Bill was introduced in 2011. Then it went to Standing Committee. In 2013, Shri Veerappa Moily was the Minister and Shri Sachin Pilot became the Minister who piloted the Bill. That Bill brought a whiff of fresh air because the old Companies Act, 1956 was outdated and was not competent to deal with a liberalized economy. So, the 2013 Act was very much appreciated by business circles. When the NDA came to power in 2014, obviously it was a new Government and they wanted to do something. Many people represented to them about problems being faced in the implementation of the Companies Act, 2013.

(g2/1455/gm-my)

Out of 470 sections of the Companies Act 2013, 284 sections were already implemented and the National Company Law Tribunal has now been set up. So, there is no problem, but still when businessmen and Chartered Accountants went to the Minister of Finance Shri Arun Jaitley, he first brought in an amendment in 2015.

That amendment was discussed in the Rajya Sabha which gave certain suggestions on it. At that time, the Government set up a Committee called the Company Law Committee comprising Chartered Accountants, Cost Accountants, Company Secretaries and a former High Court judge under the chairmanship of Secretary of the Ministry of Corporate Affairs.

The Committee submitted a report to the Government. Then the Government introduced the current Bill in 2016. It came to the Standing Committee on 12th April 2016. I am a member of this Standing Committee. So we deliberated on the new Bill and we met FICCI, CII, ASSOCHAM, Chartered Accountants, Cost Accountants, Bombay Chamber of Commerce and Industry and then the Standing Committee gave a report under the Chairmanship of Shri M. Veerappa Moily.

It is in line with that report that the present Bill has been brought in. So, I cannot really object to the structure of the present Bill. The only thing I am happy about and for which I want to thank Shri Jaitley is that today he has left it to Shri Arjun Ram Meghwal to pilot the Bill and he himself is absent. Shri Mehgal was a very vocal Member of Parliament but after having become a Minister of State, he does not get so much time to speak. So, today he will be piloting the Bill and maybe replying to our queries etc. So I welcome him in this role.

What are the specialities of this new Companies Bill? The main object is to improve the ease of doing business so that people who want to start a start-up or a one-man company do not have to go through so

many formalities, so many disclosures, so many filling up of forms. So, the idea is to make the law simple so that only lawyers do not benefit but the companies also benefit. That is why this law has been brought.

The amendments proposed are expected to simplify the disclosure and compliance requirements for companies. The example is doing away with the requirement of Government approval for managerial remuneration and replacing it with approval through a special resolution by shareholders in a general meeting. It is a good addition. The Bill has also suggested simplifying the format of the Board's report and recommended avoidance of repetitive information. The requirement of filing an extract of annual return as part of the Board's report has been removed. Exemption has been provided for uploading individual financial statements of step-down foreign subsidiaries by listed holding company where consolidated financial statements have been prepared by foreign subsidiaries according to the laws of the relevant foreign countries.

In the interest of transparency and fairness, guiding principles for determination of penalties have been introduced such as size of company, nature of business etc. To encourage start-ups, the amendment Bill proposes several incentives to start-ups and small companies, pre-conditions for a company to be considered 'small' have been relaxed and so has the format of Board's report and annual return for one person companies or small companies.

(h2/1500/rsg-nk)

The fines for non-filing of statutory annual filings have been significantly reduced. They have been provided more avenues to raise funds. This is also a good thing for start-ups.

One problem is of harmonising laws. There is a Companies Act; there is also a SEBI Act for the Securities and Exchanges Board of India. They overlap. An effort has been made now to remove that. The resultant ambiguities of an overlap dissuade companies from complying with relevant laws. The amendments are geared towards doing away with dual requirements, especially in the context of separate prescriptions for prospectus and the contents of the board report; the provision of prohibition on forward dealing and insider trading has been omitted since those are relevant for listed entities which are already regulated by SEBI. So, there is no need for keeping them in the Companies Act. The unlisted companies will also now be allowed to convene annual general meetings in any place in India, not necessarily at the place of their registered office.

The Bill has empowered the Centre to exempt any class of foreign companies from the applicability of registration and other requirements provided in the Act. I do not know if this is an unmixed blessing. I have a slight antipathy towards foreign companies because they often put money in and take it out. We have no control over that.

1502 hours (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

The Bill attempts to address the provisions that were criticised on the grounds of being onerous, relaxing the restriction on number of

layers of subsidiaries as a much needed step towards giving companies greater freedom in the way they structure themselves.

This Amendment Bill will remove many ambiguities from the current law and streamline its provisions with other relevant laws. I want to mention something here. Earlier I mentioned about the Company Law Committee which was set up by the Government. Certain recommendations of the Company Law Committee have not been incorporated in the Bill. These include issues related to resident requirement of directors and compliance requirement for dormant companies.

The new restriction will prevent a company from attracting a talented individual residing outside India. The CLC recommended that the residence requirement for a foreign national should be removed but that has not been done. Under the Act of 2013, any company without transactions for the previous two years may apply to obtain the status of a dormant company. The Act of 2013 does not exempt such dormant companies from the requirement of constituting committees. The Company Law Committee suggested that the dormant companies may be exempted from constituting an audit committee as they have no business activity or employees.

Lastly I want to say that the Supreme Court upheld the constitutional validity of the National Company Law Tribunal. However the Court held certain provisions in relation to the qualification of the technical members of the NCLT and composition of the selection committee for appointment of technical members of the

NCLT and the National Company Law Appellate Tribunal as invalid. This Bill has modified those provisions to bring them in line with the Supreme Court's decision which is a good thing.

(j2/1505/rk-sk)

To end, we want good corporate governance in India because as the economy expands and is liberalised, it is not only necessary to have proper regulation but also allow companies the freedom to grow, invest and attract investment. The intention of this Bill is to improve the ease of doing business. We shall have to pass the Bill and then see what response we get from the corporate world. I hope that Shri Arjun Ram Meghwal, who is looking after the Corporate Affairs Department, will use the powers of the Department to really save people. A number of people have sunk their money in companies which did not pay back their depositors. Companies have raised money in so many fraudulent ways and so the need of the hour is to see that the common citizen of India is free of all this encumbrance. With this, I end my speech on the Bill. Thank you.

(ends)

1506 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Chairman, Sir. I start from where Prof. Roy ended.

In India we have seen a large number of fly-by-night companies. We have seen companies being floated to do plantation and hardly a tree has been planted, yet money has been taken and they have just evaporated. We have seen during the last five or ten years one of the major concerns of every enlightened citizen of this country was why could the Government not do something about it.

Today, we have a Minister looking after the corporate affairs who very much has his feet on the ground. Not only he has his feet on the ground, he also travels to a place, which has not been visited by any public representative during the last 70 years, and calls for a ladder so that his mobile can be connected. That made him very famous throughout the country. Anyone who looks at him says यहां तो ये लैडर मिनिस्टर हैं। Sir, you have actually not only magnified the problem of your constituency, you have also magnified the problem that the Ministry is facing in remote parts of our country.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय सभापति जी, महताब जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं रेगिस्तान से आता हूँ, इन्होंने धौलिया गांव का जिक्र किया, यह श्रीडुंगरगढ़ तहसील का गांव है। 70 साल में यहां कोई मंत्री नहीं गया। मीडिया ने एक प्रोजेक्ट लिया कि क्या इस गांव में कोई मंत्री जा सकता है। मैंने चैलेंज स्वीकार किया। मीडिया का एक चैलेंज और था कि धूप में 12 से 2 बजे के बीच ही जाना है जब टेम्परेचर 49-50 डिग्री था। मैं उस दिन गांव में गया, दो घंटे रुका, उन्होंने कहा था 12 से 2 बजे तक रुकना है। वहां सारी बातें हुई कि क्या

एमपीलैड देंगे या और क्या करेंगे। यह गांव बहुत छोटा था, ग्राम पंचायत मुख्यालय भी नहीं था। गांव वालों ने कहा कि आप इस गांव में पहली बार आए हो, आप एक काम कर दो, हमने 70 साल में कोई नर्स नहीं देखी। मैंने कहा कि यह काम तो मैं कर सकता हूं, मैंने कहा कि सीएमएचओ को फोन करो, तब उन्होंने कहा कि फोन यहां नहीं लगता है। मैंने कहा कि आप कभी फोन लगाते हो, उन्होंने कहा कि हम फोन कभी लगाते हैं, एक टिब्बा है, यहां एक पेड़ है, उस पर चढ़ते हैं। मैंने कहा कि कल कर दूंगा। वे कहने लगे कि आप हमें धोखा दे रहे हैं, अगर आप हमारे जन प्रतिनिधि हो, जैसे हम फोन करते हैं आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा कि अगर यहां फोन लग गया तो ठीक है। मैं यहां जाकर सीएमएचओ को फोन कर रहा था। 70 साल से यहां सैन्ड ड्यून हैं, कोई गया ही नहीं और मोदी सरकार तो तीन साल से ही है। यहां 70 सालों से कोई नहीं गया, इसे आप एप्रिशियेट कीजिए। जब मैंने फोन लगाया, तो उस गांव में दूसरे दिन ही नर्स आ गयी। आप यह भी एप्रिशियेट कीजिए।

(k2/1510/rjs-ps)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, I was just mentioning that we have now a Minister of Corporate Affairs who has his feet on the ground. I was appreciating the effort made. But, I would also like to know this. Do you have a ladder in your quarter here? कॉल ड्रॉप की ज्यादा प्रॉब्लम दिल्ली में होती है।

Now, I come to the issue of The Companies (Amendment) Bill, 2016. I would mention here that 'yes' on earlier stages, during the UPA regime, this Bill came before this Parliament. This Amendment was moved in the Parliament on 16th March, 2016.

The Standing Committee deliberated with the Government and stakeholders like The Institute of Chartered Accountants of India, FICCI, ASSOCHAM, CII, etc., and with the representatives of the

Institute of Company Secretaries of India, Bombay Chamber of Commerce, Indian Merchant Chamber, Investor's Grievances Forum, The Chamber of Tax Consultants and NASSCOM, etc. The report was submitted to the Parliament on 1st December, 2016.

One curious aspect of this Companies (Amendment) Bill, 2016 is that when Dr. Moily was the Minister for Corporate Affairs, the Companies Bill, 2009 was introduced in the Lok Sabha. The Standing Committee on Finance examined it and submitted its Report on 31st August, 2010. The Ministry examined the Report and out of 178 recommendations made by the Committee, 167 were incorporated fully, six were partially accepted and a different view was taken by the Ministry on the rest five recommendations. In 2011, the revised Bill was introduced and again it was referred to the Standing Committee on Finance by this august House to look into it. The report was presented on 13th August, 2012 and out of 15 recommendations, 13 were accepted by the Government and a different view was expressed on the remaining two recommendations. Therefore, one may say that out of 193 recommendations, 180 were accepted fully. This shows the enormity of the problem that our old Companies Act of 1956 was facing. The Committee had recommended around 193 recommendations, out of which, 180 were accepted.

There have been a host of changes in the present Bill. It is because this is the third attempt of correcting the Act of 2013. This Bill seeks to simplify private placement process, remove restrictions on layers of subsidiaries and investment companies, amend Corporate

Social Responsibilities provisions to bring greater “clarity.” Today, out of 470 sections of the Companies Act of 2013, 284 have come into effect since 1st April, 2014. Now, new amendments are to be effected and therefore, we have this Bill before us for consideration.

Hon. Chairperson, I would say the process of fine tuning the Companies Act of 2013 seems to have no end. It is because even today a large number of corporate bodies are still saying that there is a need to have further amendment to the amendments that have been made by the Government. Should we continue to do amendment of this Companies Act, again and again?

(12/1515/rc/rps)

It was in 1956 when this Act was promulgated. We amended it in 2013. Now every time and every year whenever the corporate people meet, they say that there is some flaw in this Act and we need amendment. To tide over this situation, a committee was formed when this new Government came into being. They gave certain suggestions and those suggestions have been incorporated in this Bill and some suggestions have not been accepted by the Government in its wisdom. But should we go on amending the Act like this? That is the first question.

As I said earlier, more than 200 changes were incorporated over a period of five years. Now based on a Government-appointed panel’s report, 100 odd amendments to the Companies Act of 2013 are under discussion. Even day before yesterday, another 48 amendments have been moved by the Minister. The aim is to make it easier for the

companies to do business including simpler laws for incorporating a company, for raising funds as also for insider trading and dealing with top executives.

It is interesting to note that even as various amendments to the Companies Act were passed in the Budget Session year before last, industries still have concerns over some provisions and now the Government has again come to us with amendments.

As I have reiterated earlier, the Government is only interested in economies and money. The social fabric of the society that keeps businesses together is being torn apart. You can see the result of the hostile attitude of the Government yourself since lending by banks is at five per cent which is a 60 year low. Some may say that it is because of demonetization but the fact today is that it is a 60 year low and it has come down to five per cent. Banks are flushed with money but people are not taking money from the banks. The economy is practically stagnant today. Jobs are being lost and yet the Government insists on living in an imaginary city where buildings are made of gold.

On the one hand, the Government violated individual privacy and on the other hand, it gives more anonymity to corporates. Corporates are legal persons. They can enter into contracts, take loans and do business. People who run these corporates are not held responsible for any loss that the company makes but the burden is distributed among the shareholders. That is how, it has been since the Mauryan Empire where such entities were also present but this corporate veil of secrecy offered by the corporates is also prone to misuse.

What has happened today is that the Kingfisher will take a loan of around Rs.7000 crore and it will not pay it back. It gets a pay off from the United Breweries of Rs.515 crore, severance package. There is something, I would say which the House should ponder over. There is something very wrong with our system if things like this are allowed to happen.

The Economic Survey this year pointed out that top ten Companies in India owe Rs.40,000 crore each to the banks. The Directors who run these Companies are living lavish lives at the cost of the Company while the corporate itself is going on many misadventures.

In April last year the Supreme Court was given an envelop by the RBI regarding big defaulters in the country. An argument was made that these names should be kept confidential since it would impact our economy. It is incredible that artificial and fictional persons have more rights in India than individuals today.

On the one hand, you have brought this Bill which removes subsidiary company caps, investment layer caps, diluting requirements to have an objective clause while on the other hand, you keep imposing Aadhar on the citizens of this country.

(m2/1520/snb-asa)

Sir, the Finance Bill, 2017 went a step ahead and allowed anonymous corporate donations to political parties. The Government is going on over-drive to give more powers to institutions that are not accountable to the public while taking away the freedom of the public.

Sir, this Bill allows some pecuniary interest in companies for independent Directors. Here I would say this because this is one of the major provisions of this amendment today which the Government is dealing with relating to appointment of independent Directors with transactions up to 10 per cent with the company. Section 149 of this Bill allows an independent Director to have 10 per cent pecuniary benefits with the company where he or she holds a position. The earlier Act did not allow any personal interest to interfere in the business. This Bill is allowing it. Not only does it allow pecuniary benefits, it also leaves it to the executive to decide the percentage of interest. This goes completely against the concept of corporates as independent entities. This will be misused by the likes of Shri Mallya to lead an even more comfortable life than they already have, while the companies continue on their misadventure. This should not be allowed at all. While India has to catch up quite a bit on its record of independence of Directors, most of the problems of the corporate sector and that of the banking sector can be traced to poor corporate governance. When corruption, nepotism and crony capitalism are eroding the foundations of our institutions in India, change in a law which determines independence of Directors, even if justified for pragmatic reasons, should not be espoused. While India largely escaped the adverse effect of 2008 melt down in the wake of the sub-prime mortgage crisis, the crisis in India which is threatening to explode may be solved in the medium and large term only through a robust model of corporate governance, both in the banking sector as well as in the corporate sector.

Sir, in the light of the Satyam scam, the Company's Act 2013 introduced new rules to improve audit quality and to punish auditors who will be found guilty of negligence or connivance with the management in acts of omission and commission by the company. Will this be effective? I would like to get an answer from the Government. For business reasons auditors have strong motivation to approve client's financial statements because an unfavourable report might lead to losing the client. The Company's Act stipulates that the auditor has to be appointed for a term of five years and they can be removed only by passing a special resolution in a shareholder's meeting and with the approval of the Government. This has reduced the risk of losing the client, yet audit partners act as an agent of the firm in securing non-audit businesses from the client and therefore, there is motivation to appease the client. This needs to be corrected.

Sir, the process of fine-tuning the Company's Act, 2013 seems to have no end, but the process to make a perfect law seems to be never ending. I would come to my last point. There are certain shortcomings in this Bill. Amongst the problematic provisions of the 2013 Company's Act which have not been redressed by the amending Bill are the provisions contained in Sections 203 which requires every company of a certain size to have at least three classes of key management personnel.

(n2/1525/ru-raj)

This has been one of the most impractical provisions of the 2013 Act requiring companies to perfunctorily designate Chief Financial

Officers and Company Secretaries in companies which have significant capital but do not have day-to-day business. There was a widespread demand that either such companies may designate the same person to look after several positions or the same person to look after several companies. However, nothing has been done to introduce amendments in this section although the definition of 'key managerial personnel' in section 2(51) has been widened.

Another significant difficulty created by the 2013 Act was the unduly restrictive set of provisions pertaining to private placements. This over ambitious scheme of regulation was a direct result of some incidents in the past which I mentioned about Satyam. One such provision requires every private placement to be routed through a separate bank account opened for this purpose and a bar on utilisation of the money until allotment. While the Bill rewrites the entire section 42, it in fact, bars the use of money until the return of allotment has been filed with the Registrar of companies. It is curious to note that the use of the money has been linked with filing of a document for which the time allowed is as much as 60 days for allotment and 15 days for filing the return. More often than not, the amount received in private placement is large and companies cannot afford to keep the amount idle even for a day. The only relief in the private placement provisions seems to be that the amount of penalty for contravention has been limited to Rs. 2 crore which was earlier seemingly extending to the entire amount raised by private placement.

Sir, with your wide experience, you know that law is as good as it is administered. The Companies Act, 2013 is a modern law for a rising India. It is important that the administrators of such a law have a mindset keeping with the spirit of such a law. Unless transformative changes are brought about in its administration, the felt purpose of such a law would be lost.

Therefore, we should address this issue effectively so that India becomes a beaconing economy of the world.

(ends)

1523 hours

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I rise to support the Bill moved by the hon. Minister for Corporate Affairs, Shri Meghwal. Nearly 90 amendments proposed in the Bill are mainly in pursuance of the recommendations made by the Company Law Committee and based on the recommendations made by various industrial bodies, industries and professional organisations.

This House itself passed the Companies Bill in 2013 and out of 470 Sections, so far, only 284 have been notified and the remaining are relating to National Company Law Tribunal and National Company Appellate Law Tribunal. They could not probably be constituted earlier since the matter was *sub judice* but a five judge Constitutional Bench of the Supreme Court approved the constitution of NCLT and NCLAT in 2015 itself. But have these not been constituted? It is a big question mark which I wish the hon. Minister for Corporate Affairs to explain.

Coming to the Bill, some of the major amendments include providing greater flexibility in incorporating and running a company by simplifying Memorandum of Association which and doing away with Central Government approvals, etc., to simply procedures to raise capital, to rationalise penal provisions relating to auditors, improving corporate governance and remove ambiguities in CSR provisions, etc.

With your permission, I have a few points to make on the Bill and request Shri Meghwal to ponder over them and take steps accordingly.

(o2/1530/rbn/ind)

With your permission, I have a few points to make on the Bill and request Shri Meghwal ji to ponder over them and take steps accordingly.

The first one is regarding Clause 45. Clause 45 allows a relative of an Independent Director to be indebted to the company or its promoters within a limit as may be prescribed by the Central Government. But I wish to make a point here. When a relative of an Independent Director is indebted to company, the independence of such a Director would be highly suspect. Especially, when a relative of an Independent Director is indebted to promoters of a company, independence of such a Director becomes a definite casualty. Here, the Government of India may prescribe the limit, but that limit is nowhere mentioned in the Bill. I suggest, while framing subordinate legislation, the limit should be kept at a minimum level. Otherwise, it brings disrepute to the company and also hit its brand image in the market and before creditors.

Clause 45 allows some pecuniary interest in companies for Independent Directors. The Bill allows such Directors on their own to have transactions with companies where they are Independent Directors up to 10 per cent of such Independent Directors' total income or such

amount as may be prescribed. It means, in a way, we are legitimizing ‘self-dealing merchants’ as Independent Directors.

I apprehend that the limit of 10 per cent transactions in the hands of Independent Directors can be altered by the executive action by prescribing an altered limit. Vested interests can achieve a higher limit by influencing the executive. I feel that this would certainly weaken the independence of corporate boards. And, you are also removing an existing provision which says that an Independent Director’s relative should not have been a senior employee of the company in the last three years and it may also impact independence of an Independent Director.

Secondly, I beg to differ with the CLC which says that such a small amount of income will have no bearing on the independence of the Director. This assumption, in my view, is flawed. A threshold limit of the pecuniary relationship affecting the independence of a Director cannot be objectively set, as the concept of independence is more subjective in nature. Objectively, the only manner in ensuring independence is adhering to the provisions in the Act, i.e. absolutely no monetary relationship aside from the Director’s remuneration.

The next one is Clause 59. You are proposing to amend Section 185 which deals with loans to Directors, etc. I wish to submit that a holding company, irrespective of being a public or private company and without conditions imposed on the nature of its shareholding, can grant loans to its subsidiaries subject to the passing of a special resolution and the subsidiary utilising such amount for its principal

business activities. This may be a cause of concern because if the end-use of loan is still restricted to the 'principal business activities', it appears that in case of loans required by the subsidiaries for purpose other than its 'principal business activities', holding companies may have to continue the current practice of amending its objects in its Memorandum of Association to include 'grant of loans to subsidiaries', in order to have such loans granted in the 'ordinary course of business.'

Then, claim exemption under sub-section (3) (b) of the proposed to be amended Section 185, which exempts companies providing loans/guarantees/securities in the ordinary course of business, provided the specified rate of interest is charged. But again, if the MCA intended to permit such an exception, it would have been reflected in the Bill itself. Secondly, practice of amending the objects clause may prove to be risky. So, I suggest for consideration of the hon. Minister that Exemption Notification must be amended to reflect the above relaxation under Section 185 and there should not be any confusion that public companies enjoy more liberty than private companies under Exemption Notification.

The next one is regarding Clause 60. Clause 60 of the Bill seeks to amend Section 186 of the Principal Act by deleting restrictions on layers of investment companies. It also seeks to provide for aggregation of loans and investments so far made and guarantees so far provided, for the purpose of calculating the limits of loans and investments. Further, it also seeks to provide that requirement of passing a special resolution at general meeting shall not be necessary where a loan or

guarantee is given or where a security has been provided by a company to its wholly owned subsidiary company or a joint venture company or acquisition is made by a holding company of the securities of its wholly owned subsidiary company.

(p2/1535/rp-vb)

I agree that under the existing provisions, a company is not allowed to make investment through not more than two layers of investment companies. This Clause eases the structuring of group companies and inter-company investments.

I feel that there is a need to put a limit on the number of layers. Otherwise, I am apprehensive that this very proposed amendment facilitates rerouting of black money against which this Government waged a war. And, the second one is, you are going to create a structure where promoters can control large businesses with small holdings through a series of subsidiaries. If this is the objective of this provision, what would be the impact on corporate governance?

The next point is regarding Clause 65. It is good that the hon. Minister has removed the ceiling of 11 per cent on managerial remuneration. But, there is a condition that if a company has taken loan from a bank or if any public financial institution is subsisting or there is any default, then it has to take approval of that financial institution. If a company takes loan, say from 10 financial institutions, then it has to take approval from each one of them. And, everybody knows that no bank or financial institutions is going to agree to this. But when it comes to private companies, there is no need to take

consent of lenders even if such a private company has a running default with its lenders. So, I feel this is sheer discrimination and request the hon. Minister to relook at it once again.

Sir, one final point I would like to make is in response to rising NPAs. Hon. Minister, this is an important point to which I would just like to draw your attention. With the rising NPAs, banks are now insisting on personal guarantees or personal guarantees of the promoters for every loan taken by company. This goes against the very principle and nature of a limited liability companies. If promoters have to provide a personal guarantee for every loan that they have to take for their companies, then what is the point of having a limited liability company? That goes against this principle. So in response to this, I believe, risk taking is coming down in our country. The risk taking comes down. The dynamism of our economy depends on risk taking capability. I think, the dynamism of our economy is also at risk if personal guarantees are insisted every time. There needs to be a balance. The accountability of banks also has to be there in doing their due diligence and evaluating the loans needs to be brought into focus. What is the due diligence being done by the banks? How are they evaluating the nature of the loan before giving the loan? All these things also need to be brought into focus. The accountability of banks also needs to be established. It is not only that accountability has to be completely on the promoters who are taking the risk in the first place but the banks giving the loans also have to take some risk. I think, a balance needs to be maintained.

In conclusion, I would like to say that there is no doubt that a large portion of the Bill achieves its objective of providing clarity, unambiguity, transparency and certainty. But there are some provisions, a few of which I had mentioned, which appears to have been contradicting to the core theme of the Bill. I only wish hon. Minister will have a relook at them once again closely and avoid this Bill paving the way for rampant misuse of these provisions.

With these observations, I support the Bill. Thank you.

(ends)

1539 hours

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, at the outset, I would like to state that on behalf of the Telangana Rashtra Samithi we support this Bill. But, yes, this is a very small step in the long democratic process. While it is an important step, we are going to pass it, it may merely amount to tinkering of the existing law and great changes are required. At the end of the day, in another half-an-hour, we are going to pass this Bill. All of us are going to thump our benches loudly and cheer that the Bill is going to be passed.

I will just raise two or three points. Many more points have already been covered. There are a number of layers and subsidiaries. We should support this. The number of layers and subsidiaries were limited. Now, it is unlimited. This is very very required. I worked in a large multinational corporation, General Electric Corporation, one of the largest companies in the world. I was trying to count how many subsidiaries and layer of subsidiaries it has.

(q2/1540/rcp/pc)

I think, I stopped counting at 150, but I think there are more than 1000 subsidiaries and several layers. It is extremely required for Indian companies to grow big, to become multinational conglomerates. Sometimes, even temporary companies are formed called a Special Purpose Vehicle for a particular contract. Short duration joint ventures are formed. Country-specific companies are formed. So, I think it is

very important. It does not restrict Indian companies to grow. We support it.

My next point is regarding pecuniary interest of independent directors. I think, this restriction has been removed. This is totally not required. It is because, the concept of independent directors is that it is not the interested parties who are directors. We want a fresh thought. It may be an academician who is an independent director or it may be a scientist in that field or it may be a market engineer or a finance expert or even a social worker who brings a new thought in the company directorship. What is the need for them to own a company? It is because, the very fact of owning a company brings in conflict of interest. But the rationale here is, little bit conflict of interest is okay. But there is an American phrase which says you cannot be a little bit pregnant. Either you are pregnant or you are not pregnant. How can you have little a bit conflict of interest? Either you have conflict of interest or no conflict of interest.

I have one more point regarding removal of dealing in insider trading. Once again, unnecessarily we are treading on a dangerous area. In an age when the Prime Minister and the whole country is looking forward to give more teeth, I think we are taking away one teeth from the law makers. Right now it is only SEBI which can go after these companies that are dealing in insider trading and removal of forward dealing. We do not need relaxations. We need stricter regulations. We are discussing all this when one Mr. King of good times is actually fishing somewhere in some islands near Britain or

some other place. So, I think we need to make it stricter. While we support the entire Act, I would like to bring forth a few other issues.

In US, we have the Sarbanes-Oxley Act and the Foreign Corrupt Practices Act. These have significant teeth. Companies there are really scared not out of a moral need or ethical need. It is because of the sword hanging and because of the teeth those regulations have. I think, we need to make regulations stricter. In this case, it is mostly relaxing those regulations.

When the previous Companies Act, 2013 was addressed, there is a whole list – whether it is CII or FICCI – of disadvantages, pros and cons that were listed out. One of them is the compliant requirement which continues to be very high. It is good; it is required. But, if it is too high, it hits the ease of doing business. It can be high for large companies which have hundreds of employees and even they have the accounts and compliance departments. But for a small company, to have such stringent compliance standards will actually reduce the ease of doing business. This was actually given earlier. There is no mention of that in this Bill.

The Memorandum of Association, as per the Act, requires the company to declare the objective of formation. The Bill removes this requirement. We saw a telecom company importing apples. Earlier, we had objectives of the company and the company had to do that business. You cannot do any other business. So, we cannot do relaxations on some of these. I think, we need to increase this. I do not

want to say too much because, I think, many speakers have covered these points.

Many speakers said that we achieved great things by closing down defunct companies. This is one more thing of thumping the benches too hard for very little achievements. We had 16 lakh companies and, I think, the Ministry did a good job. They took an initiative of closing down defunct companies. Frankly, I also have a personal experience in this regard.

(r2/1545/smn/mz)

Recently, two companies belonging to my son were closed down. They were neither scam companies nor they were involved in any operations which were illegal. They were not shell companies. This is merely a part of spring cleaning. So, you get rid of unwanted things in your house. In most countries after winter, in spring, you have enough of unwanted things which you throw out or close them. So, the Ministry's initiative is good. A lot of group companies close down these unwanted companies. How many are they? Maybe, they are about 16,000 or so. They closed them down in the last six months. It is a very good initiative but let us not say that we made any impact on closing down shell companies or unauthorised operations. A lot more needs to be done. That is not the proof of the pudding. Somaiya Ji was mentioning that we closed down these many companies. By doing that, we have not closed any shell companies. Shell companies are alive, kicking well, paying all the fees and doing all the illegal operations. So, a lot more needs to be done. The real proof of the pudding is, have

the NPAs of banks reduced, has corruption reduced, has tax compliance increased, has *hawala* reduced, has under-invoicing of exports reduced and finally, has the rupee gained value in the international market? These are the real proofs of pudding. So, has our GDP increased significantly? Yes, we are making marginal progress. At this point, I would also like to make one more thing. So, entire India is not like this. Some pockets of India are doing extremely well in terms of tax compliance and other things. I would like to point out that you will be shocked to know, recently we got the data, that in the State of Telangana, got 21.7 per cent increase in its tax collections. The next is only Chattisgarh which is at 10 per cent and the rest of the country is hardly at 7-8 per cent.

Lastly, a lot more needs to be done. Not enough is being done. So, when we pass the Bill, let us not thump our benches so hardly. Let us not cheer so hardly. Let us thump little softer. Thank you Sir. We support the Bill.

(ends)

1547 hours

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Chairman Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to speak on an important Bill.

Sir, as you know that this Bill was introduced in Lok Sabha on 16th March, 2016 and referred to the Standing Committee on Finance on 12th April, 2016. Actually, the Companies Act, 2013 came into force on 1st April, 2014. Since then many companies raised their voice that they are facing difficulties with the implementation of 2013 Act. So, the then Government set up Companies Law Committee on June, 2015 to examine the issues regarding implementation of 2013 Act. The Committee submitted its report in February, 2016.

But in the meantime in 2015, the Supreme Court gave its judgement related to quasi-judicial tribunal set up under the 2013 Act as invalid.

Sir, it was the need of the time to amend some sections related to such issues.

Subsequently, the Standing Committee on Finance heard the views of the Institute of Chartered Accountants of India, FICCI, CII, ASSOCHAM and NASSCOM.

Finally, they submitted the report on 7th December, 2016. I agree with the observations made by the Standing Committee and the verdict of the Supreme Court also.

Sir, it is true that all recommendations submitted are for improving ease of doing business in India without many hurdles. The

Committee has proposed changes in 78 sections. Approximately, 50 amendments to the Rules have also been proposed. So, a record number of amendments have been proposed in this Bill. Mostly, it will help the corporates to expand their business in India. But I want to know about the small companies. The existing definition of small companies limits the scope of small companies having a turnover of rupees two crore. The limit is being increased to rupees five crore but the limit of paid up capital still remains at rupees fifty lakhs. I request the Government to review the situation.

(s2/1550/mmn-bks)

In another case relating to banking companies, I want to seek some clarifications on the provision of Sections 53 and 185. Actually, the banks are making use of Corporate Debt Restructuring (CDR) and Strategic Debt Restructuring (SDR) Schemes to convert their loan into equity. The problem is that the fair value of equity shares was less than its par value. However, the bar in the Act against issuing shares at a discount would force a banker to convert the loans at least at par value of the equity. The provisions of Section 53 are proposed to be amended to permit conversion of loans into equity at less than the par value. Please clarify this position.

Further, I want to know the provisions relating to forward dealing and insider trading to be omitted from the Companies Act, 2013. Why is such a proposal necessary? I want to know why such a proposal is necessary. Now under what Act will the insider trading be dealt with?

In addition to that I want to seek some clarifications. Dr. Kirit Somaiya, Shri Bhartruhari Mahtab and also Prof. Saugata Roy told here about some companies. Kirit Somaiya Ji told about 30 companies. He has huge information with him, including Saradha scam. I know, and also I think Dr. Kirit Somaiya also knows that Saradha Company and Rose Valley Company are under the CBI inquiry, under the CBI scanner. I am sorry to say that during interrogation, some MPs were also interrogated and one MP is still now in jail. In spite of that, I am sorry to say that the CBI is conducting its inquiry in a very, very slow pace. There is no effort to refund the money to the actual losers, the people whose money was looted. There is no effort. Then what will be done in future?

In the future also, some fake companies will be registered but not for doing any business. They will collect money and launder it to others and launder it to foreign countries also. In such a way, the companies are being registered still now in India. What do you do about that? What is the thinking of our Minister about all these ponzi and fake companies? What action are you going to take about these companies? Now it is a very serious matter in India. What kind of inquiry is being done by the CBI? The CBI is doing the inquiry. The ED is also making the inquiry by the ruling of the Supreme Court. But I am sorry to say that there is no progress in the inquiry.

The CBI is directed by the Prime Minister. Then, my question is, whether the Prime Minister has directed the CBI to go slow and not to take action and not to close their inquiry. It is a never ending process,

and finally, the public will be refunded nothing. They will suffer. So, I request the Government to take action. Also, I request Dr. Kirit Somaiya that if you have huge information, then please give it to the Minister to make an inquiry into that. Why are you speaking only here? Why are you making the statement here? You give it to the Minister and let them conduct an inquiry.

Now, you have the SFIO; you have the ED; and you have the CBI. They can make inquiry and take action. So, this is my request to the Minister that please to try to finalise this inquiry and refund the money to the losers. It is the need of the hour, and give punishment to the culprits who have taken money from them.

I am concluding my speech. I hope our Minister who is present here, will take necessary action. Thank you.

(ends)

(t2/1555/san-gg)

1555 hours

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

We appreciate the amendments which are being brought into the company law, particularly with regard to the set-up of Company Law Tribunals and Appellate Tribunals. It has also tried to take some initiatives to protect the interest of the investors on a large scale. Similarly, it has tried to bring in some accountability of the Directors, the auditors and the managerial persons. It has also tried to improve the corporate governance. It also wants to help in ease of doing business, particularly for the start-up companies and to simplify some of the procedures like private placement process, self-declarations. It is also doing away with separate offer letters. It also wants a register to be maintained of significant beneficiary-owners of the company.

We appreciate these positive aspects, but as Shri Bhartruhari Mahtab mentioned, a law is as good as it is administered. Therefore, merely bringing laws does not take us anywhere. The implementation of the law has to be good and monitoring has also to be done. All that we need is mostly on account of corporate governance, particularly dealing with the banking sector as well as corporate sector. That is totally lacking on professional lines as far as India is concerned. We are far behind in comparison to the advanced countries and the European countries.

Sir, I am not able to appreciate some of the clauses which have been incorporated for the simple reason that a relative of an independent director could give a loan to the company or to the promoters and its subsidiaries. It is definitely an unhealthy trend. I do now know why it has been considered. Many of the Members, who spoke before me, have already mentioned that there is no reason as to why it has to be considered. Already, there is lot of nepotism and corruption taking place and still you want to bring down the independence of independent directors. It is very unfortunate. The very logic of bringing in independent directors, as earlier speakers mentioned, is lost the moment you permit a relative of an independent director to give a loan to the company or to the promoters.

I thank the Ministry for having done a lot of consultations and formed committees and all that before bringing in this Bill, but there is one thing missing. They have involved the RBI, the SEBI, industrial bodies, ICWAI, ICAI, ICSI etc., but the real stakeholders, the investors, are totally missing. I do not think that representatives of the investors, who are the real shareholders and stakeholders, is mentioned anywhere. I do not think that any of the document shows that they have had discussions with the bodies of shareholders. It is an extremely important thing. Perhaps they can consider one thing now. As of now, India does not have a system or a committee at the highest level to protect the interests of the shareholders. Both the Ministers, who are sitting here, are learned Ministers. They may consider to have a high level committee to protect the interests of the investors. Most of them

are very small time investors and the money belongs to them. Every time, the other institutions are taking initiatives. It does not take them anywhere unless we really involve the investors and the shareholders.

Sir, I would like to ask the hon. Minister as to why they have given a big concession with regard to managerial remuneration. Earlier, beyond a stipulated limit, the proposal was supposed to come to the Government. Now, you are removing that also. I have a classical example. Here, I am not talking politics and I am not prejudiced. The Reliance Industries company exploits – I am saying this in a positive sense and not a negative sense – the oil and gas in our country. Whatever be the pricing policy, it is giving enormous profit to the company, running in lakhs of crores and crores of rupees. We all know about the house constructed by owners of Reliance Industries. I do not think that in the entire world, you have a parallel to that. They have spent crores and crores of rupees to construct that house. We do not deny it, but the point is that he has exploited the natural resources which belong to the State, to the country and to the poor people of this country. Therefore, I am of a very strong opinion that managerial remuneration beyond a stipulated limit should be with the Government because the money belongs to the people and the land belongs to the people and these are the national resources. Therefore, allowing it just like that is not required because as we see it now, one per cent of the people in India own 60 per cent of the interest by way of national wealth.

(u2/1600/ak-cs)

Kindly see this irony. Unless you take these kinds of steps, the gap between the rich and the poor can never be filled up. So, I would request the hon. Minister to please give a thought to it, and managerial remuneration should be restricted beyond a point.

There are Company Law Tribunals and Appellate Tribunals. It is fine, but as of now you consider that it will reduce the burden of the High Courts. There is no doubt about it because the work could be transferred to these Tribunals, but the point is that you have a very limited number of Tribunals all over the country and most of the States do not have it. Ultimately, it will again lead to pendency of cases unless you open more. For example, unless you have more number of Company Law Tribunals in the very highly industrialised States like Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, I do not think that it will serve any purpose. So, kindly have a re-look at this issue.

Many people have spoken in favour of prohibition of more than two layers of subsidiaries. We appreciate it as perhaps it wants to plug the loophole of siphoning off money illegally, and corruption also will be brought down. But certain industries, particularly, the infrastructure companies just cannot handle without having more number of layers of subsidiaries. So, that aspect needs to be considered because the infrastructure companies are extremely important. ... (*Interruptions*)

Sir, very few speakers are there. Kindly bear with me as there are a few more points. Therefore, at least for infrastructure companies it should be considered.

One more point is a buzzword in the Government for the last three years, which is 'ease of doing business'. Why are we pampering the industries so much? What did they do for the last three years? Why are we pampering the start-up companies also to this extent? It is at what cost and whose cost? If you see the Non-Performing Assets (NPAs) for the last three years, it has doubled as much as from Rs. 5 lakh crore to Rs. 10 lakh crore and in some cases even Rs. 16 lakh crore has been mentioned. When the performance of the private sector banks is so good, then why are these Government sector banks lagging behind? Therefore, 'ease of doing business' should have some logic because the money does not belong to anybody. It belongs to the poor people and whatever taxes are paid by a poor fellow like a sweeper is being given here. So, the money of the banks belongs to the poor people. Therefore, while 'ease of doing business' to some extent could be encouraged, but not beyond a point, and a blanket permission should not be given. Kindly re-look at this issue because I do not think that in the last three years any of these so-called companies have produced any employment. So, I would once again request the hon. Minister to re-look at these things.

माननीय सभापति (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): अब आप समाप्त कीजिए।

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Okay, Sir. Lastly, as regards the Corporate Social Responsibility (CSR), I would request the hon. Minister that CSR is extremely important because unless that is done, then there is no point in it. I would suggest that unless there is an Act for CSR it will not serve any purpose. It is

for the simple reason that instead of spending on smaller things, bigger things like rural infrastructure, housing, hospital buildings, roads, etc. should be constructed, and in this way the two per cent of annual profit of the companies could be better utilized than squandering it away. Thank you very much for this opportunity, Sir. Thank you.

(ends)

1604 बजे

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : महोदय, आपने मुझे कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, इस सरकार का एक उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस है और दूसरा उद्देश्य यह है कि व्यापार और उद्योग में सुगमता है। इसी उद्देश्य को लेते हुए यह कंपनी (संशोधन) विधेयक लाया गया है। काफी समय तक कंपनीज एक्ट 1956 के तहत कम्पनियाँ काम करती थीं। उसके बाद विचार हुआ, जब इन्वेस्टर का पैसा, आम गरीब जनता का पैसा इधर-उधर होने लगा, तो यह चर्चा हुई कि कंपनीज एक्ट नया बनना चाहिए और उस पर चर्चा शुरू हुई।

(w2/1605/hcb/spr)

2013 में नया कंपनीज एक्ट लागू हुआ पर उस कंपनीज एक्ट में इतनी कमियाँ थीं कि उसके जो कुल 470 सैक्शंस हैं, उसमें से आज तक 284 सैक्शंस ही लागू हुए हैं, बाकी 186 सैक्शंस सरकार अभी तक लागू नहीं कर सकी, क्योंकि उनमें काफी कमियाँ थीं। इन्हीं कमियों को दूर करने के हिसाब से बीच में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 भी पास किया गया और उस समय डिस्कशन में यह आया कि अभी कंपनीज एक्ट में और अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है ताकि जो छोटी कंपनियाँ हैं, जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं और जो वन मैन कंपनियाँ हैं, उनको कुछ फॉर्मैलिटी कम करनी पड़े जो कि बड़ी कंपनियों को ज्यादा करनी पड़ती हैं। उसी उद्देश्य से कंपनीज एक्ट 2016 आया है।

1606 बजे

(श्री हुकुम सिंह पीठासीन हुए)

जैसा अभी महताब साहब बोल रहे थे कि अभी और अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि आज जो छोटी कंपनियाँ हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं, जिनको पहले कंपनीज एक्ट 1956 में कुछ स्पेशल सुविधाएँ थीं, वे इस कंपनीज एक्ट 2013 ने हटा लीं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस बारे में भी एक बार स्टेकहोल्डर्स को बुलाकर, चर्चा करके जो भी आवश्यक अमेंडमेंट है, वह भी

आगे किये जाएँ। इसमें सबसे बड़ा जो काम किया है, वह काम यह किया है कि जो छोटी कंपनियाँ हैं और अनलिस्टेड कंपनियाँ हैं, उनको एजीएम या जनरल मीटिंग कंपनी शेयरहोल्डर्स की करनी होती हैं। अभी कंपनीज़ एक्ट में प्रावधान है कि इसमें 21 दिन का नोटिस पीरियड चाहिए। पर जो अनलिस्टेड कंपनियाँ हैं, उनको कोई मीटिंग करनी है, और उसके 95 परसेंट शेयरहोल्डर्स, यानी 95 परसेंट जो मालिक हैं, वह एग्री हो जाएँ तो वह कम समय में भी एजीएम काल कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा चेंज उन्होंने किया है।

दूसरा, कंपनीज़ प्रॉस्पैक्टस जो मिलते हैं, पब्लिक इश्यू में जाते हैं, डायरेक्टर उसमें साइन करते हैं और उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, उसमें कुछ फ्रॉड होता है तो उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर उन डायरेक्टर्स ने किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर अपनी राय दी है कि यह एक्सपर्ट रिपोर्ट है और इसके आधार पर सरकार की तरफ से जो घोषित एक्सपर्ट है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर कोई राय दी और कोई स्टेटमेंट दिया है तो इस अमेंडमेंट में यह प्रावधान किया गया है कि वह दोषी नहीं होगा, जबकि उसकी जगह जिस एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी है, वह दोषी होगा। यह बहुत बड़ा प्रावधान है क्योंकि कंपनीज़ डायरेक्टर बहुत मामलों में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। अगर वे किसी एक्सपर्ट से रिपोर्ट लेते हैं तो उसकी रिपोर्ट की गलती की वजह से उनको सज़ा न मिले, यह प्रावधान इसमें लाया गया है। इसके साथ ही पहले 2013 के कंपनीज़ एक्ट में जो नियम थे कि कंपनी का कोई भी पेपर कंपनी का ऑफिसर ही साइन करेगा, वह भी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, लेकिन अब इसमें यह प्रावधान किया है कि ऑफिसर हो या इंप्लॉई हो, क्योंकि कंपनी का ऑफिसर भी कंपनी का नौकर ही होगा और कंपनी का इंप्लॉई भी नौकर ही होगा, तो इसमें अमेंडमेंट किया कि कंपनी की तरफ से कोई भी जो डॉक्यूमेंट साइन करना है, अगर बोर्ड ने किसी इंप्लॉई को या किसी नौकर को भी ऑथराइज़ किया है तो वह कर सकता है, यह अमेंडमेंट अभी आया है।

महोदय, अभी सभी माननीय सदस्य स्माल कंपनीज़ की बात कर रहे थे। अभी स्माल कंपनीज़ की डैफिनिशन भी चेंज की है और आज की स्थिति को देखकर उसको बढ़ाया गया

है। उसमें एक बड़ा काम इस अमेंडमेंट में किया है, वैसे पूरा नहीं किया है लेकिन शुरुआत की है कि जो बड़ी कंपनियों में पेनल्टी का क्लॉज़ लागू होता था, अभी जो अमेंडमेंट आया है, क्लॉज़ 86 के तहत छोटी कंपनियों को, 1 परसेंट कंपनियों को उसमें जो मैक्सिमम लिमिट है, उसकी आधी कर दी गई है।

(x2/1610/rv-sr)

महोदय, यह एक बहुत बड़ा कदम है। पर, इसमें और कुछ करने की जरूरत है क्योंकि छोटी कंपनियां काफी फॉर्मैलिटीज़ पूरी नहीं कर सकती और उनकी अपनी मर्यादाएं होती हैं। उनके पास उतना स्टाफ भी नहीं होता है। इस कारण मेरा आग्रह है कि इसको उनकी कैपिटल के साथ लिंक करके और उस हिसाब से पेनल्टी के क्लॉज़ लगाए जाएं।

महोदय, शुरु से ही, जब से 'कंपनी (अमेंडमेंट) एक्ट, 2013' लागू हुआ और उसके बाद से जगह-जगह एस.एम.ई.जे. से, छोटी कंपनियों से यह रिक्वेस्ट आ रही है कि कम से कम डिपॉजिट के मामले में उनका ध्यान रखा जाए। बड़ी कंपनियों ने बाजार में हेराफेरी की होगी, बाजार से पैसे लाए होंगे और इन्वेस्टर्स के पैसे खा गए होंगे। लेकिन, छोटी कंपनियां, जो अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों से पैसे इकट्ठे करती है और इस पर जो रोक लगाई गई है, उसको हटाकर कंपनी के जो भी शेयरहोल्डर्स हैं, वे उस कंपनी में डिपॉजिट कर सकें, ऐसा रिलैक्सेशन आपको इस बिल में करना चाहिए, ताकि जो छोटे व्यापारी हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो अपना काम या व्यवसाय कोई भी कंपनी बनाकर स्टार्ट-अप में शुरू करना चाहते हैं, उन्हें कैपिटल की वज़ह से दिक्कतें आती हैं। इसलिए वे अपने रिश्तेदारों से, अपने शेयरहोल्डर्स से पैसे लेकर कंपनी में डिपॉजिट कर सकें और उन दिक्कतों को दूर कर सकें। जब भी आगे इस पर अमेंडमेंट हो, ऐसे प्रावधान और आने चाहिए।

तीसरा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बड़ी कंपनियों में काफी लोगों के, इन्वेस्टर्स के पैसे फंसे हुए हैं। मेरे एरिया में भी ऐसी एक कम्पनी है और वह पूरे भारत की कम्पनी है, जिसका नाम है - 'पी.ए.सी.एल.।' माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि इसको जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जिनसे पैसे लिए गए हैं, गरीब जनता से जो पैसे इकट्ठे किए गए हैं,

उन्हें वे लौटा दिए जाएं। उस कम्पनी के पास काफी एसेट्स भी हैं। उन्हें लिक्वीडेट करके उनके पैसे लौटाए जा सकते हैं, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जान-बूझ कर उसको इधर से उधर किया जा रहा है, जबकि इसमें करोड़ों गरीब आदमियों के पैसे फंसे हुए हैं। इस बारे में भी माननीय मंत्री जी को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए।

माननीय सभापति (श्री हुकुम सिंह) : अब समाप्त करें।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ।

महोदय, एक और जो दिक्कत आ रही है, वह यह है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इनको इन्क्लूड करना पड़ता है। सेक्शन-134 में कंपनीज की जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, उसमें उन्हें 'मैटेरियलिटी चेंज' को इन्क्लूड करना पड़ता है, पर कंपनीज एक्ट में कहीं पर भी 'मैटेरियलिटी' को डिफाइन नहीं किया गया है, जिसके कारण सब लोग इसका इंटरप्रेटेशन अलग-अलग ढंग से करते हैं।

महोदय, मेरा आग्रह है कि इस बिल में इसे भी एक बार डिफाइन कर दिया जाए तो ठीक होगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1613 hours

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Companies (Amendment) Bill of 2016.

I rise to speak on this Bill with so many reservations and so many objections for which I am seeking clarifications from the hon. Minister. At the outset, I would like to congratulate the hon. Minister Shri Arjun Ram Meghwalji for having piloted such an important legislation which is having drastic implications on the company administration in future. I also thank the Minister for having such patience to hear to the detailed discussion on this Bill.

The Companies Act of 2013 was enacted to consolidate and amend the laws relating to the companies. The original Companies Act of 1956 was drastically amended at the time of the UPA Government and the Act has come into force on 1st April, 2014. But, it is quite unfortunate to note that out of 470 sections of the Act, only 284 sections have been brought into force and the rest of the sections have not yet been brought into force. You may kindly see that the heart and soul of the Companies Act of 2014 was the constitution or establishment of the National Company Law Tribunal and the National Company Law Appellate Tribunal. These are the two major drastic changes which took place by virtue of 2013 Act. Unfortunately, even after four years of passing of that Act in the year 2014, three years have elapsed. So far, the Government is not able to establish the National Company Law Tribunal and the National Company Law Appellate

Tribunal throughout the country. Even the aims and objects of the Bill says that it is at the final stage.

(y2/1615/ub-my)

You may kindly see that almost all the powers, which were being governed by the Courts, even the High Court, the Supreme Court, the Company Law Board and the Boards of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), all the bodies were vested with the National Company Law Tribunal as well as National Company Law Appellate Tribunal. But it has not been constituted and it is going at a snail's pace. Even in my home State of Kerala also, the Company Law Tribunal has not been established yet.

Coming to 2013 Act, what were the circumstances because of which the UPA Government enacted such a legislation? Such a legislation was enacted because of the huge scam in company affairs or in the corporate affairs. We know about the Satyam scam, Sahara scam as well as the Saradha Chit Fund scam. So many scams took place. In order to control and check the companies in the country, such an amendment was brought in by the UPA Government. I do agree that because of these circumstances, it became a reactive one rather than a proactive one.

There are some stringent provisions also. In order to avoid the stringent and regressive provisions in the (Amendment) Bill, the Government is claiming or arguing that this 2016 Bill is being brought in. The pertinent question to be considered at this juncture is whether this 2016 (Amendment) Act is sufficient to meet the purpose of ease of

doing business. That is the question to be considered when we analyse the provisions of 2016 (Amendment) Bill.

According to me, if you see, from the first day in Office, this Government has been talking about ease of doing business and giving so many slogans like Make-In-India, Skilled India and Digital India but, Sir, if you go through the entire scenario of these three years of the NDA Government in Office, you can very well see that almost all the slogans are on paper but not in practice. Let us see as to what is the situation of ease of doing business, what is the global scenario and what is the India's position?

At the time when the NDA Government came to power, the global ranking of India was 134, now it has come to 130. I do agree that out of 189 countries, it has come to 130. It is accepted. But if you do a micro analysis of the situation, it can be seen that there is an improvement in starting a business, getting a construction permit and there is an improvement in accessing electricity. There is an improvement in three aspects when it is about ease of doing business. But in all other sectors, situation has worsened further, especially, in accessing credit and in paying tax etc. The ease of doing business is going in the reverse direction. That is why I am saying that ease of doing business is on paper but not in practice.

I am again coming to the 2013 Act. You may kindly see the delegated legislation by the rule making provision. In 2013 Act, there are 470 Sections and there are 28 sets of rules in various chapters. In more than 300 provisions of the 2013 Act, it ends with "as may be

prescribed by the notification”. That means it is a *pukka* delegated legislation. At 300 places in the Act, it is being stated “as may be prescribed by notification by the Central Government” which means ‘delegated legislation’. Therefore, a lot of ambiguity is there.

I will cite one example. What is ‘related party’ transaction? If you want to find it out, half of the portion is there in the 2013 Act and half of the provision is there in the Rule. To my belief and to my information, even now the Companies Act of 1956 has not been repealed. Even 2-3 Sections of the Companies Act, 1956 are still in existence. So, not only Rule and 2013 Act is there, but also the 1956 Act is also there. Total confusion is there. If all the authority is being given to the Government instead of having clarity in the legislation, then the Government will be overpowered and more confusion will also be there. You may kindly see that after the passage and after the 2013 Act came into force, so many circulars were issued by the Corporate Affairs Ministry in order to clear the doubt and to remove the difficulty. (z2/1620/kmr/cp)

So, giving rule-making power in almost all the provisions of this Act will never hold good as far as a good legislation is concerned. I will conclude within a short span of time, Sir, I may kindly be allowed time.

Sir, I now come to the provisions of the Bill clause by clause. I would like to seek clarification from the hon. Minister on a very contentious provision in Section 4 of the Bill. Hon. Finance Minister is also sitting here. The proposed amendment to Section 4 allows too much flexibility to use the objects clause of the Memorandum of

Association of a company. Part 3 of the Memorandum of Association is the objects clause. The aims and objects of a particular company are well established and enunciated in the objects clause of the Memorandum of Association.

What is said in the amendment is that a company can have the business only within the scope and within the limit of the objects which are stated in the Memorandum of Association. That is why the Memorandum of Association is there. By virtue of this amendment to Section 4(c):

“A company may engage in any lawful act or activity or business or any act or activity or business to pursue any specific object or object as the law for the time being enforced.”

That means, a company which has been incorporated for commencing a hospital business, a multi-specialty hospital business, can also take part in the trading business, can also take part in the tourism business, and can also take part in any other business. The only condition which is stipulated in the Amendment Act is that it should be lawful. Is this sufficient? I would like to ask the hon. Minister: what is the scope and what is the significance of having objects clause in the Memorandum of Association? The objects clause may well be removed. Any legal and lawful act can be done within the purview of the company. If it is lawful or legal, the company is entitled or empowered to enter into the business. That means the significance of

the objects clause is lost. That is the first objection which I would like to make.

The impact of Section 4(c) would be that it will definitely be misused by unscrupulous players resulting in corporate fraud. Just now my learned friend has stated that an IT company is importing apples. That is the way this is being misused by the corporate houses and this will be resulting in corporate fraud. That is my objection.

Then there is a lot of ambiguity in Section 42 of the Act.

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): Please conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): This is clause-by-clause discussion also, Sir, kindly give me five more minutes. There is ample time available too. Three hours are allotted for this.

HON. CHAIRPERSON: There are many Members who want to speak on this. Please conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the proposed amendment to Section 42 is very ambiguous about the rights issue and private placement. Private placement means issuance of shares to a select set of persons. The rights issue is something different. By virtue of Section 42, for private placement there are stringent provisions that the receipt of funds should be placed in a separate bank account, and specific timeline is prescribed for issuance or allotment of shares. However, under the rights issue the existing shareholders can renounce their shares in favour of a third party. Suppose you have allocated shares under private placement. As per the rights issue, the existing shareholder has the right to renounce those shares for issuance to a

third party. If share are renounced, what is the remedy which is available? There is ambiguity in that and things are not clear.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. I am now going to call the next speaker.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am coming to my last point on penal provisions.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): It is a very constructive intervention, Sir.

HON. CHAIRPERSON: There are many hon. Members to speak. I have got a list with me.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, the hon. Member is speaking only on the Bill. Please allow him time.

HON. CHAIRPERSON: It cannot go on for ever.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I will conclude within two minutes.

The issue is not properly addressed in the Companies (Amendment) Bill, 2016. There is a conflict between the rights issue and private placement. That issue has not been addressed.

As regards penal provisions, if a company fails to pay back the amount with interest to its depositors, there was a fine which may extend from Rs. 1 crore to Rs.10 crore.

(a3/1625/gm-nk)

Now it has been limited to one crore of rupees or double the amount of the deposit. It is now being limited to a particular amount. I think a review is required into the penal provision. But at the same

time, as far as an auditor is concerned, suppose an auditor resigns from a company but has not intimated it to the Registrar of Companies, he will be fined an amount of fifty thousand rupees to five lakh rupees. So, the penal enforcement is disproportionate compared to the gravity of the offence which is being committed.

Now I would like to mention section 149 which is also proposed to be amended and that is about the Resident Director. According to the proposed amendment, for a Resident Director, 182 days of residing in India is required. I would like to know how it will be possible in terms of ease of doing business which is the sole aim and object of the Bill.

My next point is that two per cent of the annual profit has to be earmarked for Corporate Social Responsibility. Unfortunately, there is no mandatory provision so as to implement the Corporate Social Responsibility.

My last point is that too much flexibility has been given by way of this amendment in the name of transparency and ease of doing business. This is not transparency but pure nakedness.

With these words, I conclude.

(ends)

1625 बजे

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : सभापति महोदय, आदरणीय मेघवाल जी ने कंपनी लॉ अमेंडमेंट से संबंधित बिल इस सदन में रखा है, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज जननायक भारत माता के लाल नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक कदम देश की तरक्की के लिए उठाए जा रहे हैं। देश के अंदर ब्लेकमार्केटियर या कालेधन के व्यापारियों और बोगस कंपनियां खड़ी करके देश का धन लूटने वालों को कड़ी सजा देने के लिए सदन से कानून पास किए जा रहे हैं। चाहे वह इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरपसी का बिल हो, चाहे एनेमी प्रोपर्टी बिल हो। आज जो बिल लाया गया है वह बिल श्री पिलर पर खड़ा है, इसमें **Ease of doing business and encouraging start up and need more harmonious various laws.** जिनसे इज ऑफ़ डुइंग बिजनेस को सुगमता मिले।

महोदय, आदरणीय वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में जो फाइनेंस कमेटी बनी है मैं उसका भी सदस्य हूँ। कमेटी ने समय-समय पर कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं। 25 मई, 2016 को बैठक की, 22 सितम्बर, 2016 को बैठक की, जिसमें कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के कई अधिकारियों को बुलाया गया, देश के अंदर विभिन्न औद्योगिक संगठन काम करते हैं, चाहे वह फिक्की हो, चाहे सीआईआई हो, एसोचेम हो, देश के अंदर कार्य करने वाले विभिन्न सीएस हों, उन सभी के विचार लिए गए और स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश दीं। इनमें से अधिकतर रिकमेंडेशन्स सरकार ने मानी है। 2016 का बजट आदरणीय जेटली जी ने पेश किया, उस समय महान सदन में कंपनी लॉ में अमेंडमेंट लाने की घोषणा की थी ताकि देश में इज ऑफ़ डुइंग बिजनेस में राहत मिल सके।

(b3/1630/sk-rsg)

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति श्री कोविंद जी ने सेंट्रल हॉल में शपथ ली। उस दिन उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कहा था - संविधान सभा में डॉ अम्बेडकर जी ने कहा था कि अभी हमने राजनैतिक आजादी प्राप्त की है, लेकिन अभी आर्थिक आजादी प्राप्त करनी है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय जेटली जी के नेतृत्व में

हिन्दुस्तान में आर्थिक सुधार हो रहे हैं। आज दलित का बेटा भी स्टार्ट अप ऑफ बिजनेस के बारे में सोच सकता है और वह अपनी छोटी सी कंपनी खड़ी कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन में दलित चैम्बर आफ कामर्स में कहा था क्योंकि दलित उद्यमियों ने कहा था कि हम जॉब मांगने वाले नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइड करने वाले बनना चाहते हैं। इस अमेंडमेंट में कंपनी खड़ी करने में राहत मिलेगी, भारत के दलित समाज का एक ऐसा वर्ग होगा जो इस बिल का फायदा उठाकर अपने पैरों पर खड़ा होगा और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने में सफल रहेगा।

माननीय सभापति जी, लोगों ने बोगस कंपनियां खड़ी करके देश का पैसा लूटा, कोई विदेश भाग गया और किसी ने एक कंपनी के अंतर्गत सब्सिडियरी कंपनियां खड़ी कर दी, हवाला और मनी लांड्रिंग के माध्यम से देश का पैसा लुटता चला गया, इस पर बिल के माध्यम से रोक लगेगी। देश में ग्रोथ का नया युग शुरू हुआ है।

सभापति जी, अभी मेरे कुछ मित्रों ने डिमोनेटाइजेशन का जिक्र किया कि इसके बाद देश को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ, आप देश के स्लम एरियाज़ में चले जाइए, गरीब की झोपड़ियों में चले जाइए, आपको मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार से जन-धन योजना, स्टार्ट अप और मोदी सरकार की फाइनेंशियल इन्कलूजन की विभिन्न योजनाओं का लाभ किस तरह से पहुंच रहा है। हालांकि इस बिल का इससे बहुत बड़ा संबंध नहीं है। अभी जीएसटी बिल पास हुए एक महीना भी नहीं हुआ है, एक रिपोर्ट आई है कि जो 30 परसेंट ट्रक के चलने में वृद्धि हो गई है, यानी हिन्दुस्तान में जो ट्रक सारा दिन ढाई सौ किलोमीटर सफर करता था, जिस दिन से जीएसटी लागू हुआ है, उस दिन से साढ़े तीन सौ किलोमीटर का सफर प्रतिदिन तय करने लगे हैं। सुधार हो रहे हैं, उसे देखकर हमारे जो परंपरागत विरोधी हैं, उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। हम इस देश को लूटते रहे और 70 साल तक किसी ने नहीं पूछा। लेकिन आज मोदी जी के रूप में एक जन नायक ऐसा आया है, जो खोज-खोज कर इनकी लूट को निकाल कर सजा दे रहा है।
...(व्यवधान)

(c3/1635/rjs-rk)

माननीय सभापति (श्री हुकुम सिंह) : कटारिया जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : सभापति महोदय, मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारी सरकार के बारे में टीका-टिप्पणी करते रहते हैं, उनके ऊपर मुझे तरस आता है। अब पता नहीं कोई होमवर्क होता है या नहीं, सारी दुनिया की जितनी भी एजेंसीज हैं, वे मोदी सरकार को 73 परसेंट बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ दी वर्ल्ड का खिताब दे रही हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं और हमारे में कोई न कोई नुक्ताचीनी करते रहते हैं। आने वाला समय यह बतायेगा कि किस तरह से भारत का निर्माण हुआ।

अंत में, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

इति)

1636 बजे

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति महोदय, हम कम्पनीज बिल, 2016 पर चर्चा कर रहे हैं। जिन्हें टर्बन मंत्री और साइकिल मंत्री के रूप में जाना जाता है, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य और मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने इस बिल को सदन में रखा है। इस बिल पर बहुत सारी चर्चा हो रही थी। मैं अपने साथी का बड़ा अभ्यासपूर्ण भाषण सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारी बातें यहां पर कहीं। मुझे उनकी कम्पनीज पर जो पढ़ाई और स्टडी दिखी, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री मोदी जी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो एड्रेस किया था, उसके कुछ अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हू। प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि—

‘The CA community looks after the economic health of society’.

प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा था कि—

“A country where a select few loot, cannot scale new heights; Government will continue to take tough stand against those who have looted. ”

जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने कहीं न कहीं गलत किया है, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। यह प्रधान मंत्री जी ने उस दिन कहा था।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप यह टफ स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन आप एक्शन न लेकर सिर्फ बातें क्यों कर रहे हैं? यूपीए के समय कम्पनीज एक्ट, 2013 बनाया गया था, उसमें जो-जो प्रोविजन्स, सैक्शन्स लगे थे, उनमें से कितने सैक्शन्स पर कार्रवाई हुई? कितने सैक्शन्स अमल में आये, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, तो समझ में आयेगा कि कम्पनीज एक्ट, 2013 में 470 सैक्शन्स थे। अगर आप पिछले तीन साल का आंकड़ा देखें, तो इन 470 सैक्शन्स में से 284 सैक्शन्स पर अमल हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस सरकार ने पिछले तीन साल में करीब 190 सैक्शन्स के

ऊपर कोई काम नहीं किया है। यहां पर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात थी, तो वह अभी तक बना नहीं है। आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कहा है कि हम उसे बनायेंगे, तो उसे कब बनायेंगे, यह हमें पता नहीं है। आपने यहां यह भी कहा है कि हम नैशनल कम्पनी लॉ ऐपिलेट ट्रिब्यूनल लायेंगे, तो वे कब लायेंगे, इस बारे में यहां कोई स्पष्टता नहीं है।

सभापति महोदय, अभी तक 186 सैक्शन्स अमल में नहीं लाये गये। यह क्यों अमल में नहीं लाये गये, यह सवाल देश की जनता पूछना चाहती है। यह इसलिए अमल में नहीं लाये गये, क्योंकि ये कहीं न कहीं कॉरपोरेट्स को कंट्रोल करने वाले हैं, कहीं न कहीं उनकी गलतियों को रोकने वाले सैक्शन्स हैं, इसलिए सरकार उसे अमल में नहीं लाना चाहती। यह सवाल देश के सामने है।

सभापति महोदय, यहां वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें यह जवाब देने की जरूरत है। वर्ष 2013 में यह एक्ट बना। इसे तीन साल हो गये, लेकिन आप 200 सैक्शन्स इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे।

(d3/1640/rps-ps)

आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, आप बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पिछले तीन साल में दूर-दूर तक कहीं नहीं दिखा है। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती तो कारपोरेट्स के लिए कई सारी कठिनाइयां आतीं और इस वजह से गलत बातें यहां पर होती रही हैं। यहां पर मैं बात रखना चाहता हूं कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के इस्टैब्लिशमेंट की बात उस एक्ट में हुई थी, लेकिन आपने पिछले तीन साल में इस बारे में कोई काम नहीं किया है। इसके लिए जो कमेटी बनाई गयी थी, उसने कहा था:

“The Committee deliberated on the matter in detail and felt that in view of the critical nature of responsibilities wherein lapses have been seen to cause serious repercussions, the need for an

independent body to oversee the profession is a requirement of the day.”

यह कमेटी ने भी कहा है कि आप जल्दी से जल्दी इसको इस्टैबलिश कीजिए। उसे आप कब तक इस्टैबलिश करेंगे, उसकी तारीख बताने की जरूरत है। जब तक इस प्रकार के मैकेनिज्म में काम नहीं होगा, तब तक सही मायने में आपकी ट्रांसपेरेंसी की बात हवा में रहेगी और उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। वर्ष 2013 के एक्ट में यह लिखा गया था कि रिश्तेदार या आपसे सम्बन्धित व्यक्ति ऑडिटर नहीं हो सकते हैं। अब वर्ष 2016 का यह जो बिल आप लाए हैं, उसमें रिश्तेदार की डेफिनिशन बदल दी गयी है :

“Spouse, parent, sibling, child and financially dependent person who consults that person for taking decision...”

अब यह डेफिनिशन आप इस बिल में लाए हैं। जब स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर विचार किया, उसकी क्या रिकमेंडेशन थी। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि “financially dependent person who consults that person for taking decision” इसको आप निकालिए, लेकिन बाकी पूरी डेफिनिशन वैसी ही रहने दीजिए। आपने वह पूरी डेफिनिशन ही निकाल दी, अब रिश्तेदार कौन है, पता ही नहीं है। अब कौन रिश्तेदार है और किस प्रकार से काम होगा, वह पता ही नहीं है। वीरप्पा मोड्ली जी की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने इस बारे में बात की है। रिश्तेदार की कोई परिभाषा नहीं है, ऑडिटर कौन बनेगा, इसके बारे में कोई क्लैरिटी इस बिल में नहीं है। इसलिए मंत्री जी से मेरी विनती है कि इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दें। वर्ष 2013 के एक्ट की सेक्शन 2 और सेक्शन 87 में यह प्रॉविजन था। There are provisions under Section 87 of 2013 Act which prohibit companies from making investment in other companies through more than two layers of intermediary companies. दो लेयर से ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं, यह प्रॉविजन वर्ष 2013 के एक्ट में था। अब क्या ऐसी बात आई कि

आपने इस प्रॉविजन को निकाल दिया? क्या दो लेयर्स कम नहीं हैं? क्या दो लेयर्स से ज्यादा लेयर्स की जरूरत महसूस की गयी, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर आपने इन प्राविजन्स को निकाल दिया है? दो से ज्यादा कंपनीज को आपने इसमें एलाऊ किया है तो इससे बहुत ज्यादा शेल कंपनीज तैयार होने की संभावना है। आपने कंपनी स्थापित करने के प्रोसेस को भी आसान बनाया है। क्या इससे नए टैक्स चोरी के मामले सामने आएंगे और टैक्स चोरी के नए रास्ते खुलेंगे, यह भी देखने की जरूरत है। यहां पर कहा गया था कि बिल की इंटेन्ट कम्पलायंस को कम करना है। अब आप कम्पलायंस कम करने के लिए बिल लाए हैं, लेकिन कम्पलायंस कम करने की जब बात है तो कंपनी का वाल्यूम कितना है, उसकी साइज कितनी है, क्या इसके बारे में कभी बात होगी या नहीं होगी? एक 10,000 करोड़ रुपये टर्न ओवर वाली कंपनी है और एक कंपनी जिसका टर्न ओवर 10 लाख रुपये है, अगर आप दोनों कंपनीज के लिए एक जैसे प्रॉविजन्स रखेंगे, एक जैसा लेवल ऑफ कम्पलायंस रखेंगे तो 10 लाख रुपये टर्न ओवर वाली कंपनी कम्पलायंस करते-करते ही परेशान हो जाएगी। इसलिए इस बारे में सरकार की तरफ से स्पष्टता आने की जरूरत है कि किस प्रकार से इसमें लेवल ऑफ कम्पलायंस होगा। यहां पर आपने कई ऐसे प्रॉविजन्स रखे हैं, जिनसे सरकार का कंट्रोल आपने हटा दिया है। कंपनी में जो इम्पोर्टेंट मैनेजरियल पर्सन्स हैं, उनकी रिम्यूनरेशन को आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे से हटाने की बात की है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको फेज्ड मैनर में हटाते तो आने वाले समय में इससे जो दिक्कतें होने की संभावना है, वे कम हो सकती थीं। आपने यहां पर कहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज और कारपोरेट्स को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रेगुलेशन में कमी की है। अच्छी बात है, लेकिन इसमें आने वाले समय में टैक्स चोरी के मामले कितने बढ़ने वाले हैं, क्या इसके बारे में सरकार ने कोई अध्ययन किया है?

(e3/1645/asa/rc)

इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज होगी, इसके बारे में सरकार की क्या कोई सोच है, यह भी हम मंत्री जी से सुनना चाहेंगे। यह सब करते वक्त आपने

कॉरपोरेट्स का ख्याल रखा, लेकिन कॉरपोरेट्स का ख्याल रखते वक्त जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पैसे उसमें हैं, उसके बारे में आपने कोई ख्याल नहीं रखा है। आप देखेंगे कि आपने पैनाल प्रोविजन्स ज्यादा से ज्यादा एक करोड़ रुपये का रखा है। जो 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ अगर किसी के कोई लूटेगा और उसको एक करोड़ रुपये में आप सैटल करेंगे यानी इस एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो विजय माल्या जी को एक करोड़ रुपये में पूरी तरह से मुक्ति मिल सकती है। इस तरह के प्रोविजन्स आपने बनाये हैं। जो 2013 के एक्ट में नहीं थे, जो डबल था। यानी जितने पैसे गये हैं, उससे डबल का प्रोविजन था। आपने कॉरपोरेट्स को मदद करने के लिए वे प्रोविजन्स पूरी तरह से हटा दिये हैं।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कॉरपोरेट्स को मदद करने की बात आप *ease of doing business* के नाम पर कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यह सब करते वक्त हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने दो साल पहले जो बात कही थी, वह बात मुझे याद आ रही है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि यह सरकार सूट-बूट की सरकार है। इस सरकार के पास किसान की कर्ज माफी के लिए पैसे नहीं हैं। इस सरकार का ध्यान स्वामीनाथन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है, लेकिन यह सरकार कॉरपोरेट्स की मदद करने के लिए यह सब कर रही है। यह सूट-बूट की सरकार है और यह आम आदमी की हितैषी सरकार नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति (श्री हुकुम सिंह) : किसानों की एक लाख करोड़ रुपये की कर्ज माफी हुई है।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सर, कॉरपोरेट्स की डेढ़ लाख करोड़ रुपये की हुई है।

1647 hours

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Hon. Chairman, Sir, I rise to support the Companies (Amendment) Bill, 2016.

Much has been said in terms of how the provisions or the amendments will ensure Ease of Doing Business. If you look at the stock markets, the way they are going up and if you actually see, the way business is increasing and the GST coming in, it is the correct time in which all these amendments are coming.

I completely agree with the views of previous Members. This is again work in progress and I think such a huge piece of legislation will continue to have a call for amendments even as stakeholders will come to the doors of the Government to place their views.

Sir, I actually, I do not want to take much time. I would just like to state that in the Companies Act, 2013, Section 465 was not notified. This particular Section is the one which repeals the Sikkim Registration of Companies Act, 1961. This is an old law in Sikkim. The merger making Sikkim as the 22nd State was done through the 36th Amendment by inserting Article 371F (k) in the Constitution of India. This provision seeks to protect the old laws of Sikkim. Therefore, this particular repealing of 1961 Act of Sikkim is something which the people of Sikkim are deeply worried about.

In so doing, the then hon. Minister, Shri Sachin Pilot, in the other House had given a full-fledged assurance and I want to quote that assurance. The hon. Minister had said:

“I want to assure the hon. Member from Sikkim that before the notification is issued, we will have consultations with the State Government. For that matter, we will speak to the Chief Minister of Sikkim and the hon. MPs on all the issues related to Sikkim in the Bill and will take into consideration all the issues and address them.”

(f3/1650/snb-raj)

This was the assurance given in the other House and I would like to request hon. Minister through you that this particular assurance be kept.

Sir, finally while supporting the Bill I would like to submit that the Bill seeks to provide a fillip to the entire corporate and business communities of India. To that end, there are so many other issues that seem to be impinging. For instance, the Non-Performing Assets. It is something which has been debated. It comes up repeatedly in the Standing Committee on Finance; it comes up repeatedly in the media and so on and so forth. But every time we see that it is the promoter or the people who run the company who are taken to task, but never have we seen the Chairmen of the banks or the authorities being taken to task. I think, there is a balance that we need to strike somewhere and the provisions of this piece of legislation that we are discussing and debating now will take that into consideration.

Thank you very much.

(ends)

1652 बजे

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित और श्री अर्जुन मेघवाल जी द्वारा प्रस्तुत कंपनी संशोधन विधेयक, 2016 का समर्थन करता हूं। अभी जो चर्चा हुई है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। निश्चित रूप से जब से यह सरकार बनी है तब से प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शी व्यवस्था हो, उसी तरह से व्यवसाय भी सुगम हो, काम करने में आसानी हो, पारदर्शी हो और व्यवसाय सिस्टम में आ जायें, इसके लिए सरकार ने लगातार प्रयास किया है।

मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि डिमॉनिटाइजेशन के बाद, जब फाइनेंस बिल, 2017 लाया गया, उसके बाद हमने जीएसटी को लागू किया और अब हम कंपनी संशोधन विधेयक लाये हैं, इन सभी को एक क्रम में देखा जाये तो निश्चित रूप से यह बात स्पष्ट होती है कि सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि सारा व्यवसाय अच्छे ढंग से किया जाये, ठीक तरीके से हो, पारदर्शी हो और लोगों को काम-काज करने में आसानी हो। यह सरकार की मंशा और उद्देश्य है, उसी को लेकर हम कंपनी संशोधन विधेयक लाये हैं। अभी हमारे एक साथी चले गये हैं, वह कह रहे थे कि अभी हम लोगों ने 186 प्रावधानों का प्रयोग नहीं किया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे जो अपेलेट न्यायालय हैं, उनसे संबंधित ज्यादातर वे धाराये हैं, जब राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और हमारे अपीलीय अधिकरण की व्यवस्था विधिवत् हो जायेगी तो उन प्रावधानों का भी उपयोग किया जायेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। हम यह बिल लेकर आये हैं, हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि व्यवसाय में सरलता आये, सारी चीजें हों, लेकिन उसमें मेरी दो-तीन शंकाये हैं, जो मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं। हम लोग जानते हैं कि पिछले समय में बहुत बड़े-बड़े घोटाले हुए और इस देश का बहुत सारा धन विदेशों में जमा किया गया। यह सरकार पहले दिन से ही चिंतित है। अभी जो

छोटी-छोटी सील कंपनियां, फर्जी कंपनियां बन रही हैं, हवाला पर जैसे रोक लगायी गयी, उसके कारण इन कंपनियों का दुरुपयोग धन को विदेशों में जमा करने में हो रहा है।

(g3/1655/ind-ru)

हवाला का प्रीमियम बढ़ा है, इसकी वजह से भी ट्रेड चैनल्स के माध्यम से काले धन को इधर से उधर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू को कम करके जिस तरह से दिखा देते थे, जीएसटी की वजह से इस पर रोक लगेगी। कई छोटे-छोटे द्वीप जैसे पनामा, मॉरीशस आदि हैं, जिन्हें टैक्स हैवन भी कहा जाता है, वहां दो-तीन माले की बिल्डिंगों में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना है, जिनके माध्यम से काले धन को सिस्टम में लाकर इधर से उधर करने का काम किया जाता है। हमने कम्पनी का रजिस्ट्रेशन बहुत सरल कर दिया है। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से नवभारत टाइम्स अखबार में बताया गया था कि कम्पनियों का दुरुपयोग करके कितना बड़ा घोटाला किया गया। ऐसे ही दिल्ली में जिनकी सरकार है, चार कम्पनियों ने उन्हें दो करोड़ रुपया चंदा दिया, जिसके बारे में उनके डायरेक्टर को भी मालूम नहीं था कि यह पैसा कहां से आया। उन्होंने यह तो कह दिया कि पैसा दिया है, लेकिन कैसे दिया, कहां से दिया, इसकी कोई जानकारी नहीं थी।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसी जो छोटी कम्पनियां हैं, जिनके माध्यम से इस तरीके के काम हो सकते हैं, उन्हें भी रोकने का काम करना चाहिए। हमारे देश में टैक्स एडवाइजर्स को उन कम्पनियों की भी इन्क्वायरी मिल रही है जिनके यहां ज्यादातर विदेशी काम करते हैं। जैसा कि भारत में सिस्टम है कि यहां दो-तीन साल रहने पर विदेशियों को रेजिडेंट का दर्जा मिल जाता है। ये लोग भी इस तरीके की कम्पनियां बनाकर अपने देश में भी व्यवसाय करते हैं और हमारे यहां भी कर रहे हैं तथा ऐसा करके भी वे धन को इधर से उधर करते हैं। हालांकि उन्हें यहां इनकम टैक्स की रिटर्न देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी इसमें गलत करने की संभावनाएं रहती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे विदेशियों पर भी और उनके स्पाउस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि

एपिलेट न्यायालय के लिए हमने जो प्रावधान किए हैं, जो मेरी जानकारी है कि फाइनेंस से संबंधित बहुत-सारे एपिलेट न्यायालय और ट्रिब्यूनल्स हैं, जहां जितने पदों पर नियुक्तियां होनी चाहिए, वह बहुत कम हैं। इस वजह से इनकम टैक्स के अन्य जो फाइनेंस संबंधी न्यायालय हैं, उनमें 75 प्रतिशत न्यायालय काम करने की स्थिति में नहीं हैं।

आपने अधिनियम क्रम-78 में संशोधन दिया है, जिसमें 'ड' में कहा गया है कि ऐसे लोगों को इसमें नियुक्त किया जाएगा जो प्रसिद्धि, योग्यता, सत्य निष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे औद्योगिक, वित्त औद्योगिक प्रबंधन, पुनर्निर्माण ऐसे कामों में 15 वर्ष का कम से कम वृत्तिक अनुभव हो। क्रम-79 में आपने कहा है कि लेखाक्रम, विशेष ज्ञान और कम से कम 25 वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो। मैं समझता हूं कि अनुभव के वर्ष बहुत ज्यादा हैं। जानकारी और योग्यता होना तो ठीक है, लेकिन अनुभव की कमी सामने आ रही है, जिसकी वजह से हमारे जो स्वीकृत पद हैं, उनके सापेक्ष भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। इसलिए ट्रिब्यूनल न्यायालयों में इस तरीके की नियुक्तियां हो सकें, इसके लिए हम लोगों को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, क्रम-81 संशोधन नहीं है, लेकिन एक प्रस्ताव है, जिसमें कहा गया है कि आवश्यकतानुसार न्यायालयों को बनाया जाएगा। इसमें संख्या को स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि इसका असेसमेंट करना चाहिए कि कितने न्यायालयों की संख्या होगी, इस पर विचार करना चाहिए। बहुत साफ-सुथरी मंशा के साथ हमारी सरकार पहले दिन से ही काम कर रही है। हम लोगों ने काम करने का जो तरीका रखा है, उसमें स्पष्ट है कि जो सबसे गरीब लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे अच्छा बनाया जाए और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, इसके लिए जरूरी है कि जो लोग सिस्टम से बाहर चले गए हैं, उन्हें भी सिस्टम में आना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने हम लोगों की बैठक के बीच में कहा था कि 125 करोड़ की जनसंख्या में केवल 80 लाख लोग हैं, जो टैक्स देते हैं। कहने का मतलब यह है कि 160 लोगों में से केवल 1 आदमी सिस्टम में टैक्स देता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 125 करोड़ लोगों में से यदि एक करोड़ लोग भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश का

विकास करने की संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती हैं। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी काम कर रहे हैं, मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि ऐसे ही काम करने से देश आगे बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग सिस्टम में भी आएंगे तथा पारदर्शी व्यवस्था होगी।

मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(इति)

(h3/1700/vb-ru)

1700 बजे

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बहुत ही अच्छा बिल है, इसका सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस बिल पर काफी चर्चा हो चुकी है, इसके संबंध में केवल दो-तीन बातें मैं बोलना चाहूँगा।

मैं गांव से आता हूँ। वहाँ जो घटनाएँ हो रही हैं, उनको मैं वित्त मंत्री जी को बताना चाहूँगा। यह बिल 'स्टार्ट अप' और 'इज़ ऑफ़ ड्रूइंग बिज़नेस' से जुड़ा है। लेकिन जब हमारे गांव का नौज़वान पैसा लेने के लिए बैंक में जाता है तो पैसे नहीं मिलते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में बैंकों में 4650 करोड़ रुपये एफडी है और 550 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है। वहाँ का पैसा मुम्बई-कोलकाता हेड ऑफिस भेजा जाता है। यह पैसा तमाम बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है और वे लोग उसे किसी न किसी तरह से एनपीए बना लेते हैं।

इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि कम से कम हमारे गांव के बैंकों में जो पैसे हैं, वह हमारी एफडी है। उसमें से ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे गांव के नौज़वानों को दिया जाए, ऐसा प्रयोजन किया जाए। वे 'स्टार्ट अप' में भाग लेकर वहाँ छोटे-छोटे उद्योग

स्थापित करके आगे बढ़ सकें। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है। यही एनाउंसमेंट भी हुआ है। लेकिन वहाँ ठीक तरह से पैसे नहीं दिये जा रहे हैं।

नेशनलाइज्ड बैंकों में एजेंट्स काम कर रहे हैं। एजेंट्स के माध्यम से उनको बताया जाता है कि फलां उद्योग में तुम्हें दस लाख रुपये सब्सिडी मिलेगी। वे कहते हैं कि तुम मुझे दो-ढाई लाख रुपये रिश्वत दे दो, तो हम तुम्हारा लोन पास करेंगे। अन्यथा कोई न कोई लैकुना निकालकर उनको लोन नहीं दिया जाता है।

कुछ छोटी-मोटी फाइनेंस कम्पनियाँ बनायी जाती हैं और हमारे यहाँ किसानों को ज्यादा ब्याज का लालच देकर उनको लुभाया जाता है। इससे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की महिलाएँ ज्यादा प्रभावित होती हैं क्योंकि वे चुपके से पैसे जमा करना चाहती हैं। कोई एजेंट आता है और 15-18 पर्सेंट ब्याज की बात कहकर उनके पैसे ले जाता है, बाद में वह कम्पनी गायब हो जाती है और उनके पैसे डूब जाते हैं। वे औरतें किसी से कह भी नहीं पाती हैं।

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में बड़े-बड़े अधिकारियों की तनखाहें लगभग ढाई लाख रुपये होती हैं। उन कम्पनीज़ के डायरेक्ट पाँच-पाँच लाख रुपये तनखाह लेते हैं। उनका क्वालीफिकेशन एसएससी या इंटरमीडिएट ही होता है। इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाए ताकि वे क्वालीफिकेशन के हिसाब से ही अपनी सैलरी ले सकें, नहीं तो वे लोग पब्लिक के पैसे को लूट रहे हैं।

इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ क्योंकि शेष बातें डिटेल् में हो चुकी हैं।

धन्यवाद।

(इति)

1703 hours

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, this Bill is, of course, the need of the hour. If we look into the background of the case, you may find that Companies Act, 2013 was really a revolutionary and significant legislation which we had in the history of company laws.

We really had high hopes and we all know that in the present scenario, this kind of a legislation is having its relevance. We all know that India is becoming an international destination of investment. It is our duty to remove all the hardships and ambiguity in the way of implementing various causes of the Companies Act.

Similarly, corporate governance is also coming in a big way in India. We should give more attention and emphasis there also. As regards amendment in the CSR, it was a progressive legislation which we had in the Companies Act. I think, we must concentrate and pay more attention there also.

We have many other areas which need to be addressed. We all know that as far as this Bill is concerned, it made the companies more accountable in relation to structuring, disclosure and compliance requirements. In that way, it is the most welcome step.

The Companies Act, 2013 limits the number of intermediary companies through which investment can be made. Similarly, it also limits the number of layers of subsidiaries in a company to have this kind of an investment. This amendment makes it mandatory that the

technical member must at least be at the level of an Additional Secretary.

It is true that this legislation is intending to address the difficulties faced by the stakeholders and improve ease of doing business in our country.

(j3/1705/rp-pc)

In a way, these proposals are giving clarification and removing ambiguity. This legislation is a most welcome step.

I would only like to say two points and they should be discussed in detail considering the timeframe. I do not want to say much on this. The first point is regarding the role of independent directors as per the Companies Act. It is also a most welcome amendment. As per the Act, 2013, the role of independent director was well-explained. It was brought with a very good intention. It helps the companies to protect the interest of minority shareholders and ensure that the Board does not favour any particular stakeholder. The role of the independent directors is very relevant. It ensures clean governance among the corporates. In that way, it was a very important piece of amendment in the Companies Act.

There are certain essential qualifications for independent directors. What are those qualifications? He should not be a promoter of the company. He should not have any kind of special interest in the economic affairs of the company. He should not have any kind of financial relationship with the company. None of his relatives has any

kind of financial interest in the company. He is having completely independent nature of assignment as an independent director.

As far as this piece of legislation is concerned, my apprehension is this. I would like to know whether the independence of the independent directors is diluted or not. The hon. Minister is aware of all these things. I would, once again, like to know from him whether the independence of the independent directors will be encroached upon through this amendment. That is one thing.

At the end, I would like to say something about CSR. By the introduction of CSR, India may, perhaps, be a model to the entire world. CSR was a very progressive and revolutionary measure which we had taken. Unfortunately, CSR policy was not implemented properly. Some industrial heads are diluting it. In the proposed amendments, there is a provision for that. We are giving exemption to certain categories. I would request the hon. Minister to take such things into consideration. Any kind of dilution of CSR activities should not be there. CSR should be adhered to properly.

I would, once again, like to appeal to the hon. Minister to take these two things into consideration.

With these few words, I conclude my speech. Thank you very much.

(ends)

1708 बजे

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : सभापति जी, आपने मुझे कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो यह कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। वास्तव में कंपनियाँ व्यापार को सरल बनाने के लिए और देश की प्रगति में हाथ बँटाने के लिए बनाई गई थीं, लेकिन आज उनका जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, वह चिंता का विषय है। इस उद्देश्य से कि लोगों के लिए व्यापार करना सरल हो, इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। इस संशोधन को इसलिए लाया गया है ताकि कंपनियाँ आर्थिक अनियमितताएं एवं दुरुपयोग न कर सकें। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

मान्यवर, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि कंपनियों द्वारा 2 पर सेंट सी.एस.आर. फंड खर्च करने का एक निश्चित नियम बनाया गया है, लेकिन कंपनियाँ इस सी.एस.आर. फंड से कोई खर्चा नहीं करती हैं। मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थाई समिति का सदस्य हूँ। अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों ने देश भर में उनको प्रेरित किया, कि वे वहाँ खेलों में खर्चा करें और खेलों को बढ़ावा दिए जाने के ऊपर खर्चा करें। इस पर हम लोगों ने पूरे देश में कई बैठकें की हैं। इन बैठकों में हमने उद्योगपतियों और बैंक के लोगों को भी बुलाया था, लेकिन फिर भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं इसे लगातार 3 सालों से देख रहा हूँ।

(k3/1710/mz-rcp)

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे कृपया इस मामले को इन्श्योर करें। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की ओर से भी कंपनियों को एक निर्देश जाना चाहिए। हम लोगों के सामने भी वे निर्देश देने का काम करते हैं। हम सब लोग आग्रह करते हैं, लेकिन वे सी.एस.आर. फण्ड को खर्चा नहीं करते हैं। आज तमाम देश की जो स्थितियां हैं, उन कंपनियों के सहयोग की जरूरत है, लेकिन फिर भी चाहे बात उसमें खेल-कूद को बढ़ावा देने की हो या कहीं जैसे आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने का विषय हो, इसमें उनको

खर्चा करना चाहिए। कम से कम इसमें ऐसा प्रावधान जरूर हो, जिससे कि उन पर बंधन लगाने का काम हो कि वे सी.एस.आर. फण्ड को ठीक से खर्चा करें। उनको दो परसेंट खर्च करने के लिए निश्चित ही कहा ही जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी प्रावधान होना चाहिए।

दूसरा यह कि जैसा मेरे अन्य साथियों ने भी बात कही है कि जो छोटी-छोटी कंपनियां गरीबों का पैसा लेकर भाग जाती हैं। उसमें जो तमाम, वर्ष 2013 में जो प्रावधान था, सदन में भी इस पर चर्चा हुई। लेकिन इस पर अंकुश लगाने का काम नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस बिल में निश्चित रूप से उस बात को जोड़ा जाएगा। वैसे तो वे कंपनियां स्थापित ही न हों, उनको लाइसेंस इश्यु करने के कड़े प्रावधान हों। उनके लिए शर्तें रखी जानी चाहिए, तभी उनको लाइसेंस देना चाहिए। छोटी-छोटी चिट-फण्ड कंपनियां भी लोगों का धन हड़प कर भागने का काम करती हैं। वास्तव में यह बहुत चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि इस बिल में उसे जोड़ा जाएगा। ऐसी कंपनियों के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे कंपनियां पैसे लेकर भाग न सकें।

माननीय सभापति (श्री हुकुम सिंह) : अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : दूसरा यह कि दिवालिया कानून, वास्तव में जो कंपनियां अपने को दिवालिया घोषित करके शेयरधारकों का पैसा हड़पने का काम करती हैं। उसमें समय-समय पर संशोधन हुए हैं। उसके लिए तमाम समितियां भी बनाई गई हैं, लेकिन उसमें भी अभी अंकुश लगाने का काम नहीं हो रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी ऐसे कड़े प्रावधान होने चाहिए। इस दिवालिया कानून को और भी सख्त बनाने का काम होना चाहिए। अभी जैसा मेरे कुछ साथी भी कह रहे थे कि कंपनियां बनाकर अवैध पैसे को सफेद करने का काम किया जाता है, जैसे तमाम प्रकरण आए हैं और तमाम जांचें भी हो रही हैं। सी.बी.आई. इन्क्वायरी भी हो रही है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। हम कैसे इन पर अंकुश लगाने का काम करें कि फर्जी कंपनियों के माध्यम से अवैध धन को वैध करने का काम न किया जाए। उस पर भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जिससे ये कंपनियां अपने

उस अवैध पैसे को वैध न कर सकें। तमाम समितियों का भी गठन किया गया था, दिवालियापन सुधार समिति, सी.एस.आर. संबंधी सभी उच्चस्तरीय समिति बनायी गयी थी। जो सलाह आई हैं, उन सलाह को ठीक से लागू करने इन बातों का ध्यान दिया जाए। मैं आज यही बातें कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

HON. CHAIRPERSON: Before I invite the hon. Minister, I want to make a small comment. No doubt, the debate was very fruitful. There were certain Members who had pointed out some questions. They wanted reply from the Minister. I have noted down their names also and their questions also. But, fortunately or unfortunately, luckily or by chance, they are not present here. They expected reply from the Minister. I do not know whether they will switch on their TVs at their residences or some other place, but they are not here. Anyway, this is the situation which I have pointed out before you.

Now, the hon. Minister.

(13/1715/bks-smn)

1715 बजे

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति जी, धन्यवाद। कंपनीज़ अमेंडमेंट बिल, 2016 पर बहुत सार्थक चर्चा हुई है। इस चर्चा में 18 लोगों ने भाग लिया है। काँग्रेस के बहुत ही विद्वान साथी प्रॉफेसर के.वी. थॉमस साहब ने इस चर्चा को प्रारंभ किया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और जो कुछ बिंदु आए हैं। वह मुझे लगता है कि हमने ऑफिशियल अमेंडमेंट मूव किए हैं, वे शायद नहीं देख पाए होंगे, इस वजह से आए होंगे। जैसे दो बिंदुओं पर बहुत से लोगों ने चर्चा की, करीब-करीब सभी ने चर्चा की है। *restriction on layers of companies, allowing unrestricted object clause for companies.* इन दो बिंदुओं पर बहुत चर्चा की और इसके अलावा सी.एस.आर. पर भी बहुत चर्चा की। मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ कि ये जिन दो बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, *I propose to drop this because official amendments have been moved. Already our hon. Minister has moved official amendment for that. The official amendment, therefore, should satisfy the concern of the above matter raised by some of the Members.* इस संबंध में मेरा पहला कमेंट यह है। दूसरा सी.एस.आर. के बारे में भी करीब-करीब सभी लोगों ने चर्चा की है। कंपनीज़ एक्ट की धारा 135 सी.एस.आर. की परिभाषा को परिभाषित करती है और सैक्शन 134/3 यह प्रावधान करता है कि ऐसी कंपनियां जो सैक्शन 135 में एलिजिबल हैं, वे अपने प्रॉफिट का दो परसेंट खर्च करेगी और सभी मैम्बर्स ने यह कहा कि मंत्रालय इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने नोटिसेज दिये हैं, कुछ कंपनियों ने जवाब नहीं दिया, उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन सैक्शन अलाऊ किया है। हमने कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी सी.एस.आर. के बारे में डाउट है, वे मंत्रालय में भी जाकर चर्चा कर सकते हैं। यह पहली

ऐसी सरकार है, जिन्होंने सी.एस.आर. में खर्चा करना शुरू नहीं किया है, उनके खिलाफ मोदी जी के नेतृत्व में कार्रवाई करनी प्रारंभ कर दी है।

दूसरा एक विषय बार-बार आया कि 2013 का जो एक्ट था, उसके कई सैक्शन का राजीव सातव साहब भी जिक्र कर रहे थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज की तारीख तक कंपनीज एक्ट, 2013 के खाली तीन सैक्शंस हैं, जो कमेन्स नहीं हैं, बाकी सारे हो गये। यह 184 का फिगर आप कहां से लाये, मुझे जानकारी नहीं है...(व्यवधान) आप शायद पुराना बिल पढ़ रहे होंगे।...(व्यवधान) उसे इंट्रोड्यूस हुए भी महीनों हो गये हैं। इसके अलावा प्रो.सौगत राय समेत करीब-करीब सभी सदस्यों ने जिक्र किया और जो हमारे पुराने साथी श्री निशिकान्त दुबे हैं, जो उस कमेटी के बहुत पुराने साथी हैं, शायद वह परमानेन्ट सदस्य हैं, मैं उनसे भी चर्चा कर रहा था। ...(व्यवधान) 15वीं लोक सभा में भी आप फाइनेंस कमेटी के सदस्य थे। एन.सी.एल.टी. और एन.सी.एल.ए.टी. ये 1 जून, 2016 से ऑपरेशनल हैं। ...(व्यवधान) **Yes Sir, it is operational.** आप कभी जाकर देखिये, जो हमारा आर.ओ.सी. का दफ्तर है, जो आर.डी. का दफ्तर है, उसके आसपास देखिये, एन.सी.एल.टी. और एन.सी.एल.ए.टी. चालू हैं, हां उसमें कुछ स्टाफ की कमी है। ...(व्यवधान) ये फंक्शनल हैं। **I can tell that it is functional in your State also.** लेकिन आपने कहा चालू नहीं हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये फंक्शनल हैं। मैं खुद एज ए मिनिस्टर जाकर आया हूँ। कई जगह हाई कोर्ट यह कहता है कि एल.सी.एल.टी. जहां हमारा हाई कोर्ट स्थित है, यहां होना चाहिए, वह कार्रवाई भी सरकार कर रही है। मुझे यही इनिशियल कमेन्ट्स करने थे, उसके बाद जो दो-तीन बिन्दु आए हैं, उनके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। थॉमस साहब ने जिक्र किया कि आपने 2013 के एक्ट के उद्देश्य को डाइल्यूट कर दिया, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया है। जो आपने टू लेयर और ऑब्जेक्ट क्लाज का जिक्र किया, वह मैंने आपको बता दिया कि ऑफिशियल अमेंडमेंट में जो आपका कंसर्न है, उसे हमने इस अमेंडमेंट के माध्यम से हल किया है।

इसके अलावा आपने जिक्र किया कि 8 नवम्बर के डीमोनेटाइजेशन के बाद कंट्री को क्या फायदा हुआ। इस बिंदु का और कई माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूँ कि इसके कई फायदे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक फायदा गिनाता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन के बाद इस देश में 91 लाख नये करदाता जुड़े हैं, यह देश को डीमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा लाभ हुआ है।

(m3/1720/gg-mmn)

टैक्स बेस बढ़ेगा तब आपके संसदीय क्षेत्र में पानी के लिए पैसा मिलेगा? तब आपके संसदीय क्षेत्र के स्कूलों के लिए कक्षाएं बनेंगी? तब आपके यहां, जिनके सर पर छत नहीं हैं, उन सबको छति मिलेगी? डीमॉनिटाइज़ेशन के बाद टैक्स बेस बढ़ा है, ये आंकड़ें बोलते हैं। ... (व्यवधान) हमारे दल की तरफ से किरीट सोमैया साहब बोल रहे थे और उन्होंने कुछ जिक्र किया है, एक्स डिप्टी सी.एम. महाराष्ट्र और उस बारे में, आपने कहा है कि पचास की लिस्ट है, आप लिस्ट दे दीजिए, जो एज़ पर लॉ होगा, निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यह सरकार ईमानदार लोगों के पक्ष में खड़ी है। आपने सी.ए. डे पर माननीय प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना होगा, जिसका जिक्र राजीव जी कर रहे थे। उस भाषण का सार क्या है? राजीव जी, उस भाषण का सार यह है कि यह सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है और ईमानदारों के पक्ष में है। यही तो सार है उसका और कोई सार ही नहीं है। इसलिए किरीट जी, आपने जो चिंता प्रकट की है, उसका भी मुझे लगता है कि जल्द ही समाधान होगा।

एन.के. प्रेमचन्द्रन साहब ने एक बड़ा विषय रखा और आपने इन योजनाओं को स्लोगन बता दिया। You are a very senior Member and I think you are the best parliamentarian also. डिबेट भी आप बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन यह स्टार्ट-अप इण्डिया, स्टेण्ड अप इण्डिया, मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, क्लीन इण्डिया, मुद्रा ये सब स्लोगन हैं क्या? एन.के. प्रेमचंद्रन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकेले मुद्रा में 7 करोड़ 78 लाख लोगों को लोन दिया है। मैं कल ही स्टेण्ड अप इण्डिया का

रिव्यु कर के आया हूँ। 40 हज़ार के आस-पास लोगों को, एस.सी., एस.टी. और महिला एंटरप्रिन्डोर जो नए बने हैं, जिनको दस लाख रूपये से ले कर एक करोड़ रूपये का लोन मिल रहा है। ये योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। जब धरातल पर ये योजनाएं उतर रही हैं और तब ये स्लोगन नहीं हैं, ये भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली योजनाएं हैं। एक जिक्र आया कि एनएसीएल, पीएसीएल और एल्डर फार्मा का जिक्र आया। हमारे अरुण जेटली साहब सही कह रहे हैं कि ये सब आपकी विरासत है, जो हमें मिली है और हम इसको हल कर रहे हैं। मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि एनएसीएल के केस में एक मीटिंग महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के साथ हुई है, किरीट जी के पत्र इस संबंध में बहुत आते रहते हैं। जो छोटे निवेशक हैं, उनका पैसा वापस दिलाने में यह सरकार दृढ़ संकल्प है। चाहे पीएसीएल का इश्यु हमारे सुभाष बहेड़िया जी ने उठाया हो।

सभापति जी, पीएसीएल में लोढा कमेटी बनी हुई है। एल्डर फार्मा का इश्यु आपने उठाया है। शाखा हो, रोज़ वैली हो चाहे जो भी हो, हमारी सरकार का स्पष्ट मंत्र है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है कि ये जो छोटे-छोटे निवेशक हैं, जिन्होंने भरोसा कर के कैपिटल मार्केट में अपना पैसा जमा किया है, उनको राहत देनी है और मैं आपके माध्यम से जिम्मेदारी से कहता हूँ कि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि इनको राहत देनी है। इसीलिए भरोसा इस सरकार के प्रति बढ़ा है।

सभापति जी, अभी-अभी ओईसीडी एक सर्वे रिपोर्ट आई है। जिसमें कहा गया है कि भारत के 73 प्रतिशत नागरिकों ने जो सरकार चल रही है, उस पर भरोसा किया है, जो कि सबसे ज्यादा है और विश्व में फर्स्ट है, हमारे बाद विकसित देश हैं तो यह भरोसे की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी लोढा कमेटी की भी रिपोर्ट आई हुई है, अलग से भी मंत्रालय काम कर रहा है, एसएफआईओ भी काम कर रहा है, ई.डी. भी अपने काम में लगी हुई है, सीबीआई भी काम कर रही है। लगातार छोटे निवेशकों के पक्ष में यह सरकार खड़ी है। अभी एक विषय आया कि कैपिटल मार्केट में ब्लैक करने वाली कंपनियां हैं। क्या बात कर रहे हो साहब? कैपिटल मार्केट इस देश की हैल्थ होती है।

(n3/1725/cs-san)

आपने कहा कि इसमें छोटे निवेशकों के प्रति भरोसा घटा है। अगर निवेशकों का भरोसा घटता, तो कैपिटल मार्केट का सेंसेक्स 32 हजार को पार नहीं करता। यह 32 हजार को पार कर रहा है और स्टे कर रहा है। जब 31 हजार को पार किया था, तो बहुत से लोगों ने, जो फाइनेन्शियल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि यह टेम्पेरी फेज है, 31 हजार पर स्टे किया, 32 हजार क्रॉस कर दिया और स्टे कर रहा है। इसका मतलब यह है कि कैपिटल मार्केट में भारत की हेल्थ ठीक हो रही है और यह इसे दर्शा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन विषयों को और टच करना चाह रहा हूँ। शायद भर्तृहरि महताब साहब ने कहा कि इकोनॉमी की साइज सिकुड़ रही है। आपने यह भी कहा कि बार-बार अमेंडमेंट क्यों आ रहे हैं। देखिए, वर्ष 2013 का बिल, आप साक्षी हैं, रात को यहाँ बहुत देर तक बैठना पड़ा था, शायद 10 बजे गये होंगे और उसके बाद कितने लोगों ने प्रतिवेदन दिए, बहुत लोगों ने प्रतिवेदन दिए। हमारे कोरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय में सचिव स्तर की जो कमेटी बनी, उसने सुझाव लिए। जब राज्य सभा में यह बिल चर्चा में आया तो राज्य सभा ने कहा कि कांप्रिहेंसिव अमेंडमेंट बिल लाइए, इसलिए जो कमेटी बनी, फाइनेंस कमेटी में यह गया और यह कांप्रिहेंसिव अमेंडमेंट बिल है। राज्य सभा में चर्चा के दौरान यह विषय आया, इसलिए हम अमेंडमेंट ला रहे हैं। वर्ष 2015 में हमने अमेंडमेंट किया। राज्य सभा में चर्चा के बाद यह एक विषय आया, उसके बाद यह बिल ला रहे हैं। हम यह बिल अपनी मर्जी से नहीं ला रहे हैं, जो सदस्य सुझाव देते हैं, जो संसद सुझाव देती है और जो कमेटी सुझाव देती है, उसके आधार पर हम यह कांप्रिहेंसिव बिल लेकर आए हैं। कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसकी ऑलमोस्ट ऑल रिकमेंडेशंस हमने इसमें मंजूर की हैं, स्वीकार की हैं और जो थोड़ी-बहुत रह गई हैं, उनको अमेंडमेंट के माध्यम से ला रहे हैं।

मैं इकोनॉमी के साइज के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अभी एक सर्वे आया है। आपने भी उस सर्वे को पढ़ा होगा। वह सर्वे हमने नहीं किया है। वेस्टर्न वर्ल्ड की एक एजेंसी है, जिसने इस सर्वे को किया है। वे कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी की साइज वर्ष 2030 तक

इतनी हो जाएगी कि वह चार डेवलपिंग देशों को क्रॉस करेगी। वह जापान, जर्मनी, फ्रांस, यू.के. को क्रॉस करेगी और India will be the third largest economy by 2030. भर्तृहरि महताब साहब सिकुड़ कहाँ रही है। जितने हम इकोनॉमिक रिफार्म के... (व्यवधान) शायद आप कुछ बोलना चाह रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : दिसंबर, 2016 के बाद ये जो पिछले पाँच-सात महीने हो गए हैं, including July, the credit outgo from banks has come down to five per cent, which is the lowest in the last 60 years. यही बात मैंने कही, यही उदाहरण मैंने दिया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आपने इसके साथ-साथ इकोनॉमी की भी बात की कि वह सिकुड़ रही है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): This is an indication.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : भर्तृहरि महताब साहब, मैं आपको बताता हूँ। यह 2017 का वर्ष है और वर्ष 2017 का जब भी कोई असेसमेंट करेगा, इतिहासकार, प्लानर या हमारी नीति-निर्धारण करने वाले लोग असेसमेंट करेंगे, तो यह 2017 का वर्ष आर्थिक सुधारों का वर्ष कहलायेगा। हमने वर्ष 2016 में 8 नवम्बर को डीमोनेटाइजेशन किया। वर्ष 2017 के जनवरी से यह देश तेजी से डिजिटल ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ा। उसके बाद हमने यूनियन बजट 28 फरवरी से एक फरवरी किया। उसके बाद हमने रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज किया। उसके बाद हमने फाइनेंस बिल पहली बार देश के इतिहास में 31 मार्च तक पास कर दिया और एक अप्रैल को राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को खर्च करने के लिए अधिकृत कर दिया। उसके बाद जीएसटी इस देश में एक जुलाई से लागू कर दिया और यह कंपनी बिल का भी अमेंडमेंट आज यह सदन कर रहा है। मुझे लगता है कि यह 2017 का वर्ष आर्थिक सुधारों का वर्ष होगा। जब यह आर्थिक सुधारों का वर्ष होगा, तो इकोनॉमी की साइज निश्चित रूप से भर्तृहरि महताब साहब बढ़ेगी, मैं यह कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ। एक

विषय आधार का आया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। मैं भर्तृहरि महताब साहब आपको कहना चाहता हूँ कि यह पहली सरकार है, जिनमें ऑन गोइंग स्कीम्स में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके रोकने का प्रयास किया है।

(o3/1730/hcb/ak)

जैसे चंडीगढ़ कैरोसीन जा रहा था। अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते तो हम कहते कि आपके पास तो गैस है, आप कैरोसीन क्यों ले रहे हैं? जब पहले कभी कैरोसीन बंद करते थे, कुछ सरकारों ने करने की कोशिश की होगी, तो उन्होंने कहा कि आप तो छोटे लोगों का हक मार रहे हो। जब हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया तो चंडीगढ़ कैरोसीन फ्री हो गया। ऐसा करके इस सरकार ने अलग-अलग योजनाओं में मोदी जी के नेतृत्व में 57 हजार करोड़ रुपये ऑनगोइंग स्कीम्स में बचाए हैं। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह कंपनीज़ अमेंडमेंट बिल 2016 सबके साथ चर्चा के बाद आया है। सभी माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। हमने सब सुझाव नोट भी किये हैं। मैं चाहता हूँ कि सदन इस बिल को पास करने की पूरी व्यवस्था करे, कृपा करे ताकि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी का साइज़ जो वैस्टर्न वर्ल्ड के लोगों ने तय की है और जो हमारे माननीय मोदी जी का सपना है कि भारत 2022 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाए, इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है, यह पास करने की अपील करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।

(इति)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill further to amend the Companies Act, 2013, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2

Amendments made:

Page 2, *after* line 32, *insert*—

'(ixA) in clause (72), in the proviso, in clause (A), *after* the words "State Act", the words "other than this Act or the previous company law" shall be *inserted*;' (3)

Page 2, line 39, for "a company", substitute "the company". (4)

Page 2, *after* line 39, *insert*--

'Explanation. -- For the purpose of this clause, "the investing company or the venturer of a company" means a body corporate whose investment in the company would result in the company becoming an associate company of the body corporate.' (5)

Page 3, *for* lines 3 to 7, *substitute*--

'(xii) in clause (87), in sub-clause (ii), for the words "total share capital", the words "total voting power" shall be substituted.' (6)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: There are Amendment Nos. 50 and 51 given by Shri N. K. Premachandran. Are you moving your Amendments?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

“Page 1, line 17,--

omit “the arrangement have”. (50)

“Page 2, line 11,--

for “in consultation with”

substitute “with the approval of.” (51)

I have moved Amendment Nos. 50 and 51 to Clause 2, that is, ‘in consultation with’ the Central Government. I would like to have the amendment with the approval of the Central Government in respect of instruments, which are to be signed by the concerned people.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put Amendment Nos. 50 and 51 to Clause 2 moved by Shri N. K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 2, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4

Amendment made:

Page 3, *for* lines 22 to 46, *substitute*—

'4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (5), for clause (i), the following shall be substituted, namely:-

"(i) Upon receipt of an application under sub-section (4), the Registrar may, on the basis of information and documents furnished along with the application, reserve the name for a period of twenty days from the date of approval or such other period as may be prescribed:

Provided that in case of an application for reservation of name or for change of its name by an existing company, the Registrar may reserve the name for a period of sixty days from the date of approval.".' (7)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: There are Amendment Nos. 52 and 53 given by Shri N. K. Premachandran. Are you moving your Amendments?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving Amendment Nos. 52 and 53 to Clause 4.

I beg to move:

“Page 3, line 28,--

after “specific”

insert “lawful”. (52)

“Page 3, lines 35 and 36,--

for “such other period as may be prescribed”

substitute “forty-five days from the date of the application.” (53)

The hon. Minister has not responded to the query or clarification made by us regarding the Object Clause in the Memorandum of Association. This should be specific and lawful, but unfortunately the Minister has not responded to it. Most of the Members from this side have ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He has already spoken on it.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Okay, Sir. I am moving it because ‘specific’ and ‘lawful’. So, I would like to add the term ‘lawful’ also.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put Amendment Nos. 52 and 53 to Clause 4 moved by Shri N. K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 4, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clauses 5 and 6 were added to the Bill.

(p3/1735/spr-rv)

Clause 7

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

“Page 4, line 7, -

for “employee”

substitute “director”. ” (54)

This is a very important amendment to Section 26 of the Act, that is, an instrument has to be attested by any employee. How can it be possible?

My amendment is, instead of employee, let it be the director of the company. It is a material amendment that is to be incorporated. That is why I have moved it.

HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment No.54 to clause 7 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

The question is:

“That clause 7 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8

Amendment made:

Page 4, *for* line 18, *substitute-*

“(ii) clauses (a), (b) and (d) shall be *omitted*.” (8)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 8, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

Clauses 9 to 16 were added to the Bill.

Clause 17

Amendment made:

Page 7, for lines 5 to 7, substitute-

‘17. In section 76A of the principal Act,-

(a) in clause (a), for the words, “one crore rupees”, the words “one crore rupees or twice the amount of deposit accepted by the company, whichever is lower” shall be *substituted*;

(b) in clause (b),-

(i) for the words, “seven years or with fine”, the words “seven years and with fine” shall be *substituted*;

(ii) the words “or with both” shall be *omitted*.’. (9)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 17, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

Clauses 18 to 20 were added to the Bill.

Clause 21

Amendment made:

Page 7, *for* lines 23 and 24, *substitute-*

21. In section 89 of the principal Act,-

(i) in sub-section (6), the words and figures, “within the time specified under section 403”, shall be *omitted*;

(ii) in sub-section (7), *for* the words and figures, “under the first proviso to sub-section (1) of section 403”, the word “therein”, shall be *substituted*;

(iii) *after* sub-section (9), the following sub-section shall be *inserted*, namely:-’

(10)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 21, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 21, as amended, was added to the Bill.

Clause 22 was added to the Bill.

Clause 23

Amendments made:

Page 9, lines 9 and 10, *for* “One Person Company and small company”, *substitute* “One Person Company, small company and such other class or classes of companies as may be prescribed.”.

(11)

Page 9, *after* line 14 *insert-*

(iii) in sub-section (4), the words and figures, “within the time as specified, under section 403”, shall be *omitted*;

(iv) in sub-section (5), *for* the words and figures, “under the section 403 with additional fees”, the word “therein”, shall be *substituted*.’ (12)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 23, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

Clauses 24 to 27 were added to the Bill.

(q3/1740/sr-my)

Clause 28

Amendment made:

Page 9, lines 42 and 43, *for* “not less than ninty-five per cent.”, *substitute* “majority in number of members entitled to vote and who represent not less than ninety-five per cent.”. (13)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

“That clause 28, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 28, as amended, was added to the Bill.

Clause 29 was added to the Bill.

Clause 30

Amendments made:

Page 10, *after* line 11, *insert* –

‘(i) in sub-section (1), the words and figures “within the time specified under section 403” shall be *omitted*;’. (14)

Page 10, *for* line 12, *substitute* –

‘(ii) in sub-section (2), --

(a) *for* the words and figures “under section 403 with additional fees”, the word “therein” shall be *substituted*;’. (15)

Page 10, line 13 *for* “(a)”, *substitute* “(b)”. (16)

Page 10, line 15 *for* “(b)”, *substitute* “(c)”. (17)

Page 10, line 17 *for* “(ii)”, *substitute* “(iii)”. (18)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandranji, are you moving your amendments no. 55 and 56?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 30, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 30, as amended, was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 19 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 19 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.”

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am on a point of order.

HON. CHAIRPERSON: I have already put the question.

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): My point of order is under Rule 331N of the Rules of Procedure and also under Rule 376 of the Rules of Procedure. Kindly have a hearing. There are so many other motions that are also coming. I would like to highlight my point. The hon. Minister has circulated 43 amendment proposals out of which five

new clauses also have to be incorporated – Clauses 47A, 73A, 75A, 78A and a New Provision Clause 88. My point is, out of these 43 amendments, five new clauses have to be incorporated. This Bill had been referred to the Standing Committee. The Standing Committee had a detailed scrutiny of almost all the provisions. But, unfortunately, these five clauses have not been scrutinized by the Parliamentary Standing Committee. By virtue of Rule 331N of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha:

“The report of the Standing Committees shall have persuasive value and shall be treated as considered advice given by the Committees.”

In this case, the Standing Committee had a detailed scrutiny and the Company Law Committee has given the recommendations. All these five amendments come out of all these things. My point is, it is not proper – let me conclude – to suspend Rule 80 (i) by virtue of Rule 388 because the Standing Committee has not considered these five new clauses. That is my point of order. Kindly give the ruling.

HON. CHAIRPERSON: Please refer to Rule 376. It says that a point of order is not point of privilege when a question on any motion is being put to the House. I have told you earlier also.

(r3/1745/ub-cp)

The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 19 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 30A

Amendment made:

Page 10, *after* lines 25, *insert-*

Amendment
of section
121.

‘**30A.** In section 121 of the principal Act,-
(i) in sub-section (2), the words and figures “within the time specified, under section 403” shall be *omitted*;
(ii) in sub-section (3), for the words and figures “under section 403 with additional fees”, the word “therein” shall be *substituted*.;’. (19)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

“That new clause 30A be added to the Bill”.

The motion was adopted.

New clause 30A was added to the Bill.

Clause 31

Amendment made:

Page 10, for lines 26 and 27, substitute-

'31. In section 123 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) in clause (a),-

(A) for the words "both; or", the word "both:" shall be substituted;

(B) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in computing profits any amount representing unrealised gains, notional gains or revaluation of assets and any change in carrying amount of an asset or of a liability on measurement of the asset or the liability at fair value shall be excluded; or";

(ii) in the second proviso, for the words "transferred by the company to the reserves", the words "transferred by the company to the free reserves" shall be substituted;

(b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-'. (20)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

“That clause 31, as amended, stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 31 as amended was added to the Bill.

Clause 32

Amendment made:

Page 10, line 50, *after* “subsidiary or subsidiaries”, *insert* “and associate company or companies”. (21)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

“That clause 32 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 32 as amended was added to the Bill.

Clause 33 was added to the Bill.

Clause 34

Amendment made:

Page 11, *for* lines 15 to 17, *substitute-*

'34. In section 132 of the principal Act,-

(i) in sub-section (4), in clause (c), in sub-clause (A), in item (II), for the words "ten lakh rupees", the words "five lakh rupees" shall be *substituted*;

(ii) in sub-section (5), for the words, brackets and figure "the Appellate Authority constituted under sub-section (6) in such manner as may be prescribed", the words "the Appellate Tribunal in such manner and on payment of such fee as may be prescribed" shall be *substituted*;

(iii) sub-sections (6), (7), (8) and (9) shall be *omitted*.'. (22)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

“That clause 34, as amended, stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 34, as amended, was added to the Bill.

Clauses 35 and 36 were added to the Bill.

Clause 37

Amendment made:

Page 12, lines 25 and 26, *for* "agreed by ninety-five per cent. of the members entitled to vote at the meeting", *substitute-*
"agreed by members-

(a) holding if the company has a share capital, majority in number entitled to vote and who represent not less than ninety-five per cent of such part of the paid-up share capital of the company as gives a right to vote at the meeting; or

(b) having, if the company has no share capital, not less than ninety-five per cent of the total voting power exercisable at the meeting." (23)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

“That clause 37, as amended, stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 37, as amended, was added to the Bill.

Clause 38

Amendments made:

Page 13, for lines 6 and 7, substitute-

'38. in section 137 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) the words and figures "within the time specified under section 403" shall be *omitted*;

(b) in the second proviso, the words and figures "within the time specified under section 403" shall be *omitted*;

(c) after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- (24)

Page 13, line 12, omit "listed". (25)

Page 13, after line 15, insert-

(ii) in sub-section (2), the words and figures "within the time specified, under section 403" shall be *omitted*;

(iii) in sub-section (3), for the words and figures "in section 403", the word "therein" shall be *substituted*.'. (26)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

“That clause 38, as amended, stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 38, as amended, was added to the Bill.

Clauses 39 and 40 were added to the Bill.

(s3/1750/kmr/nk)

Clause 41

Amendment made:

Page 13, *for* lines 21 to 27, *insert-*

"41. In section 141 of the principal Act, in sub-section (3), for clause (i) the following clause shall be substituted, namely:-". (27)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON (SHRI HUKUM SINGH): The question is:

“That clause 41, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 41, as amended, was added to the Bill.

Clauses 42 to 47 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.28 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.28 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 47A

Amendment made:

Page 15, *after* line 21 , *insert-*

Amendment
of section
157

'47 A. In section 157 of the principal Act,-
(i) in sub-section (1), the words and figures, "within the time specified under section 403" shall be *omitted*;
(ii) in sub-section (2), the words and figures, "before the expiry of the period specified under section 403 with additional fee", shall be *omitted*.'. (28)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That new clause 47A be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 47A was added to the Bill.

Clause 48

Amendment made:

Page 15, line 27, *after* "178", *insert*, "or a director recommended by the Board of Directors of the Company, in the case of a company not required to constitute Nomination and Remuneration Committee.". (29)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 48, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 48, as amended, was added to the Bill.

Clauses 49 to 58 were added to the Bill.

Clause 59

Amendment made:

Page 18, *for* lines 29 to 36, *substitute-*

"(4) If any loan is advanced or a guarantee or security is given or provided or utilised in contravention of the provisions of this section,-

(i) the company shall be punishable with fine which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to twenty-five lakh rupees;

(ii) every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to twenty-five lakh rupees; and

(iii) the director or the other person to whom any loan is advanced or guarantee or security is given or provided in connection with any loan taken by him or the other person, shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to twenty-five lakh rupees, or with both." (30)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 59, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 59, as amended, was added to the Bill.

Clause 60

Amendments made:

Page 18, *omit* line 38. (31)

Page 19, line 10, *after* "section", *insert*, ", except sub-section (1),".
(32)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 60, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 60, as amended, was added to the Bill.

Clauses 61 to 63 were added to the Bill.

(t3/1755/gm-sk)

Clause 64

Amendment made:

Page 19, for lines 43 and 44, *substitute*—

‘64. In Section 196 of the principal Act,-

(a) in sub-section (3), in clause (a), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that where no such special resolution is passed but votes cast in favour of the motion exceed the votes, if any, cast against the motion and the Central Government is satisfied, on an application made by the Board, that such appointment is most beneficial to the company, the appointment of the person who has attained the age of seventy years may be made.”;

(b) in sub-section (4), for the words “specified in that Schedule”, the words “specified in Part I of that Schedule” shall be *substituted*.’ (33)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That Clause 64, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 64, as amended, was added to the Bill.

Clause 65

Amendments made:

Page 20, for line 5 to 7, substitute-

“Provided also, that where the company has defaulted in payment of dues to any bank or public financial institution or non-convertible debenture holders or any other secured creditor,”. (34)

Page 20, line 18, for “of”, substitute “or”. (35)

Page 20, for lines 25 to 27, substitute-

“Provided that where the company has defaulted in payment of dues to any bank or public financial institution or non-convertible debenture holders or any other secured creditor, the”. (36)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That Clause 65, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 65, as amended, was added to the Bill.

Clause 66

Amendment made:

Page 20, for line 47 to 49, substitute-

‘(i) in sub-section (3)-

(a) in clause (a), after the words “sold by the company”, the words and figures “unless the company is an investment company as referred to in clause (a) of the *Explanation* to section 186” shall be *inserted*:

(b) *after* clause (e), the following clause shall be *inserted*, namely:-

“(f) any amount representing unrealised gains, notional gains or revaluation of assets.” (37)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That Clause 66, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 66, as amended, was added to the Bill.

Clauses 67 to 73 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.46 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved. ”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.46 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved. ”

The motion was adopted.

New Clause 73A

Amendment made:

Amendment of section 374	<p>‘73A. In section 374 of the principal Act, <i>after</i> clause (d), the following proviso shall be <i>inserted</i>, namely:-</p> <p>“Provided that upon registration as a company under this Part a limited liability partnership incorporated under the Limited Liability Partnership Act, 2008 shall be deemed to have been dissolved under that Act without any further or deed.”’.</p> <p style="text-align: right;">(38)</p>
--------------------------	--

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That new clause 73A be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 73A was added to the Bill.

Clauses 74 and 75 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.47 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved. ”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.47 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved. ”

The motion was adopted.

New Clause 75A

Amendment made:

Page 21, <i>after</i> line 41, <i>insert-</i>	
Amendment of section 391	<p>‘75A. In section 391 of the principal Act, <i>for</i> sub-section (2), the following sub-section shall be <i>substituted</i>, namely:-</p> <p>“(2) Subject to the provisions of section 376, the provisions of Chapter XX shall apply <i>mutatis mutandis</i> for closure of the place of business of a foreign company in India as if it were company incorporated in India in case such foreign company has raised monies through offer or issue of securities under this Chapter which have not been repaid or redeemed.”’.</p> <p style="text-align: right;">(39)</p>

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That new clause 75A be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New clause 75A was added to the Bill.

(u3/1800/rsg-rjs)

Clause 76

Amendments made:

(40)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

Page 22, *omit* lines 1 to 20. (41)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 76, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 76, as amended, was added to the Bill.

Clauses 77 and 78 were added to the Bill.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House has to be extended up to the passing of the Bill. Do you all agree?

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, the time of the House has to be extended till the passing of the Companies (Amendment) Bill and also for the initiation on the discussion on the IIM Bill. ... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, it is unfair. ... (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, we will initiate the discussion. We want only five minutes. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I think there is no problem since the Minister wants to speak for only five minutes. There should not be any problem in that.

... (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: Sir, he will only initiate the discussion. ...

(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: It is up to him whether he wants one minute, two minutes, or five minutes.

... *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: The Minister may now move for suspension of rule 80 (i)

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 42 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 42 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 78A

Amendment made:

Page 22, *after* line 51, *insert* –

Amendment of section 410. words,	<p>78A. In section 410 of the principal Act, <i>for</i> the words, “orders of the Tribunal”, the words, “orders of the Tribunal or of the National Financial Reporting Authority” shall be <i>substituted</i>.’. (42)</p>
--	--

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That new clause 78A be added to the Bill.”

*The motion was adopted.
New Clause 78A was added to the Bill.
Clauses 79 to 87 were added to the Bill.*

HON. CHAIRPERSON: The Minister may now move for suspension of rule 80(i)

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 43 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 43 to the Companies (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved.”

The motion was adopted.

New Clause 88

Amendment made:

Page 24, *after* line 22, *insert* –

Amendment of Section 458 “**88.** In section 458 of the principal Act, in sub-section (1), the proviso shall be *omitted*.”.

(43)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That new clause 88 be added to the Bill.”

The motion was adopted.
New clause 88 was added to the Bill.

Clause 1

Amendment made:

Page 1, line 3, *for* “2016”, *substitute* “2017”. (2)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1, for “Sixty-seventh”, substitute “Sixty-eighth”.

(1)

(Shri Arjun Ram Meghwal)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

(w3/1805/rk-rps)

HON. CHAIRPERSON: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed. ”

The motion was adopted.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, I would request you to kindly take up the next item, the IIM Bill, for consideration.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): How much time will it take?

SHRI ANANTH KUMAR: Only two minutes.

INDIAN INSTITUTES OF MANAGEMENT BILL

1807 hours

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, I beg to move:

“That the Bill to declare certain Institutes of management to be institutions of national importance with a view to empower these institutions to attain standards of global excellence in management, management research and allied areas of knowledge and to provide for certain other matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

सर, आईआईएम में आज केवल सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है और फेलोशिप मिलती है, वे डिग्री और पीएचडी नहीं दे सकते हैं। इस बिल से ये नेशनल इम्पोर्टेस की इंस्टीट्यूट होगी और अब वे पीचडी दे सकेंगे। ये हमारे 20 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं और ये विश्व स्तर पर रिकग्नाइज्ड हैं। इससे इनका रिकग्निशन और बढ़ेगा। इसमें दूसरी बात यह है।...(व्यवधान) इसकी जरूरत है। ...(व्यवधान) I would say that you will love it. Today, in IIM there is tremendous Government interference or control. We want to remove that control and this Bill also seeks to do that.

I hope that a good discussion will provide me more inputs. So, I would request that this Bill may be discussed. This in a way is a historical step as the Government will no longer be controlling these institutes. We must trust our best brains. We must trust our best institutes. This is the beginning of that era where we trust our educational institutes and give them freedom and autonomy.

I will continue my speech tomorrow.

HON. CHAIRPERSON: The discussion will continue tomorrow.

The House stands adjourned to meet on Friday, the 28th July, 2017 at 11.00 a.m.

1809 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, July 28, 2017/Shravana 6, 1939 (Saka).*